राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक

गौरवशाली भारत

दिल्ली से प्रकाशित

R.N.I. NO. DELHIN/2011/38334 वर्ष- 10, अंक- 310 पृष्ठ - 08, नई दिल्ली, रविवार ,16 मई 2021, मूल्य रु. 1.50

एक नज़र...

ममता बनर्जी के भाई का कोरोना के कारण निधन

कोलकाता, (एजेंसी)। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भाई असीम बनर्जी का कोरोना वायरस संक्रमण के कारण यहां एक अस्पताल में शनिवार सुबह निधन हो गया। उनके परिवार के सदस्यों ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कालीघाट के स्थानीय लोगों में 'कालीदा' के नाम से लोकप्रिय असीम बनर्जी ने निजी अस्पताल में सुबह करीब नौ बजकर 20 मिनट पर अंतिम सांस ली। चिकित्सा संस्थान के एक अधिकारी ने बताया कि वह करीब एक महीने पहले कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए थे और तभी से अस्पताल में भर्ती थे।

ज्वालामुखी पर बैठा है बंगाल: धनखड़

कोलकाता, (एजेंसी)। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने शनिवार को कहा कि वह उन कई परिवारों के हालात को देखकर स्तब्ध हैं जिन्होंने कथित तौर पर सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के अत्याचारों का सामना किया और उन्हें बेघर होना पड़ा। उन्होंने हिंसा प्रभावित लोगों से मुलाकात की जिन्होंने केंदेमारी, बंकिम मोड़, चिलाग्राम, नंदीग्राम बाजार और टाउन क्लब इलाकों में शरण ली है। राज्यपाल ने कहा कि तृणमूल प्रमुख कूचबिहार के सीतलकुची में केंद्रीय बलों की गोली से चार लोगों की मौत को 'जनसंहार' करार देती हैं, लेकिन नंदीग्राम की स्थिति पर चुप हैं। हमें प.बंगाल के हालात को देखकर दुख होता है। राज्य एक तरह से ज्वालामुखी पर बैठा है। शिविरों में रहने वाले लोगों ने दावा किया कि वे दो मई को चुनाव नतीजे आने के बाद नंदीग्राम स्थित अपने घरों से भागने को मजबूर हुए।

सुशील के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी

नई दिल्ली, (एजेंसी) । दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में हुए युवा पहलवान सागर राणा हत्याकांड में फरार चल रहे दो बार के ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। वहीं सूत्रों का कहना है कि कानूनी सलाह लेने के बाद सुशील जल्द ही मामले में अग्रिम जमानत की याचिका दायर कर सकता है। सुशील को अच्छी तरह पता है कि पुलिस के पास उसके खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं। इसलिए सुशील अपने बचाव में हर संभव प्रयास कर रहा है। छानबीन कर रहे एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि छत्रसाल स्टेडियम में हुए झगड़े के बाद पुलिस की टीम को उम्मीद थी कि सुशील पुलिस की पूछताछ में शामिल हो जाएगा। ऐसा होता तो शायद सुशील की मुश्किलें कम होती। लेकिन भागकर सुशील ने अपनी मुश्किलें बढ़ा ली हैं।

ठाणे में इमारत का छज्जा गिरा, चार की मौत

ठाणे, (एजेंसी)। जिले के उल्हासनगर कस्बे में एक रिहायशी इमारत का छज्जा गिरने से चार लोगों की मौत हो गई। मृतकों एक 12 साल का बच्चा भी शामिल है। एक व्यक्ति लापता है. उसकी खोज की जा रही है।ठाणे नगर निगम के स्थानीय आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ के प्रमुख संतोष कदम ने बताया कि घटना दोपहर 1 बजकर 40 मिनट पर चार मंजिला आवासीय इमारत में हुई। चौथे तल का छज्जा गिरने के बाद अन्य तलों के छज्जे भी गिरते चले गए।

प्रधानमंत्री मोदी ने, गांवों में घर-घर कोरोना टेस्टिंग का दिया निर्देश कहा- टीकाकरण अभियान को किया जाए तेज

नई दिल्ली । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को देश भर में कोविड-19 के कारण हालात और कोरोना वैक्सीनेशन की प्रगति की समीक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक में प्रधानमंत्री ने देश में जारी वैक्सीनेशन अभियान से जुड़े तमाम मसलों पर चर्चा की और टीकाकरण व कोविड टेस्टिंग की प्रक्रिया में और तेजी लाने को कहा। साथ ही केंद्र की ओर से भेजे गए वेंटिलेटर जिन राज्यों में अब तक इस्तेमाल नहीं किए गए हैं उन्हें तुरंत इंस्टॉल कराने का सख्त आदेश दिया।

प्रधानमंत्री ने गांवों में घर-घर कोरोना टेस्टिंग और सर्विलांस पर जोर दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने उच्च संक्रमण वाले क्षेत्रों में भी टेस्टिंग बढ़ाने की जरूरत बताई है। क्क्ष्र की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार, बैठक में प्रधानमंत्री ने वेंटिलेटर को लेकर कुछ राज्यों को सख्त निर्देश दिए क्योंकि वहां स्टोरेज में ऐसे वेंटिलेटर पड़े हैं जिसका इस्तेमाल अब तक नहीं किया गया है। प्रधानमंत्री ने तुरंत इन वेंटिलेटर को इंस्टॉल करने का निर्देश दिया। बैठक में प्रधानमंत्री को देश में जारी वैक्सीनेशन की प्रक्रिया के बारे में विस्तार से बताया गया है। इसके अलावा वैक्सीन की उपलब्धता को लेकर भी चर्चा हुई। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वैक्सीनेशन की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम करें।

प्रधानमंत्री ने कोरोना टेस्टिंग के लिए ऋञ्च-क्कष्टक्र व रैपिड एंटिजन टेस्ट की मदद से तेजी लाने को कहा। उन्होंने आगे कहा कि राज्यों को पारदर्शी तरीके से कोविड-19 से जुड़े आंकड़े बताने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए बिना यह सोचे की इससे उनके प्रयासों को नेगेटिव नजरिए से देखा जाएगा। उन्होंने ग्रामीण इलाकों में डोर टू डोर कोरोना टेस्टिंग पर जोर दिया। ग्रामीण इलाकों में होम आइसोलेशन व इलाज को समझाने के लिए आसान और सहज भाषा के इस्तेमाल की बात कही। इसके अलावा इन इलाकों में ऑक्सीजन सप्लाई के मामले पर प्रधानमंत्री ने कहा कि इसके वितरण प्रणाली पर काम किया जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि सभी मेडिकल डिवाइसेज के उपयोग को लेकर हेल्थवर्करों को आवश्यक ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने ्रस्॥ और आंगनवाड़ी वर्करों को सभी अनिवार्य जरूरतों को पूरा करने और सशक्त बनाने का जिक्र भी किया।

इससे पहले बुधवार को प्रधानमंत्री मोदी ने ऑक्सीजन व दवाओं के सप्लाई व उपलब्धता की समीक्षा के लिए बैठक की थी। प्रधानमंत्री ने बताया कि देशभर के सरकारी अस्पतालों में मुफ्त वैक्सीनेशन किया जा रहा है इसलिए जब भी आपकी बारी आए तो वैक्सीन ज़रूर लें।

उन्होंने कहा, 100 साल बाद आई इतनी भीषण महामारी कदम-कदम पर दुनिया की परीक्षा ले रही है। हमारे सामने एक अदृश्य दुश्मन है। उन्हें जानकारी दी गई की कोविड-19 के मैनेजमेंट में ड्रग के सप्लाई का सरकार सक्रियता से मॉनिटरिंग कर रही है। देश में अभी वैक्सीनेशन का तीसरा फेज जारी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, शुक्रवार तक वैक्सीनेशन की कुल 18,04,29,261 खुराक दी जा चुकी है। उल्लेखनीय है कि अब लगातार चार दिनों से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या संक्रमण के नए मामलों से ज्यादा रही है। इसके साथ ही कोरोना महामारी को मात दे चुके लोगों का आंकड़ा भी दो करोड़ को पार कर गया है। दो दिन की बढ़त के बाद सक्रिय मामलों में भी 30 हजार से ज्यादा की गिरावट आई है और इनकी संख्या 37 लाख के नीचे आ गई है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से शुक्रवार देर रात तक मिले आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटे में देश भर में 3,26,014 नए मामले मिले हैं, 3,52,850 मरीज ठीक हुए हैं और 3,876 और मरीजों की जान गई है। इसके साथ ही कुल संक्रमितों का आंकड़ा दो करोड़ 43 लाख 72 हजार को पार कर गया है। इनमें से दो करोड़ चार लाख 26 हजार से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं और 3,66,229 मरीजों की अब तक जान भी जा चुकी है। सक्रिय मामले 36,69,537 हो गए हैं।

टीकाकरण को लेकर सरकार पर बरसे राहुल गांधी, कहा- अनर्थकारी नीति तीसरी लहर सुनिश्चित करेगी

नई दिल्ली । कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शनिवार को राष्ट्रीय टीका रणनीति का आह्वान किया और दावा किया कि सरकार की अनर्थकारी टीकाकरण नीति देश में महामारी की तीसरी विनाशकारी लहर सुनिश्चित करेगी। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि संदिग्ध कोरोना मरीजों के शव बहते पाए जाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मां गंगा को रुलाया है।

राहुल गांधी ने ट्विटर पर कहा, भारत सरकार की अनर्थकारी टीका रणनीति विनाशकारी तीसरी लहर सुनिश्चित करेगी...भारत को उचित टीका रणनीति की आवश्यकता है। उन्होंने मीडिया में आई उन खबरों को टैग किया जिनमें दावा किया गया है कि गंगा के किनारे 1,140 किलोमीटर क्षेत्र में 2,000 से अधिक शव पाए गए हैं। कांग्रेस नेता ने कहा, जो कहता था गंगा ने बुलाया है, उसने मां गंगा को रुलाया है।

टीका रणनीति और महामारी से निपटने के मुद्दे पर गांधी और उनकी पार्टी द्वारा प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार पर प्राय- हमला किया जाता रहा है।

गांधी ने एक अन्य ट्वीट में लोगों से कई राज्यों में चक्रवात तौकते की चेतावनी के मद्देनजर सुरक्षित रहने की अपील की। उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से जरूरतमंदों की मदद करने की अपील भी की।

उन्होंने कहा, केरल, महाराष्ट्र, गोवा, तमिलनाडु, गुजरात और कर्नाटक में 15 मई को चक्रवात की चेतावनी जारी की गई है। चक्रवात तौकते की वजह से कई क्षेत्रों में पहले ही भारी बारिश हो रही है। मैं कांग्रेस कार्यकर्ताओं से जरूरतमंदों को हरसंभव मदद उपलब्ध कराने की अपील करता हूं। कृपया सुरक्षित रहें।

चक्रवाती तूफान तौकते को लेकर इन राज्यों में हाई अलर्ट, 175 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से चलेगी हवा

नई दिल्ली, एजेंसी। मौसम विभाग ने तौकते चक्रवाती तूफान के चलते हाई अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने कहा है कि चक्रवाती तूफान तौकते के अगले तीन घंटे के भीतर गंभीर चक्रवाती तूफान में तब्दील होने की आशंका है। यह मंगलवार तक गुजरात तट से टकरा सकता है। गुजरात और दीव के समुद्र तट चक्रवात को लेकर निगरानी में हैं। भारत में यह इस साल का पहला चक्रवाती तूफान है। चक्रवाती तूफान को लेकर गुजरात और दीव तटों के लिए पीला अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक इसके अगले तीन घंटों के दौरान एक गंभीर चक्रवाती तूफान में और उसके बाद के 12 घंटों के दौरान बहुत गंभीर चक्रवाती तूफान में बदलने की आशंका है। इसके उत्तर-उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ने और 18 मई की सुबह गुजरात तट पर पहुंचने के आसार हैं। तूफान के 18 मई को दोपहर या शाम तक पोरबंदर और नलिया के बीच गुजरात तट को पार करने की प्रबल संभावना है। मौसम विभाग ने पश्चिमी तटीय राय को सतर्क किया है। लिहाज़ा केंद्र सरकार ने हालात से निपटने के लिए एनडीआरएफ को भी तैनात कर दिया है।

भारतीय वायुसेना के दो C-130 एयरक्राफ्ट से एनडीआरएफ की तीन टीम गुजरात के जामनगर पहुंची हैं। कुल 126 एनडीआरएफ कर्मियों को ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर से एयरलिफ्ट करके लाया गया। यह टीम राहत और बचाव कार्यों के लिए तैनात की जा रही है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने ट्वीट कर जानकारी दी, लक्षद्वीप और अरब सागर के आसपास के इलाकों में गहरा मौसमी डिप्रेशन चक्रवाती तूफान में बदल गया है।

अरब सागर में ये तूफान पिछले 6 घंटे के दौरान 9 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। मौसम विभाग का अनुमान है कि तट से टकराते समय चक्रवात की रफ्तार 140 से 150 किलोमीटर प्रति घंटे तक रह सकती है। गुजरात के तट से ये तूफान इस वक्त 160 किलोमीटर दूर है, जबकि गोवा के पणजी से इसकी दूरी 350 किलोमीटर है।

मौसम विभाग के मुताबिक इस तूफान के शनिवार रात तक अत्यंत भीषण चक्रवाती तूफान में तब्दील होने की संभावना है। 18 मई को दोपहर या फिर शाम को ये तूफान गुजरात के पोरबंदर और नालिया तट को पार करेगा।

आईएमडी ने कहा कि 16-19 मई के बीच पूरी संभावना है कि ये 150-160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली हवाओं के साथ एक 'अत्यंत भीषण चक्रवाती तूफान' में तब्दील होगा। हवाओं की रफ्तार बीच-बीच में 175 किलोमीटर प्रति घंटा भी हो सकती है।

देश में कम हो रहे कोरोना के सक्रिय मामले, 17 राज्यों में हैं 50 हजार से भी कम केस- स्वास्थ्य मंत्रालय

नई दिल्ली। देश के अधिकतर राज्यों में कोरोना के सक्रिय मामलों में गिरावट देखी गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश के 11 राज्यों में 1 लाख से अधिक सक्रिय मामले हैं। 8 राज्यों में 50,000 से 1 लाख के बीच कोरोना के सक्रिय मामले हैं। देश के 17 राज्यों में 50,000 से कम कोरोना के सक्रिय मामले हैं। महाराष्ट्र, यूपी, गुजरात और छत्तीसगढ़ जहां अधिक संख्या में कोरोना के नए मामले सामने आ रहे हैं और वहां भी अब सक्रिय मामलों में गिरावट दर्ज की जा रही है। इसके साथ ही मंत्रालय ने बताया कि चिंता का कारण तमिलनाडु है जहां पिछले एक सप्ताह में सक्रिय मामलों की संख्या में वृद्धि दर्ज की गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल के अनुसार देश में सक्रिय मामलों में कमी देखी जा रही है। 3 मई को रिकवरी रेट 81.3 फीसद थी जिसके बाद रिकवरी में सुधार हुआ है।अब रिकवरी रेट 83.83 फीसद है। 75 फीसद मामले 10 राज्यों से आ रहे हैं और कुल सक्रिय मामलों का 80 फीसद सिर्फ 12 राज्यों में है। स्वास्थ्य सचिव ने बताया कि देश में 24 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जहां 15 फीसद से ज्यादा पॉजिटिविटी रेट है। 5 से 15 फीसद पॉजिटिविटी रेट 10 राज्यों में है। 5 फीसद से कम पॉजिटिविटी रेट 3 राज्यों में है। पिछले 1 सप्ताह में 18 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश पॉजिटिविटी रेट कम हुई है। देशभर में पॉजिटिविटी रेट जो 21.9 फीसद थी, वो अब 19.8 फीसद रह गई है।

ब्लैक फंगस से लोगों की हो रही मौत -इसके साथ ही एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने बताया कि जैसे-जैसे कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, यह सबसे महत्वपूर्ण है कि हम अस्पतालों में संक्रमण नियंत्रण प्रथाओं के प्रोटोकॉल का पालन करें। यह देखा गया है कि ज्यादातर मरीज दूसरे संक्रमण यानी ब्लैक फंगस से लोगों की मौत हो रही है।

गुलेरिया के अनुसार ब्लैक फंगस के पीछे स्टेरॉयड का दुरुपयोग एक प्रमुख कारण है। मधुमेह, कोरोना पॉजिटिव और स्टेरॉयड लेने वाले रोगियों में फंगल संक्रमण की संभावना बढ़ जाती है। इसे रोकने के लिए हमें स्टेरॉयड का दुरुपयोग रोकना चाहिए।

नई दिल्ली में इजराइल में हमास के रॉकेट हमले का शिकार बनी केरल की नर्स सौम्या संतोष को विदेश राज्यमंत्री मुरलीधरन ने श्रद्धांजलि अर्पित की। शनिवार को ही शव केरल में उनके घर पहुंचा, जहां उनका अंतिम संस्कार किया गया।

आंदोलन के छह महीने होने पर 26 मई को काला दिवस मनाएंगे किसान

संयुक्त किसान मोर्चा का एलान

नई दिल्ली, (एजेंसी)। कृषि कानूनों के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे किसान पीछे हटने को तैयार नहीं हैं।

खास बात यह है कि किसानों की केंद्र के साथ कई दौर की वार्ता हो चुकी है, परंतु अब तक कोई सार्थक हल नहीं निकल पाया है। कृषि कानूनों का विरोध कर रहे 40 किसान संघों के प्रधान संगठन संयुक्त किसान मोर्चा ने शनिवार को कहा कि दिल्ली की सीमाओं पर चल रहे प्रदर्शन के छह माह होने पर 26 मई को काला दिवस के रूप में मनाया जाएगा। किसान नेता बलबीर सिंह राजेवाल ने केंद्र के कृषि कानूनों के विरोध में लोगों से 26 मई को अपने घरों, वाहनों, दुकानों पर काला झंडा लगाने की अपील की है। 26 मई को इस प्रदर्शन के छह महीने हो जाएंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सरकार बनाने के सात साल पूरे होने के अवसर पर यह हो रहा है। हम इसे काला दिवस के तौर पर मनाएंगे।

चार राज्यों से बस सेवाओं की रोक बरकरार

महाराष्ट्र, छग, यूपी व राजस्थान की बसें 23 तक नहीं चलेंगी

भोपाल, (एजेंसी)। कोरोना की दूसरी लहर के प्रकोप के कारण मध्यप्रदेश से महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तरप्रदेश और राजस्थान के बीच बस सेवाएं स्थगित रहने की अवधि बढ़ाकर 23 मई कर दी गई है।

राज्य के अपर परिवहन आयुक्त (प्रवर्तन) एवं राज्य परिवहन प्राधिकार के सचिव अरविंद सक्सेना ने इस संबंध में शनिवार को आदेश जारी कर दिए हैं। अभी तक यह अवधि 15 मई थी, जिसे बढ़ाकर 23 मई किया गया है। इस दौरान इन राज्यों से मध्यप्रदेश में बस सेवाओं के संचालन पर पहले की तरह पूरी तरह रोक रहेगी। मध्यप्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर ने अप्रैल माह में काफी नुकसान किया है। हालांकि अब मई में हालात थोड़े नियंत्रण में होते हुए नजर आ रहे हैं।

यूके एक्सपर्ट का दावा, बी1.617.2 वैरिएंट पर वैक्सीन भी प्रभावी नहीं

नया वैरिएंट भारत में पहली बार मिला

लंदन, (एजेंसी)। ब्रिटेन (यूके) में कोरोना से बचाव के लिए लगाए जा रहे टीके (वैक्सीन) वायरस के बी1.617.2 वैरिएंट को फैलने से रोकने में कम प्रभावी है। ब्रिटेन के एक प्रमुख वैज्ञानिक जो यूके के टीकाकरण कार्यक्रम का हिस्सा हैं, ने शनिवार को यह दावा किया। कोरोना का बी1.617.2 वैरिएंट भारत में पहली बार पाया गया था और कुछ लोग इसे भारतीय वैरिएंट भी कह रहे हैं। न्यूज एजेंसी के मुताबिक, कोरोना के बी1.617.2 वैरिएंट के मामलों की संख्या यूके में एक हफ्ते के भीतर दोगुनी हो गई है। ऐसे में देश के जिन हिस्सों में वायरस का यह वैरिएंट तेजी से फैलने लगा है, वहां जांच और टीकाकरण में तेजी लाई जा रही है। बी1.617.2 वैरिएंट सबसे पहले भारत के महाराष्ट्र में मिला था।

अनलॉक करने, आंकड़ों का इंतजार कर रही ब्रिटिश सरकार

ब्रिटेन में फैल रहे कोरोना के वैरिएंट को लेकर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर एंथनी हार्डेन ने कहा कि इससे देश को अनलॉक करने के प्लान में रुकावटें पैदा हो सकती हैं क्योंकि यह अभी तक साफ नहीं हो पाया कि ये वैरिएंट कितनी तेजी से फैलेगा। साथ ही उन्होंने दावा किया कि वैक्सीन नए वैरिएंट के खिलाफ कम प्रभावी हो सकते हैं।

इससे पहले ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन ने कहा था कि सरकार उन आंकड़ों का इंतजार कर रही है जो बताएंगे कि क्या नया वैरिएंट दूसरे वैरिएंट के मुकाबले ज्यादा फैलने वाला है। वहीं ब्रिटिश स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि बी1.617.2 वैरिएंट उत्तर पश्चिमी इंग्लैंड और लंदन में फैलने लगा है।

इस बीच ब्रिटेन ने अब कोविशील्ड की दोनों डोज देने के बीच के समय को कम कर दिया है। अब दोनों डोज के बीच का गैप आठ हफ्ते का किया गया है। हालांकि, यह नियम 50 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए ही लागू किया गया है। पहले इनके लिए दोनों डोज के बीच के समय 12 हफ्ते का था। प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कहा है कि यह नया वैरिएंट हमारी प्रगति के लिए बाधा पैदा कर सकता है. हमें लोगों को सुरक्षित रखने के लिए जो कछ भी करना होगा. हम करेंगे।

आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त चार लोग गिरफ्तार, पूछताछ जारी

आतंकी नेटवर्क का भंडाफोड़

श्रीनगर, (एजेंसी)। कोरोना काल में भी सुरक्षाबलों ने कश्मीर घाटी में आतंकवादी गतिविधियों के खिलाफ अपना शिकंजा कसा हुआ है। सुरक्षाबलों ने दक्षिण कश्मीर के जिला पुलवामा से चार ऐसे संदिग्ध व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने में उनकी मदद की थी। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इन चारों लोगों के बारे में सुरक्षाबलों को काफी दिन पहले से जानकारी मिल गई थी परंतु घरों से गायब होने की वजह से यह उनकी पकड से दर थे। पुलिस को सूचना मिली की ये चारों लोग पुलवामा में बारपोरा गांव में छिपे हुए हैं। पुलिस सेना और बीएसएफ की टीमों के साथ गांव बारपोरा पहुंचे और इलाके की घेराबंदी शुरू कर दी। अचानक से मारे गए छापे के बाद इन चारों लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने इनकी पहचान बिलाल अहमद गनई, फिरोज अहमद, यावर अहमद डार व तलनगम के वकार अहमद के रुप में हुई है। तलाशी के दौरान उनके पास से आतंकवादी संगठनों से संबंधित कुछ आपत्तिजनक दस्तावेज भी बरामद हुए हैं।

संकट

चक्रवाती तूफान 'तौकते' को लेकर कई राज्यों में हाई अलर्ट

155 किमी की रफ्तार से चलेगी हवा

अहमदाबाद, (एजेंसी)। अरब सागर में उठा चक्रवाती तूफान तौकते अब तीव्र (सिवीयर) तूफान में बदल चुका है और रविवार तड़के तक अति तीव्र श्रेणी के तूफ़ान में परिवर्तित हो जाएगा तथा इसके 18 मई को गुजरात के नलिया और पोरबंदर के बीच से तट से टकराने का अनुमान व्यक्त किया गया है।

मौसम विभाग के अनुसार इसके अति तीव्र तूफान में बदलने और गुजरात तट से टकराने के दौरान हवाओं की रफ्तार 155 से लेकर 175 किमी प्रति घंटा तक हो सकती है। इसके साथ तटीय गुजरात में भारी से अति भारी वर्षा भी हो सकती है। फिलहाल इसके आस पास हवाओं की गति 110 से 135 किमी प्रति घंटा है, जो रविवार तक 155 किमी प्रति घंटा तक पहुंच जाएगी। वहीं केरल में भारी बारिश का जोर जारी है।

विमान सेवाएं हुईं प्रभावित, कंपनियों ने ग्राहकों के लिए जारी की ट्रैवल एडवाइजरी

नई दिल्ली, (एजेंसी)। अरब सागर में उठ रहे चक्रवात तौकते ने देश की चिंता बढ़ा दी है। मौसम विभाग ने पश्चिमी तटीय राज्य को सतर्क किया है। इसके मद्देनजर विस्तारा एयरलाइंस और इंडिगो ने अपने ग्राहकों के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है। कंपनियों की सेवाएं कई शहरों में बाधित हो गई हैं।

चक्रवात से निपटने मोदी ने ली बैठक

नईदिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चक्रवात से निपटने की राज्यों, केंद्रीय मंत्रालयों और एजेंसियों की तैयारियों का जायजा लेने के लिए एक महत्वपूर्ण बैठक की। आईएमडी ने कहा कि 17 मई को मुंबई सहित उत्तरी कोंकण में कुछ स्थानों पर तेज हवाएं चलेंगी और भारी बारिश होगी। वरिष्ठ निदेशक (मौसम) आईएमडी, मुंबई शुभानी भूटे ने कहा कि महाराष्ट्र की राजधानी में रविवार दोपहर से बारिश की उम्मीद है।

सिंगापुर ने कोविड-19 के मामले बढ़ने पर कड़ी हुई पाबंदियां

सिंगापुर, (एजेंसी)। सिंगापुर ने कोविड-19 के मामले बढ़ने के बाद लोगों के एकत्रित होने और जन गतिविधियों पर पाबंदियां कड़ी कर दी। इस दौरान शिक्षा मंत्री लॉरेंस वोंग ने कहा कि समूह में एकत्रित होने वाले लोगों की संख्या पांच लोगों से घटाकर दो लोगों तक की जाएगी। यह कदम उन रिपोर्टों के बाद उठाया गया है कि कोविड-19 के ज्यादातर मामले चांगी हवाईअड्डे, स्कूल और अस्पतालों से जुड़े हैं।

वोंग ने कहा, अगर आप किराना का सामान खरीदने, व्यायाम करने या किसी भी चीज के लिए बाहर जाते हैं,तब अधिकतम दो लोगों को इकट्ठा होने की अनुमति होगी। उन्होंने कहा, हम हर किसी को जितना संभव हो , घर में रहने के लिए प्रेरित करते हैं, केवल आवश्यक होने पर ही घर से बाहर जाएं। उन्होंने कहा, अगर स्थिति में सुधार नहीं है,तब हम निश्चित तौर पर और सख्त कदम उठाने की संभावना से इनकार नहीं करते है।

स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा, दो से ज्यादा लोग एकत्रित नहीं हो सकते चाहे वे घर में अपने दोस्तों या परिवार के सदस्यों से मिल रहे हो या सार्वजनिक स्थान पर। इसमें कहा गया है कि इस अवधि के दौरान किसी बंद जगह में होने वाले व्यायाम और खेल गतिविधियों को भी अनुमति नहीं होगी। बहरहाल मेडिकल और दंत चिकित्सा संबंधी सेवाएं जारी रह सकती हैं। सिंगापुर के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बृहस्पतिवार को सामुदायिक संक्रमण के 24 मामलों की जानकारी दी जो सितंबर के बाद से सबसे अधिक संख्या है। देश में अब तक कोरोना के 61,000 से अधिक मामले आ चुके हैं और 31 लोगों की मौत हो चुकी है।

गाजा सीमा पर 9,000 सैनिकों को भेजेगा इजरायल

यरुशलम, (एजेंसी)। इजराइल ने कहा कि वह गाजा सीमा पर बड़ी संख्या में सैनिकों को भेजने की योजना बना रहा है और उसने हमास शासित क्षेत्र में संभावित जमीनी आक्रमण के लिए 9,000 सैनिकों को तैयार रहने को कहा है। यह दिखाता है कि दोनों शत्रु युद्ध की ओर बढ़ रहे हैं। मिस्र के मध्यस्थ संघर्ष विराम प्रयासों के लिए इजराइल पहुंचे लेकिन इसमें प्रगति के कोई संकेत नहीं दिखे हैं। इजराइल में चौथी रात भी साम्प्रदायिक हिंसा होने के बाद लड़ाई और तेज हो गई। यहूदी और अरब समूहों में लॉड शहर में झड़पें हुई। पुलिस की मौजूदगी बढ़ाने के आदेश देने के बावजूद झड़पें हुईं। इस लड़ाई ने इजराइल में दशकों बाद भयावह यहूदी-अरब हिंसा को जन्म दिया है। लेबनान से देर रात रॉकेट दागे गए जिससे इजराइल की उत्तरी सीमा पर एक तीसरे पक्ष के शामिल होने का खतरा पैदा हो गया है। हमास के एक वरिष्ठ निर्वासित नेता ने लंदन स्थित एक चैनल को शुक्रवार को बताया कि उनके समूह ने पूर्ण संघर्ष विराम के लिए और बातचीत करने देने के लिए तीन घंटे के विराम के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है।

उन्होंने कहा कि मिस्र, कतर और संयुक्त राष्ट्र संघर्ष विराम प्रयासों की अगुवाई कर रहे हैं। इजराइली सेना ने शुक्रवार को कहा कि गाजा में हवाई और जमीनी हमले हो रहे हैं। गाजा सिटी के बाहरी इलाकों में विस्फोटों से आसमान में धुएं का गुबार बन गया। हमले इतने भयावह थे कि कई किलोमीटर दूर शहर में लोगों की चीखें सुनी गई। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक बयान में कहा कि मैंने कहा था कि हमास से बहुत भारी कीमत वसूल करेंगे। हम यही कर रहे हैं और भारी बल के साथ यही करते रहेंगे। यह लड़ाई सोमवार को शुरू हुई जब यरुशलम को बचाने का दावा करने वाले हमास नेलंबी दूरी के रॉकेट दागने शुरू किए। इजराइल ने जवाबी कार्रवाई करते हुए कई हवाई हमले किए। तब से इजराइल ने गाजा में सैकड़ों ठिकानों को निशाना बनाया है।

तेल अबीब में इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतनयाहू कुछ इलाकों में हुई हिंसा के बाद इजरायली बोर्डर पुलिस के अधिकारियों से मिले।

काठमांडू की एक ऑक्सीजन फैक्ट्री के बाहर खाली सिलेंडरों के साथ लाइन में लगे हुए लोग।

चीनी वैक्सीन लगाने वाले पाकिस्तानी को वीजा नहीं देगा सऊदी

इस्लामाबाद, (एजेंसी)। सऊदी अरब ने एक ताजा फरमान जारी कर इमरान सरकार की मुसीबतें बढ़ा दी हैं। सऊदी अरब ने कहा है कि वो उन पाकिस्तानियों को किसी भी तरह का वीजा जारी नहीं करेगा, जिन्होंने चीन में बनी वैक्सीन लगवाई है। इसका कारण सऊदी रेगुलेटर ने चीन की साइनोवैक और साइनोफार्म के टीके को अनुमति नहीं दी है। हालांकि चीन ने वैक्सीन डिप्लोमैसी के तहत यह वैक्सीन सऊदी भेजी थीं, लेकिन प्रशासन ने इसका इस्तेमाल नहीं किया। रिपोर्ट के मुताबिक, सऊदी प्रशासन ने अब इस मामले में कुछ राहत दी है। जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाई है, उन्हें निगेटिव आरटी-पीसीआर रिपोर्ट तो दिखानी ही होगी। इसके साथ ही 14 दिन का क्वारंटाइन भी पूरा करना होगा और वह भी अपने खर्च पर। सऊदी अरब सरकार ने अभी तक चार टीके को ही अनुमति दी है। इसमें फाइजर, एस्ट्राजेनेका, मॉडर्ना और जॉनसन एंड जॉनसन। इनमें से जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन सिंगल शॉट है।

यानी इसका एक ही डोज लगता है। बाकी तीनों के डबल डोज लगाए जाते हैं। चीन ने भले ही अपनी दोनों वैक्सीन की डोज सऊदी अरब भेजे हों, लेकिन इनका इस्तेमाल नहीं किया गया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब की यात्रा करने की मंजूरी सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलेगी, जिन्होंने वैक्सीनेशन पूरा कर लिया हो। इसमें भी एक शर्त यह जोड़ी गई है कि चीन में बनी वैक्सीन लगवाने वालों को यात्रा की मंजूरी नहीं मिलेगी। पाकिस्तानियों की दिक्कत यह है कि यहां चीन की तरफ से दान मिलीं वैक्सीन ही इस्तेमाल की जा रही हैं।

रूस से स्पुतनिक वैक्सीन का ऑर्डर दिया गया, लेकिन अब तक इनका एक भी डोज पाकिस्तान नहीं पहुंचा। बता दें कि नए फरमान से सऊदी अरब जाने की तैयारी कर रहे पाकिस्तानी नागरिकों की उम्मीदों पर पानी फिर गया है। सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान (एमबीएस) के प्रशासन ने पाकिस्तान को झटका दिया है। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान रविवार रात को ही सऊदी अरब के सरकारी दौरे से लौटे हैं।

वैक्सीनेशन कराने वालों के लिए मास्क पहनना जरूरी नहीं

वाशिंगटन, (एजेंसी)। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पूरी तरह से टीकाकरण करवा चुके लोगों के लिए मास्क लगाने की आवश्यकता को हटाने के सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के नवीनतम दिशानिदेर्शों की प्रशंसा की है। वहीं, टीकाकरण न करवाने वालों को चेतावनी दी कि जब तक वो अपना टीकाकरण पूरा नहीं करवा लेते हैं तब तक खुद को सुरक्षित रखें और मास्क पहनें। व्हाइट हाउस में बाइडेन ने कहा, सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, सीडीसी ने घोषणा की है कि वे अब यह अनुशंसा नहीं कर रहे हैं कि पूरी तरह से टीकाकरण वाले लोगों को मास्क पहनने की आवश्यकता है। चाहें आप घर पर हों या बाहर। मुझे लगता है कि यह एक बड़ा मील का पत्थर है। इतने सारे अमेरिकियों को इतनी जल्दी टीका लगाने में हमें जो असाधारण सफलता मिली है, उससे यह संभव हुआ है।

बाइडेन ने कहा कि इन 114 दिनों में हमारे टीकाकरण कार्यक्रम ने दुनिया का नेतृत्व किया है और यह बहुत सारे लोगों की अविश्वसनीय मेहनत के कारण हुआ है। वैज्ञानिकों और शोधकताओं, दवा कंपनियों, नेशनल गार्ड, यूएस मिलिट्री, फेमा, डॉक्टरों, नर्सों, फार्मासिस्टों की मेहनत इसमें है। इसके साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति ने उन लोगों से फिलहाल मास्क पहनने की अपील की है जिनका वैक्सीनेशन नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों का टीकाकरण नहीं हुआ है, उन्हें अभी भी मास्क पहनने की जरूरत है। उन्होंने आग्रह किया कि अपनी सुरक्षा तब तक रखें जब तक आपका वैक्सीनेशन नहीं हो जाता है।

कोरोना के कारण यूएई से केरल लौटे श्रमिक, केरल की आय को बढ़ा झटका

दुबई, (एजेंसी)। केरल को खाड़ी देशों से प्रवासियों की ओर से आने वाले पैसे में काफी गिरावट दर्ज की गई है। खाड़ी देशों में कोविड के कारण हुई छंटनी से लगभग 10.02 लाख श्रमिक केरल लौटे हैं। इसकी जानकारी विश्व बैंक ने साझा की है। बैंक के प्रवासन और विकास संक्षिप्त से पता चला है कि कुल मिलाकर, हालांकि, 2020 में विदेशों में भारतीय कामगारों की ओर से भेजा जाने वाला पैसा करीब 8.3 अरब डॉलर था, जो पिछले वर्ष की तुलना से केवल 0.2 प्रतिशत कम है।

इसके अनुसार संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) से भारत के प्रेषण में 17 प्रतिशत की भारी गिरावट दर्ज की गई, लेकिन यह अमेरिका और अन्य मेजबान देशों से लचीले प्रवाह से ऑफसेट था। विस्तार से बात करने पर भारत कुल मूल्य में प्रेषण का दुनिया में 2008 से शीर्ष प्राप्तकर्ता बना हुआ है। हालांकि भारत के लिए प्रेषण कहीं नहीं है जब तक यह सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के अपने हिस्से में आता है। टोंगा और लेबनान जैसे छोटे देशों के लिए प्रेषण सकल घरेलू उत्पाद एक अधिक महत्वपूर्ण हिस्सा होता हैं। संक्षिप्त के अनुसार, पिछले साल खाड़ी सहयोग परिषद (जीसीसी) के सात सदस्य देशों से विदेशी कामगारों के पलायन ने केरल को बुरी तरह प्रभावित किया। बैंक ने कहा कि केरल में, अनुमानित 10.02 लाख प्रवासी श्रमिक, 40 लाख से अधिक हैं, जिन्होंने गल्फ को ऑपरेशन काउंसिल से जुड़े देशों में काम किया और राज्य की आय का 30 प्रतिशत योगदान दिया, 2020 में कोरोना ने उन्हें बेरोजगार बना दिया। इसमें कम- कुशल श्रमिक सबसे ज्यादा प्रभावित हुए थे।

रिपोर्ट में कहा गया है कि परिवारों को मिलने वाले मासिक वेतन में औसतन 267 डॉलर की गिरावट आई है। संक्षेप में अमेरिका को प्रेषण के सबसे बड़े स्रोत के रूप में सूचीबद्ध किया गया है, इसके बाद संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब और रूस का स्थान आता है। बांग्लादेश, पाकिस्तान, भूटान और श्रीलंका में बढ़ते प्रवाह के कारण दक्षिण एशियाई क्षेत्र के लिए प्रेषण में लगभग 5 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई। भारत की तरह, नेपाल ने भी प्रेषण में एक छोटी सी गिरावट का अनुभव किया। अगले वर्ष के लिए, बैंक ने अनुमान लगाया कि उच्च आय वाली अर्थव्यवस्थाओं में विकास की एक मॉडरेशन और गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल देशों में प्रवासन में एक और अपेक्षित गिरावट के कारण क्षेत्र में प्रेषण थोड़ा कम होकर 3.5 प्रतिशत हो जाएगा।

बीमारी फैलाने वाले मच्छरों की पीढ़ी हो जाएगी नष्ट

फ्लोरिडा कीज, (एजेंसी)। अगली पीढ़ी ऐसे मच्छरों की आएगी जो किसी को बीमार नहीं कर पाएंगे। इसके लिए अमेरिकी जेनेटिकली मॉडिफाइड मच्छर छोड़ने की तैयारी कर रहा है। फ्लोरिडा में करीब 75 करोड़ जेनेटिकली मॉडिफाइड मच्छरों को छोड़ने की तैयारी हो चुकी है। ये मच्छर बाहर जाकर मच्छरों के साथ संबंध बनाएंगे। ये मच्छर सामान्य मच्छरों के बीच जाकर उनकी पीढ़ी को नष्ट कर देंगे। या फिर इनकी वजह से ऐसी नस्लें आएंगी जिनके काटने से इंसान किसी बीमारी का शिकार नहीं होगा। जो कंपनी ये काम कर रही है उसे बिल गेट्स ने फंडिंग की है।तो अमेरिका का प्लान ये है कि वह फ्लोरिडा में अगले एक साल में चरणबद्ध तरीके से 75 करोड़ जेनेटिकली मॉडिफाइड मच्छर छोड़ने की तैयारी है।

जेनेटिकली मॉडिफाइड मच्छरों को छोड़ने के इस प्रोजेक्ट को पिछले साल अगस्त में अमेरिकी सरकार से अनुमति मिल चुकी थी। जेनेटिकली मॉडिफाइड मच्छर ऐसे हैं कि इनके ऊपर किसी भी बीमारी का बैक्टीरिया, वायरस या पैथोजेन असर नहीं करता। इस लिए जब ये सामान्य मच्छरों के साथ संबंध बनाएंगे तो आने वाली मच्छरों की नस्लें भी इनके जीन लेकर पैदा होंगी। बस वो भी बीमारियां फैलाने में नाकाम हो जाएंगे, क्योंकि उनके शरीर में वो जींस होंगे जो बैक्टीरिया, वायरस को दूर रखेंगे। जेनेटिकली मॉडिफाइड मच्छरों को छोड़ने से भविष्य में कीटनाशकों का खर्च बचेगा। ये मच्छर खासतौर से एडीस एजिप्टी मच्छरों की नस्ल को खत्म करेंगे। एडीस एजिप्टी मच्छरों की वजह से ही इंसानों में डेंगू, जीका वायरस और यलो फीवर फैलता है। फिलहाल ये पायलट प्रोजेक्ट फ्लोरिडा कीज में शुरू किया जाएगा। यहां पर इस साल अब तक 47 लोग डेंगू की वजह से बीमार पड़ चुके हैं। इसे रोकने के लिए यह प्रोजेक्ट कितना कारगर होगा ये तो समय बताएगा, लेकिन इस काम के लिए अमेरिकी सरकार ने ब्रिटेन में स्थित अमेरिकी कंपनी से समझौता किया है।

इस कंपनी का नाम है ऑक्सीटेक। इसे इस काम के लिए अमरेकी पर्यावरण एजेंसी से भी हरी झंडी मिल चुकी है। ऑक्सीटेक जेनेटिकली मॉडिफाइड मच्छरों को पैदा करती है। यह ऐसे नर एडीस एजिप्टी मच्छर पैदा करेगी जो किसी तरह की बीमारी फैला नहीं पाएंगे। इन मच्छरों को ओएक्स5034 नाम दिया गया है।ये जेनेटिकली मॉडिफाइड नर एडीस एजिप्टी मच्छर जब छोड़े जाएंगे तो ये मादा एडीस मच्छरों से संबंध बनाएंगे। ऐसे में इनके शरीर से एक खास तरह का प्रोटीन मादा एडीस मच्छरों में जाएगा। जिससे आगे पैदा होने वाली मच्छरों की नस्लें बीमारी पैदा नहीं कर पाएंगी।मादा एडीस मच्छर जब अपने अंडों को बड़ा कर रही होती हैं, तब वे खून पीना शुरू करती हैं। लेकिन नर मच्छर फूलों का पराग खाता है।

नर मच्छर किसी तरह की बीमारी भी लेकर नहीं घूमता। ये काम मादा मच्छर का होता है। लेकिन जेनेटिकली मॉडिफाइड मच्छरों से संबंध बनाने के बाद मादा एडीस जो अंडे देगी उसमें से जेनेटिकली मॉडिफाइड मच्छर ही पैदा होंगे। इससे पहले ऐसा एक्सपेरीमेंट साल 2016 में ब्राजील में किया गया था लेकिन बेहद छोटे पैमाने पर। हालांकि, उसके नतीजे बेहद सकारात्मक थे। ब्राजील में मच्छरों को छोड़े जाने के बाद मच्छर जनित बीमारियों में भारी कमी दर्ज की गई थी।अब इस प्रोजेक्ट को लेकर भी पर्यावरणविदों का कहना है कि इससे धरती का इको सिस्टम बदल जाएगा। ये आगे चलकर खतरनाक भी साबित हो सकता है। कहीं ऐसा न हो कि जेनेटिकली मॉडिफाइड मच्छर भी कोई नई बीमारी लेकर घूमने लगे, जो ज्यादा जानलेवा हो।

भारत में कोरोना वैक्सीन के दूसरे डोज की समयावधि बढ़ाना सही फैसला : फाउची

वॉशिंगटन। अमेरिका के चर्चित संक्रामक रोग विशेषज्ञ डॉक्टर एंथनी फाउची ने भारत में कोविशील्ड कोरोना वैक्सीन के दूसरे डोज की समयसीमा को बढ़ाने का समर्थन किया है। डॉक्टर फाउची ने कहा कि अगर आपके पास पर्याप्त वैक्सीन नहीं है तो पहले और दूसरे डोज के बीच समय सीमा बढ़ाना एक विवेकपूर्ण फैसला है। इससे ज्यादा लोगों को कोरोना वैक्सीन की कम से कम एक डोज तो लग जाएगी। डॉक्टर फाउची ने कहा कि इस बात की संभावना न के बराबर है कि कोरोना वायरस वैक्सीन के दूसरे डोज में देरी से इसके प्रभाव पर बुरा असर पड़ेगा। इससे पहले भारत में ऑक्सफर्ड की कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड की दो खुराकों के बीच का गैप 6-8 हफ्ते से बढ़ाकर 12-16 हफ्ते कर दिया गया। राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकर समूह का कहना है कि ब्रिटेन में यह अंतराल 12 हफ्ते है जिसे जबिल्युएचओ ने भी सही ठहराया है। एनटीएजीआई का कहना है कि ब्रिटेन के अनुभव से सीख ली गई है। दरअसल, ब्रिटेन में यह गैप 12 हफ्ते ही है और यूरोपियन यूनियन ने भी इसे बढ़ाने की सलाह नहीं दी है। कुछ स्टडीज में यह कहा गया है कि दोनों खुराकों के बीच ज्यादा अंतराल होने पर फायदा ज्यादा होता है। इस वैक्सीन पर अंतरराष्ट्रीय टीमों की रिसर्च के डेटा में पता चला कि दो खुराकों के बीच में 12 हफ्ते का अंतर होने से ज्यादा असर होता है।

न्यूयार्क में मैट्रोपोलिटन ओपेरा हाउस के सामने विरोध प्रदर्शन करते हुए लोग।

गूगल कर रहा था मनमानी, इटली ने लगाया 904 करोड़ रुपए का जुर्माना

मैड्रिड, (एजेंसी)। टेक सेक्टर में गूगल को एक बार फिर मनमानी करने का दोषी पाया गया है। इटली के एंटी टेरेरिस्ट वाचडाग ने गूगल पर 904 करोड़ रुपये का जुमार्ना लगाया है। गूगल आरोप था कि उसने इलेक्ट्रिक वाहनों के चार्जिंग स्टेशन का पता बताने वाले एक सरकारी मोबाइल एप को अपने एंड्राइड ऑटो प्लेटफॉर्म पर चलने नहीं दिया। इटली की प्रतिस्पर्धा व बाजार अथॉरिटी (एजीसीएम) ने गूगल को यह भी आदेश दिया है कि वह इस एप जूसपास को एंड्राइड ऑटो पर तत्काल उपलब्ध करवाए। एजीसीएम ने कहा कि लगभग हर दूसरे स्मार्टफोन में इस्तेमाल हो रहे अपने ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्राइड से मिले एकाधिकार का दुरुपयोग कर उसने प्रतियोगिता को खत्म करने की कोशिश की।

एजीसीएम ने कहा, अपने एप स्टोर गूगल प्ले का भी गलत इस्तेमाल कर एप की उपयोगकताओं तक पहुंच को सीमित कर दिया। इस मामले पर गूगल के प्रवक्ता ने बयान दिया कि वह एजीसीएम के आदेश से सहमत नहीं है और इसके खिलाफ याचिका दाखिल करेंगे। इटली में इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग बढ़ा है। इन वाहनों के लिए इटली सहित यूरोपीय संघ में 95 हजार सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन बनाए गए हैं। इससे लोगों को वाहन की चार्जिंग रास्ते में खत्म होने की चिंता नहीं रहती। सहूलियत और बढ़ाने के लिए इटली की सरकारी संस्था एनिल की एक शाखा एनिल - एक्स ने जूसपास नामक एप बनवाया। इससे नागरिक निकटवर्ती चार्जिंग स्टेशन का पता जान सकते हैं। गूगल ने जूसपास को अपने एंड्राइड ऑटो प्लेटफॉर्म पर चलाने नहीं दिया। इस पर एजीसीएम में शिकायत हुई जिसमें बताया गया कि करीब दो साल से गूगल ने जूसपास को चलाने की अनुमति नहीं दी। जांच के बाद शिकायतों को सही मानते हुए एजीसीएम ने कहा कि एप को अपने प्लेटफार्म पर रोक कर गूगल ने गलत किया। यूरोपीय संघ के प्रतिस्पर्धा समझौते के आधार पर यह जुमार्ना लगाया गया। समझौते की धारा 102 के अनुसार, गूगल पर एकाधिकार का दुरुपयोग करने और प्रतियोगिता को बाधित करने का दोष सिद्ध हुआ है। इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में संबंधित एप को सीमित करना आपत्तिजनक है। तीन साल में 73।6 हजार करोड़ जुमार्ना प्रतिस्पर्धा विरोधी गतिविधियों के लिए गूगल पर यह पहला जुमार्ना नहीं है। पिछले केवल तीन वर्षों में ईयू के प्रतिस्पर्धा नियामक आयोग ने गूगल पर 1000 करोड़ डॉलर यानी करीब 73,600 करोड रुपये के जुमार्ने लगाए हैं।

निगम कर्मियों के वेतन के लिए 1051 करोड़ जारी

उपमुख्यमंत्री ने कहा कर्मचारियों को वेतन देने में ही इन पैसों का हो इस्तेमाल

नई दिल्ली (आनंद राय) ।

उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जानकारी दी कि दिल्ली नगर निगम इस महामारी के दौरान अपने सिस्टम में व्याप्त भ्रष्टाचार और अव्यवस्था के कारण अपने कर्मचारियों और फ्रंट लाइन वर्कर्स को महीनों से वेतन नहीं दे रही है। ये दिखाता है कि एमसीडी अपना कर्तव्य निभाने में पूरी तरह विफल हो चुकी है। इसलिए दिल्ली सरकार नगर निगम के फ्रंट लाइन वर्कर्रों और कर्मचारियों के वेतन के लिए 1051करोड़ रुपए जारी किए है।

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली में कोरोना महामारी के बीच में दिल्ली नगर निगम अपनी अव्यवस्था और भ्रष्टाचार की वजह से नगर निगम के कर्मचारियों को तनख्वाह नही दे पा रहा है। इस महामारी में जो डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ दिन रात मेहनत कर अपनी जान की बाजी लगाकर लोगों को बचा रहें हैं। वैसे में मेडिकल कर्मियों की तनख्वाह तक नही मिल पाना नगर निगम की बड़ी विफलता दर्शाता है। इसलिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में दिल्ली सरकार ने निगम कर्मचारियों के वेतन के लिए 1051 करोड़ रुपये ज़ारी किए है। इसमें पूर्वी दिल्ली नगर निगम के लिए 366.9 करोड़, उत्तरी दिल्ली नगर निगम के लिए 432.8 करोड़ और दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के लिए 251.6 करोड़ रुपए जारी किया गया है। उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि संकट के समय कर्मचारियों का वेतन नहीं रुकना चाहिए। उन्होंने कहा कि एमसीडी ये सुनिश्चित करे कि इस राशि का उपयोग बिना किसी हेराफेरी किए केवल कर्मचारियों को तनख्वाह देने के लिए किया जाए।

निगम के दबाव के कारण जारी किए 1050 करोड़ : महापौर

नई दिल्ली। उत्तरी दिल्ली के महापौर जय प्रकाश ने बताया कि दिल्ली सरकार ने दिल्ली की तीनों निगमों का 1050 करोड़ रुपए जारी कर दिया है। उन्होंने कहा कि उन्होंने पहली तिमाही के फंड के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री और माननीय उपराज्यपाल महोदय को पत्र लिखे थे। जिसके कारण आज दिल्ली सरकार ने उत्तरी दिल्ली नगर निगम के 432 करोड़ रुपए, पूर्वी दिल्ली नगर निगम के 367 करोड़ रुपए और दक्षिण दिल्ली नगर निगम के 251 करोड़ रुपया जारी किए गए हैं।

कोरोना की संभावित तीसरी लहर को लेकर तैयार : केजरीवाल

एजेंसी

नई दिल्ली । मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली सरकार द्वारा पालिका केंद्र स्थित एनडीएनसी बिल्डिंग में स्थापित इंटीग्रेटेड कोविड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का दौरा कर जायजा किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सेंटर पर कोरोना से संबंधित हर तरह का डेटा वास्तविक समय के आधार पर एकत्र किया जाएगा।

हमने एक हजार आईसीयू बेड बढ़ा दिए हैं : अरविंद केजरीवाल

- दिल्ली सरकार का इंटीग्रेटेड कोविड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर हुआ चालू
- कोरोना से संबंधित डेटा वास्तविक समय के आधार पर एकत्र किया जाएगा

यहां अस्पतालों में बेड, ऑक्सीजन, वैक्सीनेशन और कोविड प्रबंधन से संबंधित डेटा को एकत्र कर मिलान और विश्लेषण किया जा सकेगा। सीएम ने कहा कि अगर सरकार हवा में निर्णय लेगी है, तो वह कभी भी सफल नहीं होंगे, लेकिन वही निर्णय डेटा के आधार पर लेगी, तो वह सार्थक और प्रभावशाली होंगे। हम कोरोना की संभावित तीसरी लहर को लेकर तैयार हैं। हमने अभी एक हजार आईसीयू बेड बढ़ाए हैं और आगे भी हमारी तैयारी जारी रहेगी। सीएम ने कहा कि सभी का वैकसीनेशन बहुत जरूरी है। कई देशों का अनुभव बताता है कि बड़े स्तर पर वैक्सीनेशन करने से कोरोना को कम किया जा सकता है। हमने कोविशील्ड और कोवैक्सीन की 67-67 लाख वैक्सीन मांगी है और लगभग इतनी ही वैक्सीन के लिए स्पूतनिक को भी लिखा है।

सीएम अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा की दिल्ली सरकार ने एक एकीकृत कमांड एंड कंट्रोल सेंटर आईसीसीसी शुरू किया है। यहां अस्पतालों, ऑक्सीजन, टीकाकरण और कोविड प्रबंधन के अन्य पहलुओं से संबंधित डेटा को वास्तविक समय के आधार पर एकत्र, मिलान और विश्लेषण किया जाता है। यह हमें निर्णय लेने में मदद करेगा।

स्पूतनिक कंपनी से किया संपर्क

सीएम ने कहा कि स्पूतनिक कंपनी से संपर्क किया है। डॉ. रेड्डी कंपनी के भारत में डीलर है। हमने डॉ. रेड्डी को पत्र लिखा है, लेकिन अभी उनकी तरफ से कोई ठोस जवाब नहीं आया है कि वे कितनी वैक्सीन कब दे सकते हैं? हम लोगों ने कोविशील्ड की 67 लाख, कोवैक्सीन की भी 67 लाख वैक्सीन मांगी है और लगभग इतनी ही स्पूतनिक वैक्सीन के लिए भी लिखा है कि कितनी दे सकते हैं और कब-कब दे सकते हैं।

संक्षिप्त खबर

निगम ने दाह संस्कार के लिए शुरू की गोपराली परियोजना

नई दिल्ली। उत्तरी दिल्ली के महापौर जय प्रकाश ने आज श्मशान घाटों पर दाह संस्कार के लिए ईंधन के रूप में लकड़ी की जगह फसलों के अवशेष पराली और गाय के गोबर से निर्मित ईंधन ब्लॉक गोपराली की दूसरी परियोजना का शुभारंभ ग्रामीण गौशाला, बवाना में किया।
महापौर जय प्रकाश ने बताया कि इससे पहले रोहिणी में गोपराली परियोजना शुरू की गई थी।उन्होंने बताया कि उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने श्मशान घाटों पर दाह संस्कार के लिए ईंधन के रूप में लकड़ी की जगह फसलों के अवशेष पराली और गाय के गोबर से निर्मित ईंधन ब्लॉक गोपराली के उपयोग किया जाएग। उन्होंने बताया कि यहाँ पर लगभग 250-300 किलो की गोपराली प्रतिदिन बनायी जाएगी और विभिन्न श्मशान घाटों में इसका प्रयोग किया जाएगा। जय प्रकाश ने बताया कि यह दिल्ली में उत्तरी दिल्ली नगर निगम द्वारा शुरु की गई अपनी तरह की एक नई पहल है।

गुरुद्वारा सिंह सभा में उपलब्ध कराई जा रही है ऑक्सजीन सेवा

नई दिल्ली। शिरोमणि अकाली दल दिल्ली (शिअदद) के वरिष्ठ नेता गुरप्रीत सिंह खन्ना की अगुवाई में दक्षिणी दिल्ली में गुरुद्वारा सिंह सभा मालवीय नगर से राशन,ऑक्सीजन कैन और अन्य प्रकार की जरूरी सामग्री इस कोरोना संकट के बीच जरूरतमंदों को मुहैया करायी जा रही है। श्री खन्ना ने बताया कि वह और उनके सेवादारों की टीम जरूरतमंदों तक पहुंच कर उनकी हर संभव मदद कर रही है। लंगर, सूखा राशन और ऑक्सीजन कैन के अलावा सेनिटाइजेशन मशीनों से इलाकों को कीटाणुरहित करने की भी सेवा की जा रही है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में बेशक कोरोना संक्रमण और मौतों का आकड़ा कम होने लगा है, लेकिन सिखों का सेवा भाव कम नहीं हुआ है।

डीयू में गेस्ट फैकल्टी के लिए कोविड सहायता कोष की मांग

नई दिल्ली। दिल्ली विश्वविद्यालय के एडहॉक और गेस्ट फैकल्टी के लिए एक कोविड सहायता कोष स्थापित करने की मांग की गई है। दिल्ली विश्वविद्यालय शिक्षक संघ यानी डूटा, एकेडमिक काउंसिल, दिल्ली टीचर्स एसोसिएशन समेत कई संगठनों ने विश्वविद्यालय प्रशासन से एडहॉक टीचर्स के एवं उनके परिजनों के उपचार हेतु कोष बनाने की मांग की है। डीयू टीचर वेलफेयर फंड को भी बढ़ाने की मांग की गई है। दिल्ली विश्वविद्यालय में फिलहाल 5 से 7 लाख रुपए की धनराशि पीड़ित परिवार को मिलती हैं। हालांकि शिक्षकों की मांग है कि मौजूदा महामारी को देखते हुए यह सहायता बढ़ाकर 30 लाख की जाए।

रोहिणी में दूसरे कोविड केयर सेंटर की शुरुआत

'कोरोना प्रोटोकॉल काल का पालन करते हुए वैक्सीन अवश्य लगवाएं : विजेंद्र गुप्ता

एजेंसी

नई दिल्ली । उत्तर पश्चिम दिल्ली के सांसद हंसराज हंस, संगठन महामंत्री दिल्ली प्रदेश भाजपा सिद्धार्थन और दिल्ली भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष व विधायक विजेंद्र गुप्ता द्वारा आज रोहिणी के रजापुर, सेक्टर-9 संपूर्णा के प्रांगण में दूसरा नि:शुल्क कोविड केयर सेंटर दीप प्रज्वलन कर जनता को समर्पित किया गया।

इस कोविड केयर सेंटर में ऑक्सिजनयुक्त 15 बेड की व्यवस्था की गई है। जो आज से ही नागरिकों के लिए उपलब्ध है। इस अवसर पर हंसराज हंस और सिद्धार्थन ने विजेंद्र गुप्ता द्वारा कोरोना काल में रोहिणी के निवासियों के लिए कोरोना को हराने के लिए किए जा रहे प्रयासों की सराहना की। सिद्धार्थन ने कहा कि सेवा ही संगठन के भाव से भाजपा हर वो सुविधा मुहैया कराने का प्रयास कर रही है, जिससे आम जन को कोई असुविधा नहीं है और यही कारण है कि अब कोविड के केसों में लगातार कमी आ रही है।

हमें पूर्ण विश्वास है कि आने वाले कुछ दिनों में ही कोरोना पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, लेकिन उसके लिए हमें लगतार प्रयासरत रहना होगा। लॉकडाउन और अस्पतालों की स्थिति को देखते हुए दिल्ली की जनता काफी परेशान है। उन्होंने कहा कि मरीजों को लेकर लोग सरकारी अस्पतालों का चक्कर लगा रहे हैं जहां सुविधाओं का अभाव है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की कोशिश यही है की आम जनता को दवाइयां, ऑक्सीजन अस्पतालों में बेड, भोजन सहित जरूरी सामान उन तक पहुंचे ताकि इन्हें इन सब की चिंता करने की जरूरत ना हो और हम उसमें कामयाब भी हुए हैं। विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि यह कोविड केयर सेंटर सेवा भारती, संपूर्ण एनजीओ पुरुषोत्तम बंसल फाउंडेशन सामाजिक संगठनों के सहयोग से कोविड संक्रमित मरीजों के लिए 24 घंटे डॉक्टर, ऑक्सीजन, दवाइयां, नर्सिंग स्टाफ, भोजन सहित इलाज की सभी व्यवस्थाएं की गई हैं।

एक स्वास्थ्य कार्यकर्ता नई दिल्ली में एलएनजेपी अस्पताल के सामने रामलीला मैदान में एक नवनिर्मित 500 आईसीयू बेड कोविड -19 देखभाल केंद्र में एक कोविड -19 रोगी का निरीक्षण करते हुए।

भाजपा का आरोप केंद्र सरकार द्वारा दिए गए राशन को अपना बता रही दिल्ली सरकार

नई दिल्ली । लॉकडाउन में गरीबों को राशन नहीं मिल रहा है, लेकिन इस मुद्दे पर सियासत जारी है। भाजपा का कहना है कि केंद्र सरकार ने मई व जून माह के लिए मुफ्त राशन दिया है। दिल्ली सरकार इसे गरीबों के बीच नहीं बांट रही है और। केंद्र सरकार द्वारा दिए गए राशन को अब वह अपना बता रही है। उपराज्यपाल को इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए। इसकी जांच भी जरूरी है।

सीएम आवास के बाहर भाजपा नेताओं ने दिया धरना- केंद्र द्वारा दिए गए मुफ्त राशन वितरण में हो रही देरी के विरोध में पिछले दिनों भाजपा नेताओं व विधायकों ने मुख्यमंत्री आवास के बाहर धरना दिया था। प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता व विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी का कहना है कि आम आदमी पार्टी (आप) सरकार ने यह घोषणा की है कि दिल्ली के 72 लाख राशन कार्ड धारकों को मई और जून माह का मुफ्त राशन दिया जा रहा है।

यह घोषणा जनता के साथ धोखा

यह घोषणा जनता के साथ धोखा है, क्योंकि केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत दिल्ली के प्रत्येक राशन कार्ड धारक को आठ किलो गेहूं और दो किलो चावल मुफ्त दिया जा रहा है। मुफ्त राशन देने के लिए केंद्र सरकार ढाई सौ करोड़ रुपये खर्च कर रही है। इस योजना से दिल्ली सरकार का कोई लेना देना नहीं है। दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी सिर्फ इसे गरीबों तक पहुंचाने की है जिसे वह पूरा नहीं कर रही है।

सरकार बताए कितना पैसा खर्च हुआ

उन्होंने कहा कि अगर दिल्ली सरकार अपनी तरफ से गरीबों को मुफ्त राशन देना चाहती है तो वह अलग से इसकी व्यवस्था करे। दिल्ली सरकार को यह बताना चाहिए कि मुफ्त राशन के लिए उसने अपने खजाने से कितने पैसे खर्च किए हैं?

आक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी करने वाला आरोपित गिरफ्तार

नई दिल्ली । द्वारका जिला पुलिस के स्पेशल टास्क फोर्स की टीम ने आक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी करने वाले एक शख्स को गिरफ्तार किया है। इसकी पहचान मोहित के रूप में हुई है। पुलिस को इसके पास से चार आक्सीजन सिलेंडर बरामद हुए हैं। साथ ही पुलिस ने शख्स की आइ-10 कार भी जब्त कर ली है। द्वारका जिला पुलिस उपायुक्त संतोष कुमार मीणा ने बताया कि कोरोना संकट को देखते हुए चिकित्सा उपकरण की कालाबाजारी करने वाले शख्स को पकड़ने के निर्देश दिए गए हैं।

इसी क्रम में शुक्रवार को एएसआइ धर्मेंद्र को जानकारी मिली कि मोहित नाम का शख्स आक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी करता है और वह द्वारका सेक्टर 23 में अपनी कार से आनेवाला है। जानकारी के आधार पर एक टीम का गठन किया गया और पुलिसकर्मी सेक्टर 23 सीएनजी पंप के पास तैनात हो गए। करीब नौ बजे रात सेक्टर नौ की ओर से एक आइ-10 कार आती हुई दिखाई दी।

पुलिस ने कार को रोका तो चालक ने कार में रखे तीन सिलेंडर दिखा दिये, जिससे कि पुलिस उसे नहीं रोके, लेकिन पुलिस ने उसके इरादे को भांपते हुए पूछताछ शुरू की। कार चालक ने अपना नाम मोहित बताया। पूछताछ के दौरान वह पुलिस के सवालों का जवाब नहीं दे पाया। इसके बाद पुलिस ने मोहित को गिरफ्तार कर कार व आक्सीजन सिलेंडर जब्त कर लिए। बाद में आरोपित की निशानदेही पर एक और बड़ा सिलेंडर बरामद हुआ। ये सभी सिलेंडर नारायणा इलाके से आरोपित ने लिए थे।

दो बदमाशों को पुलिस ने किया गिरफ्तार - वहीं, पश्चिमी जिला स्पेशल स्टाफ की टीम ने रमेश नगर मेट्रो स्टेशन के पास झपटमारी की वारदात को अंजाम देने वाले दो बदमाशों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से दो सोने की चेन के अलावा अन्य आभूषण बरामद हुए हैं। बदमाशों की पहचान रोहित व अर्जुन के रूप में हुई। पुलिस ने बदमाशों की स्कूटी भी जब्त कर ली है।

पश्चिमी जिला पुलिस उपायुक्त उर्विजा गोयल ने बताया कि स्पेशल स्टाफ की टीम को जानकारी मिली कि रमेश नगर मेट्रो स्टेशन के पास नजफगढ़ रोड पर दो बदमाश आने वाले हैं। इसके बाद एसीपी आपरेशन जगपाल सिंह के मार्गदर्शन में एक टीम बनाई गई। टीम ने नजफगढ़ रोड पर नजर रखनी शुरू कर दी। इसी दौरान बदमाश स्कूटी पर आते हुए दिखाई दिए। पुलिस ने इन्हें रोककर पूछताछ की। साथ ही तलाशी ली। तलाशी में इनके पास से सोने के आभूषण बरामद हुए। पूछताछ में बदमाशों ने कुबूल किया कि राजौरी गार्डन, हरि नगर व खयाला इलाके में झपटमारी की वारदात को अंजाम दिया था। इनकी गिरफ्तारी से चार मामले सुलझ गए हैं।

कालाबाजारी करने वालों को नहीं मिलेगी अंतरिम जमानत, गर्भवती महिलाओं को जेल से छोड़ा जाएगा

नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित उच्च स्तरीय कमेटी ने जेलों में बंद कैदियों को 90 दिन या आठ सप्ताह के लिए पैरोल और जमानत पर छोड़ने की सिफारिश करने के फैसले में कुछ बदलाव किया है। हाल ही में हुई बैठक में फैसला लिया गया है जिन आरोपितों को आक्सीजन, दवाओं या अन्य जीवन रक्षक उपकरणों की तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया गया है, उन्हें कोविड-19 के तहत अंतरिम जमानत में राहत नहीं मिलेगी। वहीं राहत श्रेणी में गर्भवती महिला कैदियों और नाबालिग बच्चों की माताओं के अलावा हत्या के केस में दो साल से ट्रायल का सामना कर रहे कैदियों को भी शामिल करने का फैसला लिया गया है। पिछली बैठक में न्यायमूर्ति विपिन सांघी की अध्यक्षता वाली कमेटी ने अपनी सिफारिश में कहा था कि पिछले साल के मुकाबले इस हालात ज्यादा भयानक हैं। विशेषज्ञ और डॉक्टरों को भी यह मानना है कि कोविड-19 का मौजूदा स्ट्रेन जानलेवा है। कमेटी ने कहा कि इस साल फरवरी में आखिरी बैठक की थी और तब से लेकर अब तक हालात 360 डिग्री तक बदल चुके हैं। ऐसे में जेलों में भीड़ कम करना बेहद जरूरी है। इसलिए करीब चार हजार विचाराधीन कैदियों को जेलों से बाहर लाना होगा।

पूरे देश के साथ-साथ राजधानी में हालात बेकाबू हो चुके हैं और ऐसे में हमारा फर्ज बनता है कि हम संविधान का सम्मान करते हुए एक-एक जान बचाने का प्रयास करें। पिछली बैठक में वरिष्ठ नागरिक और सिविल मुकदमों में बंद कैदियों के अलावा 10 साल से ज्यादा सजा काट चुके कैदियों को प्राथमिकता दी गई थी और अब इसमें कुछ बदलाव के साथ कार्य शुरू कर दिया गया है।

ताहिर हुसैन ने दंगे भड़काने के लिए मानव हथियार के रूप में किया बहके लोगों का इस्तेमाल- कोर्ट

नई दिल्ली । दिल्ली दंगे के मुख्य आरोपित एवं आप के पार्षद रहे ताहिर हुसैन को कड़कड़डूमा कोर्ट ने शनिवार को जमानत देने से साफ इन्कार कर दिया। दंगे के दौरान दयालपुर इलाके में दो युवकों पर जानलेवा करने के अलग-अगल मामलों में उसने जमानत के लिए अर्जी लगाई थी। कोर्ट ने यह कहते हुए अर्जियां खारिज कर दी कि ताहिर ने सरगना की भूमिका में साम्प्रदायिक हिंसा की आग भड़काने के लिए अपने बाहुबल और राजनीतिक शक्तियों का इस्तेमाल किया। खुद आगे न आकर बहके हुए लोगों का उपयोग मानव हथियार के रूप में किया। कोर्ट ने टिप्पणी की कि विश्व शक्ति की ओर बढ़ रहे देश की अंतरात्मा पर इस दंगे ने गहरा घाव लगा है।

गत वर्ष 25 फरवरी को दुकान से घर का सामान लेने जा रहे युवक प्रिंस बंसल पर चांद बाग पुलिया के पास जानलेवा हमला हुआ था। प्रिंस बंसल ने पुलिस को बयान दिया था कि हे खजूरी स्थित ताहिर हुसैन के घर की छत से छत से पत्थर और पेट्रोल बम फेंके गए थे। फायरिंग भी की गई थी। जिसमें से एक गोली उनको लग गई थी। इसी जगह युवक अजय कुमार के हाथ में गोली लगी थी। दोनों की शिकायत पर अलग-अलग मुकदमे दर्ज हुए थे। दोनों ही मामलों में आरोपित ताहिर हुसैन ने जमानत के लिए फरवरी 2021 में अर्जी दायर की थी। जिस पर अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विनोद यादव की कोर्ट में सुनवाई हुई। ताहिर के अधिवक्ता रिजवान ने पक्ष रखा कि उनके मुवक्किल को दोनों मामलों में गलत फंसाया गया है। उसके खिलाफ सीसीटी कैमरे की कोई फुटेज नहीं है। न ही घायलों ने मूल प्राथमिकी में ताहिर का नाम दर्ज कराया था। साथ ही कहा कि ताहिर पर कोई स्पष्ट आरोप नहीं लगा है। राजनीति द्वेष के तहत उसे फंसाया गया है। ऐसा भी कोई साक्ष्य नहीं पेश किया गया कि गोली ताहिर की लाइसेंसी पिस्तौल से चली थी। अधिवक्ता यह भी पक्ष रखा कि इलाके की बिगड़ती स्थिति, पनी और अपने परिवार की जान को खतरे में देखते हुए ताहिर हुसैन ने दयालपुर थाने के थानाध्यक्ष और क्षेत्र के एसीपी को सात कॉल किए थे, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। पीसीआर को भी सात कॉल किए थे।

अभियोजन पक्ष की तरफ से विशेष लोक अभियोजक डीके भाटिया ने पक्ष रखा कि यह दंगा नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में एक सोची समझी साजिश थी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की यात्रा से पहले इसकी योजना बनाई गई। साजिशकर्ताओं को मालूम था कि पुलिस प्रशासन उस दौरान तैयारियों में जुटा हुआ था। उन्होंने दलील दी कि कॉल डिटेल रिकॉर्ड से स्पष्ट है कि ताहिर घटना के वक्त वहीं उपस्थित था, जिससे इन दोनों घटनाओं में उसकी सक्रियता बयां होती है। दोनों घायलों ने अपनी शिकायत में स्पष्ट बताया था कि घटना के वक्त ताहिर अपने घर की छत पर मौजूद था। साथ ही कहा कि कोई शक न करे, इसलिए आरोपित ने पुलिस अधिकारियों और पीसीआर को कॉल किया। कोर्ट को यह भी बताया कि दंगे से पहले क्षेत्र के सीसीटीवी कैमरों को तोड़ दिया गया था।

दोनों पक्षों के तथ्यों पर गौर करते हुए कोर्ट ने ताहिर हुसैन की जमानत अर्जियों को खारिज कर दिया। यह कहते हुए कि दूसरे समुदाय के ज्यादा से ज्यादा लोगों और संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने के लिए दंगाइयों ने घातक हथियारों का इस्तेमाल किया। इन मामलों आंखो देखे पर्याप्त साक्ष्य हैं। दोनों घायलों के अलावा चश्मदीद गवाहों ने आरोपित को पहचाना है। सीडीआर लोकेशन से पता चलता है कि आरोपित घटना के वक्त मौके पर मौजूद था और पूरी तरह सक्रिय था।

कोर्ट ने कहा कि रिकॉर्ड बताता है कि आरोपित ने दंगे भड़ाने से ठीक पहले खजूरी खास थाने से पिस्तौल को छुड़वाई थी। उसके पास जारी हुए 100 कारतूसों में 64 ही थे। बाकी कारतूस कहां और कब चलाए गए वह हिसाब नहीं दे पाया था।

भाजपा सांसद मीनाक्षी लेखी का आरोप, कांग्रेस से है नवनीत कालरा का संबंध

नई दिल्ली । भाजपा सांसद मीनाक्षी लेखी ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस का कोरोना संकट के दौर में आक्सीजन व अन्य उपकरणों की कालाबाजारी करने वालों के साथ मिलीभक्त है। उन्होंने कहा कि आक्सीजन कंसंट्रेटर की कालाबाजारी करने के आरोपित नवनीत कालरा का सीधा संबंध कांग्रेस है। वह अपने फेसबुक पर प्रधानमंत्री को महामारी के लिए दोषी ठहराता है। उसके रेस्तरां के कर्मचारी की फोटो गांधी परिवार के साथ है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कालाबाजारियों के साथ मिलकर दिल्ली व देश में आक्सीजन व अन्य जरूरी चीजों की कमी पैदा कर रही है।

मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि कालरा और उसके साथियों के ठिकानों से पुलिस ने लगभग 13 करोड़ रुपये मूल्य की 75 सौ आक्सीजन कंसंट्रेटर जब्त किए हैं। इससे साढ़े सात हजार मरीजों को लाभ मिल सकता था। कांग्रेस के लोग मरीजों की जान बचाने की जगह आवश्यक उपकरणों की जमाखोरी कर रहे थे। राहुल गांधी और उनके दोस्त आक्सीजन की कमी को लेकर हंगामा करते हैं। टीकाकरण को लेकर भ्रम फैलाते हैं। उन्होंने कहा कि कालाबाजारी करने वाले के वकील कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी हैं। वह उन्हें बचाने में लगे हुए हैं। उन्होंने कहा कि शहरी विकास मंत्री रहते हुए अजय माकन ने दिल्ली गोल्फ क्लब के लिए वर्ष 2004-05 में राबर्ट वाड्रा और 2005-06 में कालरा का नामिनेशन किया था।

संपादकीय

इबोला से सबक सीखे भारत

पश्चिमी अफ्रीका में इबोला महामारी ने 28,616 लोगों को संक्रमित किया था और 2014 से 2016 के बीच सिएरा लियोन, लाइबेरिया और गिनी में 11,310 लोगों की मौत हुई थी। इबोला से हुई वह त्रासदी भले ही एक क्षेत्र विशेष की थी, लेकिन कोविड-19 महामारी के समय वह गौरतलब है। आज जब दूसरी लहर भारत को कुचल रही है, तब सूक्ष्म और स्थूल, दोनों स्तरों पर इबोला संकट से हम सबक ले सकते हैं। सबसे पहले, इबोला की तरह ही कोविड-19 को भी देखभालकर्ता को भी होने वाली बीमारी के रूप में माना जाना चाहिए। पश्चिमी अफ्रीका में इबोला के इलाज से जमीनी स्तर पर जुड़े रहे विश्व प्रसिद्ध संक्रामक रोग चिकित्सक और मानव विज्ञानी पॉल फार्मर ने अपनी पुस्तक फेवर्स, फ्यूड्स ऐंड डायमंड्स = इबोला ऐंड द रैवेजेज ऑफ हिस्ट्री में लिखा है - महत्वपूर्ण बात यह है कि हजारों लोगों को इबोला इसलिए हुआ, क्योंकि वे बीमार लोगों की सेवा व मृतकों के अंतिम संस्कार में लगे थे। कोविड-19 के मामले में भी पहचानना जरूरी है कि यह देखभाल करने वालों, जैसे डॉक्टरों, नर्सों व पैरा-मेडिकल स्टाफ से लेकर घर, अस्पताल, क्लिनिक और श्मशान में काम करने वालों को प्रभावित कर रहा है। आज सेवा में लगे लोगों को अपने छोटे-छोटे प्रयास के स्तर पर कमियों को पहचानने व सुधार करने की जरूरत है।

टीकाकरण से परे भारत सरकार को कोरोना के खिलाफ मोर्चा ले रहे अग्रिम पंक्ति के योद्धाओं को जोखिम से बचाने के लिए ठोस योजना विकसित करनी चाहिए। अग्रिम पंक्ति के योद्धाओं की कमी का जोखिम बहुत वास्तविक है। श्मशान, कब्रिस्तान और मोर्चरी में कार्यरत लोग आम तौर पर दलित-दमित वर्ग से आते हैं, क्या उन्हें राज्य मान्यता देता है? क्या ऐसे उपेक्षित श्रमिकों (और उनके परिवारों) के लिए सरकार ने किसी बीमा की व्यवस्था की है? साफ है, इबोला या कोरोना से पीड़ित लोगों के साथ-साथ उनकी तिमारदारी करने वालों को भी उतनी ही गंभीरता से लिया जाए। दूसरा, संक्रमितों की देखभाल-क्षमता का विकास पहले करने के बाद ही कंटेनमेंट बनाकर वायरस से मुकाबले के निर्देश जारी किए जाने चाहिए। लॉकडाउन की घोषणा और सिर्फ जबरदस्ती से रोकथाम के उपाय लागू करना अपने आप में कोई समाधान नहीं है। इबोला के मामले में पॉल फार्मर चर्चा करते हैं, सार्वजनिक स्वास्थ्य और बायो-मेडिसिन राज्य के सामाजिक अनुबंध का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। सुरक्षित और प्रभावी देखभाल सुनिश्चित किए बिना रोकथाम की नीति की अपनी सीमाएं हैं। इबोला के समय भली-भांति देखा गया था कि ऐसा करना न सिर्फ पीड़ितों के जीवन को खतरे में डालता है, बल्कि राज्य के खिलाफ आक्रोश भी पैदा करता है, जो अविश्वास का रूप ले सकता है। अपने हाल पर छोड़ दिए गए लोग कंटेनमेंट, संपर्क-ट्रेसिंग और टीकाकरण का विरोध भी कर सकते हैं।

तीसरा, भारत में मौजूदा संकट इसलिए भी ज्यादा है, क्योंकि अस्पताल जरूरत से ज्यादा दबाव में आ गए हैं, और राज्य बुनियादी जरूरतों को पूरा करने में नाकाम है, ऑक्सीजन, बिस्तर, उपकरण, दवाएं और टीके का अभाव है। इबोला संकट भी यही दर्शाता है कि बुनियादी कर्मचारियों, सामग्री और देखभाल की व्यवस्था का अभाव था। पश्चिमी अफ्रीका में स्वतंत्र इबोला उपचार इकाइयां सामुदायिक सक्रियता के माध्यम से स्थापित की गई थीं और दूसरे व तीसरे स्तर की चिकित्सा की अनुपस्थिति में दो साल तक कायम थीं। भारत में उन इलाकों में चिकित्सा इकाइयों को तेजी से विकसित करना चाहिए, जिनके आसपास लोग इलाज के अभाव में मर रहे हैं, जहां अस्पताल में जगह नहीं मिल रही। लोग कोरोना से नहीं, बल्कि स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी से जान गंवा रहे हैं। अभी बुनियादी चिकित्सा ढांचे की अनुपस्थिति भारी पड़ रही है। आज जांच और इलाज के लिए तत्काल चिकित्सा इकाइयों और ऑक्सीजन हब बनाने की जरूरत है। चौथा, हम वायरल महामारी में स्वास्थ्य के सामाजिक निर्धारकों की उपेक्षा नहीं कर सकते। भारत में चल रही दूसरी लहर में संक्रमण और चिकित्सा व्यवस्थाओं की विफलता मध्य व उच्च-मध्य वर्गों को प्रभावित कर रही है। यह 2020 की पहली लहर से अलग है, जिसमें सबसे पहले दुर्बल श्रमिक, प्रवासी श्रमिक, गरीब व सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित ज्यादा निशाने पर थे। हमें खुद से पूछना चाहिए, राज्य, मीडिया, नागरिक और चिकित्सा व्यवस्थाएं पहली और दूसरी लहर के बीच के समय में पर्याप्त कदम उठाने में नाकाम क्यों रहीं? वर्तमान दौर दर्शाता है कि वर्ग और जाति के आधार पर संकट व देखभाल की हमारी धारणा कैसे तय की जाती है? हम सार्वजनिक स्वास्थ्य के प्रति तभी गंभीर होते हैं, जब उच्च वर्ग के लोग शिकार होने लगे। पांचवां, वायरस हमेशा समाज में कमजोरियों का पीछा करते हैं, और समाज की दरारों व कमियों पर हमला बोलते हैं। जैसा कि पॉल फार्मर ने एक साक्षात्कार में कहा था, महामारी की शुरुआत में एक भ्रम होता है कि यह नया वायरस समाज में सभी वर्गों, लोगों को समान रूप से प्रभावित करेगा, लेकिन ऐसा कभी होता नहीं है। आज वायरस की गति को समझने और उसे काबू करने के लिए हमें अपनी सामाजिक व्यवस्था को अधिक संवेदनशील ढंग से समझना चाहिए। इबोला के मामले में पॉल फार्मर इतिहास में समस्या की जड़ें तलाशते हैं। उपनिवेशवाद व उत्तर-औपनिवेशिक गृह युद्धों, जातीय संघर्ष और शोषणकारी संरचनात्मक ढांचा इबोला से मची तबाही के लिए जिम्मेदार हैं। भारतीय संदर्भ में देखें, तो स्वास्थ्य के प्रति सरकारों के रवैये का आधार नस्ल, वर्ग, लिंग या जातीयता नहीं रही है। इसी वजह ने सार्वजनिक स्वास्थ्य को सामाजिक या सरकारी प्राथमिकता के रूप में आकार लेने से रोका। ऐसे में, बीमार स्वास्थ्य व्यवस्था की जिम्मेदारी पीड़ितों पर ही डाल देना आम बात है। वैज्ञानिकों और वायरोलॉजिस्टों के साथ, जिनके प्रयास महत्वपूर्ण हैं, भारत सरकार को अपनी आपदा तैयारियों में समाज विज्ञानियों, सामुदायिक स्वयंसेवकों और नियमित रूप से समाज पर नजर रखने वाले लोगों को शामिल करना चाहिए। सिर्फ इबोला ही नहीं, एड्स जैसी वैश्विक महामारियों के रिकॉर्ड से भी इलाज की खास जरूरतों की पूर्ति, कमजोर समूहों की पहचान और मौजूदा देखभाल उपायों का सही पता चलता है।

प्रवीण कुमार सिंह

गांवों में कोरोना को नियंत्रित करने के लिए तात्कालिक उपाय करने की जरूरत

यह राहतकारी है कि अभी तक किसी वस्तु की आपूर्ति बाधित नहीं हुई, लेकिन कुछ वस्तुओं की आपूर्ति का संकट उभरता दिख रहा है। मुनाफाखोरों ने आवश्यक वस्तुओं के दाम अभी से बढ़ा दिए हैं। उन पर लगाम लगाने और जरूरी वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सरकारों को तत्काल प्रभाव से कड़े कदम उठाने चाहिए। याद रखें, अगले कुछ दिन कोरोना महामारी के नियंत्रण में बहुत महत्वपूर्ण हैं। यदि इन दिनों कोरोना संक्रमण का प्रसार ग्रामीण क्षेत्रों में होता है तो स्थिति विस्फोटक हो जाएगी। दूसरी लहर थमने के बाद तीसरी लहर से भी गांवों को बचाने के लिए तैयारी शुरू की जानी चाहिए।

पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय पंचायत दिवस के अवसर पर पंचायती राज से जुड़े अधिकारियों को संबोधित करते हुए ग्रामीण क्षेत्रों को पहले की तरह ही कोरोना संक्रमण से बचाने का आह्वान किया। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर भारत के कई राज्यों को अपनी गिरफ्त में ले चुकी है, जो पहले से कहीं अधिक तेज एवं मारक है। इनमें बड़ी आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और तमिलनाडु भी सम्मिलित हैं। कोरोना की इस दूसरी लहर में मरीजों की बढ़ती संख्या से विकसित एवं आधुनिक चिकित्सा सुविधा वाले प्रदेशों एवं महानगरों का स्वास्थ्य ढांचा तक चरमरा गया है, जिसमें दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, देहरादून, सूरत, चेन्नई आदि शामिल हैं। यहां मरीजों की संख्या में हुई अभूतपूर्व बढ़ोतरी से टेस्टिंग, एंबुलेंस, अस्पताल बेड, आक्सीजन आदि जरूरी स्वास्थ्य सुविधाएं कम पड़ गई हैं। साथ ही किसी आपात स्थिति को संभालने के लिए रेमडेसिविर जैसी दवाएं एवं वेंटिलेटर की उपलब्धता भी सीमित हो गई है। यह दुखद सच्चाई है कि इस बार कोरोना से जुड़ी अधिकांश मौतें समय पर आपात चिकित्सा सुविधाएं न मिलने के कारण हो रही हैं।

भारत एवं विश्व के महामारी विज्ञान विशेषज्ञों के अनुसार देश में कोरोना संक्रमण का उच्चतम स्तर मई के मध्य तक आएगा और उस समय संक्रमितों की संख्या और अधिक हो सकती है। तब बड़ी संख्या में मरीजों की देखभाल के लिए पर्याप्त अस्पताल बेड और डॉक्टरों एवं नर्सों की आवश्यकता होगी। इन दुरूह परिस्थितियों में प्रधानमंत्री मोदी का गांवों को कोरोना संक्रमण से बचाने का आह्वान अत्यंत महत्वपूर्ण एवं समीचीन है, लेकिन पिछली कोरोना लहर की तुलना में इस दूसरी लहर

में ग्रामीण क्षेत्रों को संक्रमण से बचाना पहले की अपेक्षा अधिक चुनौतीपूर्ण है। भारत में कोरोना संक्रमण की स्थिति जानने के लिए हुए दूसरे सीरो-प्रसार सर्वे (अगस्त-सितंबर 2020) में ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना संक्रमण 5.2 प्रतिशत था, जो तीसरे सर्वे (दिसंबर-जनवरी 2021) में बढ़कर 21.4 प्रतिशत हो गया। सिर्फ तीन महीनों में कोरोना संक्रमितों की संख्या में 16 प्रतिशत की वृद्धि का मुख्य कारण शहरों में रह रहे संक्रमित प्रवासी श्रमिकों का गांवों में वापस लौटना था। इस बार कोरोना वायरस में हुए परिवर्तनों के कारण संक्रमण दर पहले से बहुत अधिक है। दिल्ली, मुंबई जैसे शहरों में संक्रमितों की संख्या तो 36 प्रतिशत तक पहुंच गई है। बेंगलुरु में यह 55 प्रतिशत के करीब है। ग्रामीण क्षेत्रों की देश की जनसंख्या में हिस्सेदारी 65 प्रतिशत है, जबकि देश की चिकित्सा सुविधाओं में इसकी हिस्सेदारी केवल 35 प्रतिशत ही है। ऐसे में यदि गांवों में कोरोना संक्रमण बेलगाम होता है तो उसका बोझ पहले से चरमराई शहरी चिकित्सा व्यवस्था पर पड़ेगा, जिससे अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। जाहिर है शहरों से गांवों में कोरोना के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए कुछ तात्कालिक उपाय करने की आवश्यकता है। जैसे 15 प्रतिशत से अधिक पॉजिटिविटी दर वाले जिलों में सख्ती से लॉकडाउन लगाया जाए, गांवों में संक्रमितों की निगरानी के लिए जनभागीदारी से सूचना तंत्र स्थापित किया जाए, कोरोना टेस्टिंग के लिए ग्रामीण क्षेत्रों के लिए सर्मिपत तंत्र स्थापित किया जाए, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर कोरोना हेल्प सेंटर की स्थापना कर वहां सामान्य दवाइयों की किट उपलब्ध कराई जाए, एएनएम (सहायक नर्स मिडवाइफ) तथा अन्य ग्रामीण प्रशासन में लगे सरकारी कर्मचारियों को पीपीई किट उपलब्ध कराकर उन्हें घर में आइसोलेशन सुविधा विकसित करने का प्रशिक्षण दिया जाए। इसके अलावा गांवों में चिकित्सा सुविधाओं की स्थापना की जाए तथा जितना तेजी से संभव हो उतनी तेजी से निःशुल्क टीकाकरण किया जाए। हरिद्वार में आयोजित कुंभ, उत्तर प्रदेश में हुए पंचायती चुनाव, पांच राज्यों के चुनावों के कारण भी कोरोना संक्रमण गांवों तक पहुंचने लगा है, लेकिन सीमित प्रभाव होने के कारण उसे अभी नियंत्रित किया जा सकता है। इसके लिए जरूरी है कि संक्रमितों की पहचान कर उन्हें जल्दी से आइसोलेट कर उनका इलाज किया जाए तथा गांवों में शहरों से आने वालों की जांच कर उन्हें क्वारंटाइन किया जाए। यदि अंतिम विकल्प के रूप में राज्य कुछ जिलों में लॉकडाउन लगाने का निर्णय करते हैं तो संबंधित सरकारें उन जिलों में शहरी एवं ग्रामीण मजदूरों को सड़क पर आने से रोकने के लिए राशन के साथ कुछ नकद आर्थिक सहायता भी उपलब्ध कराएं, ताकि पिछले साल की तरह प्रवासी मजदूरों को गांव न लौटना पड़े तथा गांव में रह रहे गैर कृषि मजदूरों को काम की तलाश में शहर न जाना पड़े। गांवों के कोरोना मरीजों को वहीं पर आइसोलेट करने और साथ ही वहीं उनका उपचार करने की व्यवस्था इसलिए प्राथमिकता के आधार पर करनी होगी, ताकि शहरी क्षेत्र के अस्पतालों पर और दबाव न बढ़ने पाए। ध्यान रहे कि वे पहले से ही दबाव का सामना कर रहे हैं। जो शहर जितने बड़े हैं, वहां दबाव उतना ही अधिक है। स्थिति यह है कि दिल्ली-एनसीआर इलाके के कोरोना मरीज पड़ोसी राज्यों हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पंजाब तक के अस्पतालों में भर्ती होने पहुंचे हैं।

यह राहतकारी है कि अभी तक किसी वस्तु की आपूर्ति बाधित नहीं हुई, लेकिन कुछ वस्तुओं की आपूर्ति का संकट उभरता दिख रहा है। मुनाफाखोरों ने आवश्यक वस्तुओं के दाम अभी से बढ़ा दिए हैं। उन पर लगाम लगाने और जरूरी वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सरकारों को तत्काल प्रभाव से कड़े कदम उठाने चाहिए। याद रखें, अगले कुछ दिन कोरोना महामारी के नियंत्रण में बहुत महत्वपूर्ण हैं। यदि इन दिनों कोरोना संक्रमण का प्रसार ग्रामीण क्षेत्रों में होता है तो स्थिति विस्फोटक हो जाएगी। दूसरी लहर थमने के बाद तीसरी लहर से भी गांवों को बचाने के लिए तैयारी शुरू की जानी चाहिए।

अपने काम से नाम बनाने वाले राजनेता जगमोहन युवा पीढ़ी के लिए आदर्श बने रहेंगे

ईमानदार राजनेता और कुशल प्रशासक के रूप में जगमोहन का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उनकी छवि एक दूरदर्शी और कठोर फैसले लेने और उनका सही व समयबद्ध कार्यान्वयन कराने वाले कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति की रही है। आज की समझौता परस्त, अवसरवादी और पॉपुलिस्ट राजनीति व राजनेताओं के लिए उनका जीवन मिसाल है। उन्होंने सदैव पॉपुलिज्म की जगह अपने कर्तव्य, सिद्धांतों और जनकल्याण को प्राथमिकता दी। उन्होंने अडिग-अविचल होकर अपनी कर्तव्य पूर्ति की और उसकी राह में आने वाली हर चुनौती का सामना निडरतापूर्वक किया। किसी भी कीमत पर कभी भी समझौता नहीं किया। 25 सितंबर 1927 को अविभाजित पंजाब के हाफिजाबाद में जन्मे जगमोहन ने भारत विभाजन के दर्दनाक दृश्यों को अपनी आंखों से देखा था। उन्होंने विभाजन के फलस्वरूप हुए विस्थापन के दर्द को स्वयं भी झेला था। भारत-विभाजन और उससे पैदा होने वाले विस्थापन ने न सिर्फ उन्हें सेक्युलरिज्म के खोल में भारत में पनपी मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति के प्रति सजग किया, बल्कि इसके खिलाफ मुखर होने का साहस और इसके संतुलन के लिए काम करने की समझ भी दी। इसीलिए मुस्लिमपरस्त सेक्युलर लॉबी ने उनकी कार्यकुशलता और कार्यशैली को 'अल्पसंख्यक विरोधी' कहकर अवमूल्यित करने का प्रयास किया। प्रतिष्ठित भारतीय प्रशासनिक सेवा से अपने करियर की शुरुआत करने वाले जगमोहन ने पिछली सदी के सातवें दशक में दिल्ली विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष के रूप में सराहनीय काम करते हुए लोगों को अपनी कार्यशैली से प्रभावित किया। बहुत जल्द वे तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के पुत्र संजय गांधी के निकट आ गए।

आपातकाल के दौरान वे दिल्ली के उपराज्यपाल थे। उनकी पहचान एक अत्यंत कार्यकुशल, ईमानदार और अडिग इरादों वाले मजबूत प्रशासक की बन चुकी थी। पिछली सदी के नौवें दशक में जब जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद पनप रहा था तो तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने उन्हें राज्यपाल बनाकर जम्मू-कश्मीर भेजा। उन्होंने आतंकवाद को परोक्ष रूप से शह दे रही अलगाववादी शक्तियों की नकेल कसना शुरू किया। इसी क्रम में उन्होंने फारुक अब्दुल्ला की सरकार को बर्खास्त कराने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे जम्मू-कश्मीर आते ही इस बात को समझ गए थे कि आतंकवाद और अलगाववाद की जड़ वहां के क्षेत्रीय दल हैं। उन्होंने इस गठजोड़ को काफी हद तक तोड़ भी दिया। राजीव गांधी के बाद प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने भी उन्हें दोबारा जम्मू-कश्मीर का राज्यपाल बनाया। हालांकि उनका यह कार्यकाल अल्पकालीन ही रहा। जब जगमोहन ने कश्मीर घाटी में हिंदुओं पर हो रहे जुल्म को रोकने की कोशिश की और ज्यादतियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की तो दिल्ली में बैठे उनके हिमायतियों ने वीपी सिंह पर दबाव बनाकर उन्हें हटवा दिया। लेकिन 19 जनवरी 1990 की काली रात में कश्मीर घाटी में होने वाले कत्लेआम से ठीक पहले ही उन्होंने बड़ी संख्या में हिंदुओं को वहां से सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाकर उनकी रक्षा करने का सराहनीय कार्य किया। उन्होंने जम्मू और लद्दाख संभाग के साथ होने वाले भेदभाव और जम्मू-कश्मीर की राजनीति में हावी कश्मीरियों और मुसलमानों के वर्चस्व को संतुलित करने की कोशिश की। तमाम आतंकवादी संगठनों के अलावा पाकिस्तान की तत्कालीन प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो ने भी उनको खुलेआम धमकियां दीं। लेकिन उन्होंने इन गीदड़भभकियों की तनिक भी परवाह किए बिना और भी मजबूत इरादों के साथ पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद की रीढ़ तोड़ने का काम किया। इस दौर के अपने अनुभवों को उन्होंने अपनी बहुर्चिचत पुस्तक 'माइ फ्रोजन टर्बुलेंस इन कश्मीर' में अभिव्यक्त किया है। जम्मू-कश्मीर के राज्यपाल के रूप में उन्होंने श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की स्थापना करके श्रद्धालुओं के चढ़ावे के उपयोग में पारदर्शिता सुनिश्चित की। उल्लेखनीय है कि इसी राशि से श्री माता वैष्णो देवी विश्वविद्यालय की स्थापना हुई है। अस्पताल आदि और भी अनेक सामाजिक कार्य इसी चढ़ावे से होते हैं। उन्होंने वैष्णो देवी यात्रा और अमरनाथ यात्रा को विकसित, व्यवस्थित और सुविधाजनक भी किया। जगमोहन का दृढ़ विश्वास था कि अनुच्छेद 370 राष्ट्रीय एकीकरण की सबसे बड़ी बाधा है। यह अनुच्छेद ही जम्मू-कश्मीर को भारत से अलगाता है। यही जम्मू-कश्मीर में भारतीय संविधान के अन्य तमाम प्रविधानों को लागू नहीं होने देता। उन्होंने इसे अस्थायी और संक्रमणकालीन प्रविधान मानते हुए इसे जल्द-से-जल्द समाप्त करने की बात खुलकर की। दिल्ली की मुस्लिमपरस्त सेक्युलर लॉबी के दबाव में जब उन्हें जम्मू-कश्मीर के राज्यपाल पद से अकारण कार्यमुक्त कर दिया गया तो वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की नजरों में आ गए। उनके काम करने के तरीके ने ही उन्हें आगे और अधिक काम करने के अवसर दिलाए। वे कम-से-कम चार प्रधानमंत्रियों के पसंदीदा 'टफ टास्क मास्टर' थे। उनकी कार्यशैली ने उनके जितने विरोधी तैयार किए, उससे कहीं ज्यादा उनके प्रशंसक भी बनाए। संघ के आग्रह पर वे भाजपा में शामिल हो गए और नई दिल्ली लोकसभा क्षेत्र से तीन बार वर्ष 1996, 1998 और 1999 में निर्वाचित हुए। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में वह शहरी विकास, संचार और पर्यटन मंत्री रहे। सार्वजनिक जीवन में उनके उल्लेखनीय योगदान और राष्ट्र-सेवा के लिए उन्हें भारत के प्रतिठति नागरिक अलंकरणों- पद्म श्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया।

गांवों में फैला कोरोना

केंद्र ही खरीदे टीका

दिल्ली सरकार ने कोवैक्सीन की कमी की बात कहते हुए 18-44 साल आयुवर्ग के लिए चल रहे 100 टीकाकरण केंद्र बंद कर दिए हैं। उधर, महाराष्ट्र ने भी 18-44 साल आयुवर्ग के लिए टीकाकरण रोक दिया है। इस वर्ग के लिए उसके पास 10 लाख खुराक थी, जिनका इस्तेमाल वह 45 साल से अधिक उम्र वालों को दूसरी खुराक देने में करेगा। इस आयु वर्ग में टीके की कमी का सामना करीब-करीब सभी राज्य कर रहे हैं। जरा गौर करिए, 1 मई से 12 मई तक 18-44 साल की आयु वालों को टीके की कुल 34.66 लाख डोज मिली हैं, जबकि जरूरत 1.20 अरब की है।

इस आयु वर्ग में 6.25 लाख डोज के साथ महाराष्ट्र सबसे आगे है। इसके बाद राजस्थान, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों का नंबर आता है। लेकिन यह संख्या इतनी कम है कि इससे कोरोना की दूसरी लहर को रोकने में मदद नहीं मिलने वाली और इसकी वजह टीके की कमी है। सचाई यह भी है कि आज कोरोना के अधिक मरीज इसी आयु वर्ग के हैं। इसे देखते हुए टीकाकरण की रफ्तार में तुरंत तेजी लाने की जरूरत है।

इसका उपाय घरेलू कंपनियों के साथ अंतरराष्ट्रीय बाजार से टीका खरीदना हो सकता है। कई राज्यों ने इसकी पहल की है। उन्होंने ग्लोबल टेंडर दिए हैं। लेकिन यहां भी राज्य कंपनियों से अलग-अलग बातचीत कर रहे हैं। अगर वे मिलकर मोलभाव करें तो इसकी लागत कम आएगी। साथ ही, राज्यों को एक कीमत पर टीका मिल सकेगा। 12 विपक्षी दलों ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की है कि अंतरराष्ट्रीय और घरेलू बाजार से टीके की खरीद केंद्र सरकार करे। दिल्ली सरकार ने भी 100 टीकाकरण केंद्र बंद करने के ऐलान के साथ कहा कि टीका दिलाने की जिम्मेदारी केंद्र की है। वैसे, मोदी सरकार का कहना है कि पहले राज्यों ने ही वैक्सीन खरीदने को लेकर स्वायत्तता की मांग की थी। इस आरोप-प्रत्यारोप को रहने दें तो इस सचाई से कोई इनकार नहीं कर सकता कि देश आज टीके की जबरदस्त किल्लत से गुजर रहा है, जिसे तत्काल दूर करने की जरूरत है।

केंद्र ने हाल में इसके लिए कई कदम उठाए हैं। उसे अब एक कदम और आगे बढ़कर टीके की खरीद का जिम्मा अपने हाथों में लेना चाहिए। इससे वित्तीय संसाधनों की बचत होगी और राज्यों के लिए टीकाकरण अभियान में तेजी लाने का रास्ता भी साफ होगा। साथ ही, केंद्र को राज्यों के बीच टीके का बंटवारा भी इस तरह से करना होगा कि 18-44 साल आयुवर्ग के टीकाकरण को लेकर विषमता न पैदा हो। अभी ऐसी ही स्थिति दिख रही है। 18-44 आयुवर्ग में 85 फीसदी टीके सिर्फ सात राज्यों में लगे हैं। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में इस विषमता को रोकने का वादा किया था, उसे अपना वादा पूरा करना चाहिए।

पाकिस्तान से वार्ता द्विपक्षीय स्तर पर ही हो सकती तीसरे पक्ष के लिए कोई गुंजाइश नहीं

भारत ने अपने रवैये में भविष्य की वार्ताओं के लिए कुछ लचीलापन छोड़ दिया। उस समझौते के अनुसार, 'दोनों देश इस पर सहमत हुए कि उनके बीच मतभेद द्विपक्षीय वार्ता के जरिये शांतिपूर्ण तरीके से या परस्पर सहमति से स्वीकृत किसी अन्य शांतिपूर्ण तरीके से ही सुलझाए जाएंगे।' इसमें एक सन्निहित शर्त है कि किसी भी अन्य तरीके में दिल्ली की सहमति आवश्यक होगी। संभव है कि ओतेबा अपने मेजबान अमेरिकियों के बीच इस क्षेत्र में यूएई के रुतबे को दिखाने के लिए कुछ प्रयास कर रहे हों। ऐसे प्रयासों को सुर्खियों में जगह नहीं मिलनी चाहिए।

अमेरिका में संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई के राजदूत यूसुफ अल ओतेबा ने बीते दिनों एक बड़ा दावा किया। स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित एक वर्चुअल कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि उनका देश भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता कर रहा है। यह बात कुछ अजीब इसलिए थी, क्योंकि उनसे इस बारे में कोई सवाल ही नहीं किया गया था। उनसे पूछा गया था कि क्या उनका देश अफगान शांति प्रक्रिया में पाकिस्तान को और उपयोगी बनाने के लिए उसे समझाने का प्रयास करेगा? इसके जवाब में उन्होंने खुद ही भारत और पाकिस्तान को लेकर यह टिप्पणी की। स्पष्ट है कि ओतेबा कूटनीति की पिच का अपने मुताबिक इस्तेमाल कर रहे थे, क्योंकि यह एकदम स्पष्ट है कि भारत, पाकिस्तान और यूएई के बीच कोई त्रिपक्षीय वार्ता नहीं हो रही है। इसका अर्थ यह नहीं कि भारत और पाकिस्तान एक दूसरे के बिल्कुल संपर्क में ही नहीं हैं। विशेषकर तब जब दोनों देशों के बीच सीमा पर तनाव घटाने को लेकर, जो इन परमाणु शक्तियों के बीच नागरिक सीमा न रहकर सैन्य सीमा बन गई है। इसीलिए दोनों देशों के सैन्य अभियानों के महानिदेशक तनाव घटाने की संभावनाओं को तलाशने के लिए एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं। यह सब उनकी जानकारी के बिना संभव नहीं है, जिन पर राष्ट्रीय सुरक्षा का दारोमदार है।

भारत और पाकिस्तान के बीच वार्ता की तार्किकता को लेकर कोई संदेह नहीं। संबंधों को शांतिपूर्ण एवं स्थायित्व रूप देने के लिए किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री ने कभी कोई हिचक नहीं दिखाई। सिर्फ एक उदाहरण से समझ लीजिए कि

वर्ष 1965 में तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री काहिरा से लौटते समय तबके पाकिस्तानी राष्ट्रपति अयूब खान से वार्ता के लिए कराची में रुक गए थे। इसके बावजूद पाकिस्तान ने उसी साल भारत के साथ सीमा पर विश्वासघात किया। पाकिस्तान से वार्ता किस परिवेश में संभव हो सकती है, उसे लेकर स्पष्टता बहुत आवश्यक है। भारतीय कूटनीति का यही तकाजा रहा है कि सभी प्रकार की वार्ताएं द्विपक्षीय स्तर पर होनी चाहिए। वार्ताओं को लेकर भारत का अनुभव खट्टा ही रहा है। इसकी शुरुआत जवाहरलाल नेहरू द्वारा लॉर्ड माउंटबेटन की सलाह पर कश्मीर मामले को संयुक्त राष्ट्र में ले जाने वाले कदम के साथ ही हो गई थी। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इस पर अवश्य कड़ा रुख अपनाया था कि वार्ता और आतंक साथ-साथ नहीं चल सकते। दोनों देशों के बीच अंतिम शिखर वार्ता जो जुलाई 2001 में आगरा में हुई थी, उसमें पाकिस्तान ने मसलों को द्विपक्षीय स्तर पर सुलझाने की शर्त पर तो सहमति जताई, लेकिन आंतकवाद वाली दूसरी शर्त से वह मुकर गया। गत सात वर्षों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बार-बार दोहराया है कि इन दोनों शर्तों पर कोई रियायत संभव नहीं।

भारत के उलट पाकिस्तान ने हमेशा से द्विपक्षीय विवाद के अंतरराष्ट्रीयकरण का प्रयास किया है। फिर इसमें चाहे उसे महाशक्तियों को या क्षेत्रीय ताकतों को जोड़ना हो या संयुक्त राष्ट्र के समक्ष ही गुहार क्यों न लगानी पड़ी हो। इस्लामाबाद में कुछ आशावादियों ने तो इसमें चीन तक को शामिल करने के भी प्रयास किए। असल में इस्लामाबाद किसी तीसरे पक्ष को इसलिए शामिल करना चाहता है ताकि वह भारत पर जम्मू-कश्मीर की स्थिति से समझौता करने के लिए दबाव बनाए और पाकिस्तान उसे अपनी 'जीत' के तौर पर पेश कर सके। भारत के साथ वार्ता को लेकर पाकिस्तानी नीति को एक वाक्य में इस प्रकार समेटा जा सकता है कि मानों कोई एक पैर ब्रेक पर मजबूती से टिकाकर ही आगे बढ़ रहा हो। यह खेल अभी भी जारी है। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान और विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी दोनों यह कह चुके हैं कि भारत के साथ तब तक वार्ता संभव नहीं जब तक वह जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को बहाल नहीं करता।

जहां तक यूएई की बात है तो वह भारत का बहुत घनिष्ठ मित्र है। यह मित्रता एक निर्विवाद तथ्य है, लेकिन मित्रता का अर्थ यह नहीं कि उसमें सिद्धांतों की बलि दे दी जाए। एक बार द्विपक्षीयता के सिद्धांत से समझौता किया गया तो भारत के मित्र देशों की सूची से तीसरे देश का नाम कभी भी उछाला जा सकता है। क्या हम कल इस पर बहस करेंगे कि अमेरिका भारत का भरोसेमंद मित्र नहीं है? यदि यह स्वीकार करते हैं तो क्या हम उसके साथ जुड़ी अच्छी भावनाएं और उसके दर्जे को अनदेखा कर सकते हैं कि वाशिंगटन को तो वार्ता की मेज पर लाया ही जाएगा?

इतिहास इसका साक्षी रहा है कि मित्र देशों ने इस द्विपक्षीय विवाद को दिल्ली के नजरिये से देखने के बजाय अपने ही चश्मे से देखा है। अब हम उस कालखंड से आगे बढ़ चुके हैं, जब ब्रिटेन यह सोचता था कि इसमें हस्तक्षेप उसका स्वाभाविक अधिकार है। या फिर उस दौर से भी जब अमेरिका अपने दक्षिण एशियाई समीकरणों के अनुकूल किसी किस्म के समझौते पर दबाव बढ़ा रहा था। हमारी विदेश नीति उन गलियारों में वापस नहीं लौट सकती, जिन्हें वह काफी पीछे छोड़ चुकी है।

अगर पाकिस्तान भारत के साथ वार्ता के लिए तैयार है तो उसके नेताओं को एक महफूज टेलीफोन चुनकर दिल्ली में एक फोन लगाना होगा। भारत और पाकिस्तान ऐसे लोगों को चुन सकते हैं, जो दोनों प्रधानमंत्रियों के बीच भविष्य के सम्मेलन की रूपरेखा तैयार कर सकें। इतिहास में गंवाए अवसरों पर ध्यान नहीं देना होगा, जैसा इंदिरा गांधी ने 2 जुलाई, 1972 को शिमला समझौते पर हस्ताक्षर के दौरान जुल्फिकार अली भुट्टो के साथ गंवा दिया था। उस क्षण कश्मीर विवाद को हमेशा के लिए सुलझाया जा सकता था, लेकिन हम एक परास्त, पस्त और हताश पड़े पाकिस्तान से केवल 'जम्मू-कश्मीर में नियंत्रण रेखा के सम्मान की प्रतिबद्धता' ही ले सके, जिसे 'स्थायी शांति की कुंजी' बताया गया।

भारत ने अपने रवैये में भविष्य की वार्ताओं के लिए कुछ लचीलापन छोड़ दिया। उस समझौते के अनुसार, 'दोनों देश इस पर सहमत हुए कि उनके बीच मतभेद द्विपक्षीय वार्ता के जरिये शांतिपूर्ण तरीके से या परस्पर सहमति से स्वीकृत किसी अन्य शांतिपूर्ण तरीके से ही सुलझाए जाएंगे।' इसमें एक सन्निहित शर्त है कि किसी भी अन्य तरीके में दिल्ली की सहमति आवश्यक होगी। संभव है कि ओतेबा अपने मेजबान अमेरिकियों के बीच इस क्षेत्र में यूएई के रुतबे को दिखाने के लिए कुछ प्रयास कर रहे हों। ऐसे प्रयासों को सुर्खियों में जगह नहीं मिलनी चाहिए।

गौरवशाली भारत के स्वामी प्रकाशक एवं मुद्रक प्रवीण कुमार सिंह द्वारा आला प्रिंटिंग प्रेस 3636 कटारा दिना बेग लाल कुआं, दिल्ली.... से मुद्रित एवं, ब्लॉक नं. 23 मकान नं. 399 त्रिलोकपुरी दिल्ली....91 से प्रकाशित संपादक -प्रवीण कुमार सिंह टेलीफोन नं. 011.22786172 फैक्स नं. 011.22786172
RNI, No. DELHIN383334, E-mail: gauravashalibarat@gmail.com इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के पीआरबी एट के तहत

संक्षिप्त खबर

रालोद ने की गेहूं खरीद केन्द्रों पर किसानों का उत्पीड़न रोकने व सुचारु खरीद शुरू करने की मांग

आगरा । राष्ट्रीय लोक दल नेताओं ने गेहूं के सरकारी खरीद केंद्रों पर हो रहे किसानों के उत्पीड़न पर गहरा रोष व्यक्त किया है राष्ट्रीय लोक दल के पूर्व प्रदेश प्रवक्ता कसान सिंह चाहर, पूर्व मंडल अध्यक्ष नरेंद्र बघेल ,चौधरी दिलीप सिंह, मुकेश पहलवान आदि ने आदि ने संयुक्त रूप से जारी बयान में कहा है कि सरकारी खरीद केंद्रों पर किसान मारा मारा फिर रहा है लेकिन किसान के गेहूं की खरीद नहीं हो रही है, तीन तीन दिन तक ट्रैक्टर ट्रॉली में किसान अपने गेहूं को लादकर खरीद केन्द्रों पर खड़ा रहता है फिर भी उसका नंबर नहीं आ रहा है। खरीद केंद्रों के कर्मचारी कभी बारदाना ना होने का बहाना, कभी खरीद केंद्र पर जगह ना होने का बहाना, कभी तोलने वाले कर्मचारियों का न आने का बहाना, तो कभी खरीदे हुए गेहूं का न उठने का बहाना बनाकर उत्पीड़न कर रहे हैं जिससे किसान परेशान होकर अपना गेहूं प्राइवेट मंडियों में सस्ते दामों पर बेचने को मजबूर है।

राष्ट्रीय लोक दल नेताओं ने कहा है कि खरीद केंद्रों के कर्मचारी और दलालों का बड़ा कॉकस बन गया है और यह दलाल किसानों से सस्ता गेहूं खरीद कर सरकारी खरीद केंद्रों पर दे रहे हैं इसके एवज में यह सरकारी खरीद केंद्रों के कर्मचारियों को 50 रुपये प्रति कुंतल तक का कमीशन दे रहे हैं, इन दलालों का गेहूं तुरंत रात में भी तोला जाता है या इन दलालों को कर्मचारी सीधा वारदाना दे रहे हैं और यह दलाल किसानों से खरीदे हुए गेहूं को एक गोपनीय स्थान पर रखकर सीधे ट्रकों में लादकर एफसीआई के गोदामों में पहुंचा रहे हैं जबकि किसान को तीन-तीन दिन तक खड़ा रखा जाता है, जिससे मजबूरी में परेशान होकर किसान अपने गेहूं को इन दलालों को बेचने पर मजबूर हो रहा है राष्ट्रीय लोकदल नेता कसान सिह चाहर ने कहा है कि जिलाधिकारी आगरा और जनप्रतिनिधि तुरंत किसानों के गेहूं की खरीद सुचारू रूप से शुरू कराएं जिससे किसानों का उत्पीड़न रोका जा सके अन्यथा की स्थिति में राष्ट्रीय लोक दल इस कोरोना काल में भी किसानों को साथ लेकर खरीद केंद्रों पर धरना प्रदर्शन करने को बाध्य होगा।

सरयू राय ने सीएम हेमंत सोरेन पर लुटाया प्यार, पीएम नरेंद्र मोदी की साख पर उठाए सवाल...

रांची । कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर में झारखंड में सियासत उफान पर है। अब भाजपा के पुराने दिग्गज, पूर्व मंत्री और जमशेदपुर पूर्वी के निर्दलीय विधायक सरयू राय भी कोरोना पर मचे राजनीतिक घमासान में कूद गए हैं। अपने ताजा बयानों में सरयू ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनकी साख घटने का सर्टिफिकेट दे दिया है।

शुक्रवार को ट्विटर पर लिखे संदेश में सरयू राय ने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की साख घटी है, पर लोगों में विश्वास नहीं घटा है। सरयू राय ने दूसरी ओर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बारे में कहा कि राज्य में उनकी साख पूर्व की तुलना में बढ़ी है। हालांकि सरयू ने उन्हें नसीहत देते हुए कहा कि इस अनुपात में उन्हें लोगों के बीच विश्वास भी बढ़ाना होगा। सरयू राय के इस ट्वीट को सीएम हेमंत सोरेन ने रीट्वीट कर अपनी सहमति जाहिर की है।

बता दें कि हाल के दिनों में सीएम हेमंत सोरेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर एकतरफा संवाद को लेकर कड़ी टिप्पणी की। जिसके बाद पूरे देश में सियासी घमासान मच गया। तब देश के कई राज्यों के मुख्यमंत्री ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को निशाने पर लिया। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने सीएम हेमंत सोरेन को फेल मुख्यमंत्री बताया। वहीं आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने भी हेमंत सोरेन की खिंचाई की।

चंडीगढ़ में 8 मौतों के साथ 660 नए पॉजिटिव, मोहाली में घटे संक्रमण के नए मामले

चंडीगढ़ । शहर में नए कोरोना संक्रमित मामलों में गिरावट दर्ज की गई है। शनिवार को 660 नए पॉजिटिव केस दर्ज किए गए। इनमें 351 पुरुष और 309 महिलाएं हैं। इसके मुकाबले पिछले 15 दिन से लगातार 800 से 900 संकरित मामले दर्ज किए जा रहे थे। कोरोना संक्रमण से 8 लोगों की मौत दर्ज की गई। चंडीगढ़ में अब तक 625 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं, कुल 54,703 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में 3,417 लोगों का कोरोना टेस्ट किया गया। 963 कोरोना संक्रमित मरीजों को ठीक होने के बाद डिस्चार्ज किया गया। अब तक 46,231 संक्रमित मरीजों को ठीक होने के बाद डिस्चार्ज किया जा चुका है।

चंडीगढ़ में इस समय 7,847 कोरोना एक्टिव मरीजों का होम आइसोलेशन या अस्पताल में इलाज चल रहा है। स्वास्थ्य विभाग अब तक 4,58,231 लोगों के कोरोना सैंपल लेकर टेस्टिंग कर चुका है। इनमे से 4,02,365 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। 97 लोगों के कोरोना सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं। इनकी जांच रिपोर्ट रविवार देर शाम तक आएगी।

लुधियाना में घर लौट रहे युवक से 10,000 कैश व मोबाइल लूटा, मामला दर्ज

लुधियाना । काम खत्म कर अपनी साइकिल पर सवार होकर घर लौट रहे एक युवक को दो एक्टिवा सवार युवकों ने रास्ते में रोककर उससे नकदी व मोबाइल लूट लिया। जिसकी शिकायत उसने थाना बस्ती जोधेवाल की पुलिस को दर्ज करवाई। पुलिस ने बयान दर्ज कर दो अज्ञात एक्टिवा सवार व्यक्तियों पर मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

नदीम अंसारी ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वह 13 मई शाम को काम खत्म कर अपनी साइकिल पर घर लौट रहा था। जब वह काली सड़क के पास पहुंचा तो वहां उसे एक्टिवा पर आए दो युवकों ने रोक लिया। उन्होंने उसे डरा धमका कर उससे 10 हजार रुपए की नकदी व मोबाइल छीन लिया और मौके से फरार हो गए। जिसकी सूचना उसने तुरंत कंट्रोल रूम पर पुलिस को दी। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। लुधियाना। हैबोवाल के इलाके में घर लौट रही एक महिला से एक्टिवा सवार दो युवकों ने मोबाइल छीन लिया। महिला ने शिकायत थाना हैबोवाल की पुलिस को दी। पुलिस ने महिला की शिकायत पर दो अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है। यह मामला पुलिस ने नामदेव कॉलोनी सिविल सिटी निवासी रीटा के बयानों पर दर्ज किया है। महिला ने पुलिस को बताया कि 14 मई की शाम वह मैक्सी नर्सिंग होम से छुट्टी करके घर लौट रही थी। जब वह धर्मशाला रोड सिविल सिटी के पास पहुंची तो पीछे से दो एक्टिवा सवार युवक आए और उसके हाथ में पकड़ा मोबाइल फोन छीन लिया। उसने काफी शोर भी मचाया लेकिन तब तक आरोपित वहां से फरार हो चुके थे। महिला ने घटना की जानकारी कंट्रोल रूम पर दर्ज करवाई। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।

कनकनी स्वास्थ्य व कल्याण केंद्र में 18 वर्ष से अधिक आयु वालों का नहीं शुरू हुआ टीकाकरण

लोयाबाद । कनकनी स्वास्थ्य एंव कल्याण केंद्र में 18 वर्ष से ऊपर वाले व्यक्तियों को टीकाकरण शुरू नहीं हुआ। वहीं दूसरी ओर 45 वर्ष से अधिक आयु वाले का एक दिन टीकाकरण होने के बाद बंद हो गया है। 18 वर्ष से अधिक आयु वाले को अब तीन किलोमीटर दूर करकेंद शहरी स्वास्थ्य केंद्र में जाकर टिका लगवाना पड़ेगा। दुसरे डोज लगाने से पहले जांच के लिए स्वाब लिए जाने के कारण मात्र 11 लोग ही टीका लगाया था। कहा जा रहा है कि स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा दुसरे डोज के समय बढ़ा दिया गया है। बहुत से लोगों का दुसरे डोज का समय अभी नहीं हुआ है हालांकि पहला डोज लेने वाले लोगों को दुसरा डोज लेने के लिए उनके मोबाइल पर लगातार मैसेज आ रहे है। यदि इस केंद्र में टीकाकरण शुरू नहीं हुआ तो करीब 20 हजार लोगों को दुसरी जगह जा कर टीका लेना पडेगा। लोयाबाद कनकनी,मदनाडीह,सेंद्रा बांसजोडा एकडा आदि क्षेत्र के लोगों ने स्वास्थ्य विभाग से कनकनी स्वास्थ्य एंव कल्याण केंद्र में दुसरे डोज के साथ साथ 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के लिए टिका करण शुरू कराने की मांग की है।

उत्तर प्रदेश में 24 मई तक बढ़ाया गया कोरोना कर्फ्यू, मंत्रिपरिषद की बैठक में फैसला

लखनऊ । उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण के सेकेंड स्ट्रेन पर कोरोना कर्फ्यू के दौरान काफी प्रभावी असर होने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने मंत्रिमंडल के सदस्यों के साथ बैठक के बाद इनको और बढ़ाने का निर्णय लिया है। उत्तर प्रदेश में अब 24 मई की सुबह सात बजे तक कोरोना कर्फ्यू लागू रहेगा। नियम तोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आवश्यक सेवाओं को छूट मिलती रहेगी।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सरकारी आवास पर सम्पूर्ण मंत्रिमंडल की बैठक में कैबिनेट मंत्री के साथ राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार तथा राज्य मंत्री भी शामिल थे। इसमें निर्णय लिया गया कि उत्तर प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू को 24 मई तक बढ़ाया जाए। एक हफ्ते तक इसको बढ़ाया गया है। इसके साथ ही सरकार ने सभी पंजीकृत पटरी दुकानदारों को आर्थिक सहायता के रूप में 1000 रूपया देने का भी निर्णय लिया गया। इन सभी को प्रदेश सरकार तीन महीने का राशन भी देगी। कैबिनेट मीटिंग में यूपी ऑक्सीजन उत्पादन प्रोत्साहन योजना 2021 को भी मंजूरी दी गई है।

कसा निजी अस्पतालों पर शिकंजा- इसके साथ ही प्रदेश सरकार ने सभी कोविड संक्रमितों का उत्पीडन् रोकने के लिए बड़ा फैसला लिया है। इसके तहत संक्रमितों से अधिक वसूली करने वालों अस्पतालों को तीन वर्ष तक के लिए सील कर दिया जाएगा। अगर किसी से भी शिकायत मिली कि किसी प्राइवेट अस्पताल ने निर्धारित दर से अधिक वसूली की तो अस्पतालों का लाइसेंस भी निरस्त होगा।

योगी आदित्यनाथ मंत्रिमंडल बैठक में गरीबों को एक हजार रुपया महीना भत्ता तथा मुफ्त में राशन देने के साथ

ही 18 वर्ष से ऊपर के लोगों को निःशुल्क वैक्सीन लगवाने पर मुहर लगी। इसके साथ ही संक्रमण बढने के दौरान कम्युनिटी किचन का संचालन भी होगा और संक्रमित परिवारों का ध्यान रखते हुए 20 मई से माध्यमिक व उच्च शिक्षा विभाग में ऑनलाइन शिक्षण पर भी विचार किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में 30 अप्रैल से कोरोना कर्फ्यू लागू किया गया है। इसके बाद इसे तीन मई तक लागू रहना था। इसको बढ़ाकर 6 मई और विस्तार देते हुए 10 मई तक कर दिया गया था। इस दौरान अच्छे परिणाम मिलने पर बढ़ाकर 17 और फिर 24 मई तक किया गया है।

कोरोना वायरस संक्रमण पर प्रभावी नियंत्रण करने के लिए प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू को आगे बढ़ाने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक में निर्णय लिया गया। इसी बैठक में कोरोना कर्फ्यू को 17 मई से आगे बढ़ाने पर मुहर लगी। अधिकांश मंत्रियों की राय कोरोना कर्फ्यू को 24 मई सुबह सात बजे तक आगे बढ़ाने की थी।

बैठक में प्रदेश में कोरोना वायरस प्रबंधन पर योजना बनाने के साथ ही कोरोना कर्फ्यू को एक हफ्ते तक आगे बढ़ाने को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंत्रियों से राय ली। इस बैठक के बाद आने वाले निर्णय पर सर्वसम्मति से फैसला लिया गया। माना जा रहा था प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू को 24 मई सुबह सात बजे तक बढ़ाया जाएगा। अभी कोरोना कर्फ्यू 17 मई की सुबह 7ः00 बजे तक है।

सीएम योगी आदित्यनाथ रविवार को मेरठ, गाजियाबाद और गौतमबुद्धनगर में कोरोना वायरस के प्रभाव की समीक्षा करने के साथ ही इंटीग्रेटेड कोविड कमांड कंट्रोल रूम का निरीक्षण करेंगे। मेरठ में बीते चार दिन से कोरोना वायरस संक्रमण से तेजी पकड़ी है। इसके साथ ही गाजियाबाद और गौतमबुद्धनगर में कोरोना वायरस संक्रमण से मौत के मामले काफी बढ़ रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ दिन में 12 बजे लखनऊ से चलकर दो बजे के करीब मेरठ पहुंचेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ वहां पर कोरोना वायरस संक्रमण पर प्रभावी नियंत्रण के लिए तैयारियों व व्यवस्था का निरीक्षण करने के बाद अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे।

बिहार में बढ़े ब्लैक फंगस के मरीज, नौ नए मामलों के साथ 25 तक पहुंचा आंकड़ा

पटना । कोरोनावायरस संक्रमण से उबरे मरीजों को इन दिनों ब्लैक फंगस से भी जूझना पड़ रहा है। बिहार की बात करें तो पोस्ट कोविड मरीजों में अब तक ब्लैक फंगस के 25 मामले मिल चुके हैं। बीते 24 घंटे के दौरान ही राज्य के विभिन्न भागों के रहने वाले नौ नए मरीज मिले हैं। ब्लैक फंगस के सर्वाधिक सात मरीज पटना के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में इलाज करा रहे हैं। खतरनाक बात यह है कि मई के अंत तक ब्लैक फंगस के 1000 से 1500 तक मामले समाने आ सकते हैं।

ब्लैक फंगस संक्रमण के लक्षण, एक नजर

ब्लैक फंगस से संक्रमित मरीजों के नाक, चेहरे, दांत, आंख और सिर में दर्द रहता है। उनके नाक से पानी और खून निकल सकता है। नाक में काली पपड़ी भी जम सकती है। आंखें लाल हो सकतीं हैं, उनमें सूजन हो सकती है। कई मामलों में आंखें बाहर निकल आती हैं तथा रोशनी भी जा सकती है। प्रारम्भिक अवस्था में पहचान हो जाने पर यह संक्रमण दवा के कुछ डोज से ही ठीक हो जाता है। देर होने पर सर्जरी की जरूरत पड़ती है।

बिहार में 24 घंटे के दौरान मिले नौ मरीज

बीते 24 घंटे के दौरान मिले ब्लैक फंगस के मरीजों में तीन पटना एम्स में, तीन पटना के

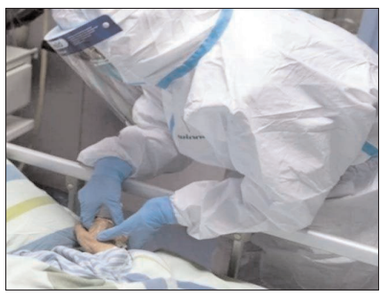

बोरिंग रोड स्थित वेल्होर ईएनटी सेंटर में, दो पटना के पारस अस्पताल में तथा एक कैमूर जिले के कुदरा स्थित रीना देवी मेमोरियल कोविड डेडिकेटेड अस्पताल में भर्ती हैं। पटना एम्स में इलाज करा रहे तीन मरीजों में एक मुजफ्फरपुर का तथा दो पटना के हैं। पटना के वेल्होर ईएनटी सेंटर में भर्ती मरीज पटना, बक्सर और औरंगाबाद के हैं। पटना के पारस अस्पताल में भर्ती किए गए दोनों मरीज पटना के हैं। वेल्होर ईएनटी सेंटर में ब्लैक फंगस के तीनों मरीजों का ऑपरेशन किया जा चुका है।

अब तक मिले 25 मरीज, पटना एम्स में सात- अभी तक पटना में मिले मरीजों की बात करें तो पटना एम्स में सात मरीज भर्ती हैं। पटना के इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान में दो, रूबन मेमोरियल अस्पताल में दो और पारस अस्पताल में चार मरीज मिल चुके हैं। पटना एम्स में भर्ती एक मरीज की आंख की रोशनी चली गई है तो दूसरा बेहोशी की स्थिति में है। एक के ब्रेन में भी संक्रमण है। पूरे राज्य में अभी तक ब्लैक फंगस के 25 मामले सामने आ चुके हैं।

प्रतिरोधी क्षमता के कमजोर होने पर संक्रमण- पटना एम्स के कोरोना नोडल पदाधिकारी डॉ. संजीव कुमार बताते हैं कि ब्लैक फंगस का संक्रमण शरीर की रोग प्रतिरोधी क्षमता के कमजोर होने पर लगता है। यह फंगस नाक, गला, चेहरा, आंख और दिमाग को संक्रमित करता है। इसका एक कारण बिना डॉक्टरी सलाह लिए अपने मन से स्टेरॉयड दवा लेना भी है। कोरोनावायरस संक्रमण के इलाज में शरीर काफी कमजोर हो जाता है।

साथ ही स्टेरॉयड दवा भी दी जाती है। इस कारण ऐसे मरीजों में ब्लैक फंगस के संक्रमण का खतरा रहता है। डॉ. संजीव कहते हैं कि कोरोनावायरस संक्रमण के इलाज में स्टेरॉयड कारगर है, लेकिन इसका उपयोग केवल डॉक्टर की सलाह पर करना चाहिए। खासकर कैंसर, डायबिटीज व किडनी के रोग या किसी अन्य लंबी बीमारी से ग्रसित मरीजों को स्टेरॉयड दवा देने में बहुत सावधानी की जरूरत होती है।

चिकित्साकर्मी एक कोविड -19 रोगी को प्रयागराज के स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल के लेवल -3 वार्ड में स्थानांतरित करते हुए।

पंजाब में मालेरकोटला को जिला बनाने पर सीएम योगी का कांग्रेस पर हमला

लखनऊ । पंजाब की कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार के ईद पर राज्य के मालेरकोटला को 23वां जिला घोषित करने पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यह कांग्रेस की बंटवारे की नीति है। पंजाब में मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र मलेरकोटला को कल ही कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार ने जिला घोषित किया है।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पंजाब सरकार के इस फैसले की न सिर्फ तीखी आलोचना की है, बल्कि इस काम को भारत के संविधान के विपरीत भी बताया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने पंजाब की कांग्रेस सरकार के इस फैसले के खिलाफ एक ट्वीट भी किया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मत और मजहब के आधार पर किसी प्रकार का विभेद भारत के संविधान की मूल भावना के विपरीत है। इस समय, मालेरकोटला (पंजाब) का गठन किया जाना कांग्रेस की विभाजनकारी नीति का परिचायक है।

पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर ने मुस्लिम बाहुल्य मलेरकोटला को जिला बनाया तो उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने उनको तगड़ी नसीहत दी है। योगी आदित्यनाथ ने उनपर हमला बोला है।ईद के अवसर पर शुक्रवार को पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने घोषणा की थी कि मालेरकोटला राज्य का नया जिला होगा। अभी तक संगरूर जिले में मालेरकोटला मुस्लिम बहुल कस्बा था। मालेरकोटला के साथ लगे अमरगढ़ व अहमदगढ़ भी पंजाब के इस 23वें जिले का हिस्सा बनाया गया है।

पंजाब में विधानसभा चुनाव के समय जिला संगरूर जिला मुख्यालय से 35 किलोमीटर दूर मालेरकोटला को जिले का दर्जा देना कांग्रेस का चुनावी वादा था। ईद के मौके पर लोगों को बधाई देने के लिए राज्य स्तर पर ऑनलाइन तरीके से आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने मालेरकोटला के लिए 500 करोड़ रुपये की लागत से मेडिकल कॉलेज, एक महिला कॉलेज, एक नया बस स्टैंड और एक महिला पुलिस थाना बनाने की भी घोषणा की। नये जिले की घोषणा करते हुए, मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं जानता हूं कि यह लंबे समय से लंबित मांग रही है।

उन्होंने कहा कि देश की आजादी के वक्त पंजाब में 13 जिले थे। वर्ष 1947 में बंटवारे के दौरान मालेरकोटला में काफी हद तक शांति रही, जबकि भारत-पाकिस्तान सीमा पर सांप्रदायिक संघर्ष और बड़े पैमाने पर पलायन हुआ। उन्होंने कहा कि नए जिले में डिप्टी कमिश्नर की जल्द नियुक्ति की जाएगी। मालेरकोटला के लिए विभिन्न विकास प्रोजेक्टों का ऐलान करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा स्थानीय लड़के और लड़कियों को डॉक्टरी शिक्षा के योग्य बनाने के लिए नवाब शेर मोहम्मद खान के नाम पर 500 करोड़ रुपए की लागत से यहां पर सरकारी मेडिकल कॉलेज जल्द स्थापित होगा।

सांसद आजम खां को लेकर अफवाह फैलाने के मामले में एक और तहरीर, पुलिस ने शुरू की जांच

मुरादाबाद । सांसद आजम खां को लेकर अफवाह फैलाने के मामले में एक और समर्थक ने तहरीर दी है। यह तहरीर गंज कोतवाली में दी गई है। सांसद इन दिनों बेटे अब्दुल्ला के साथ लखनऊ के मेदांता अस्पताल में भर्ती हैं। सीतापुर जेल में दोनों कोरोना संक्रमित हो गए थे। उनके स्वास्थ्य को लेकर अस्पताल प्रशासन की ओर से रोजाना बुलेटिन जारी किया जा रहा है। बावजूद इसके कुछ लोग उनकी सेहत को लेकर इंटरनेट मीडिया पर झूठी अफवाह फैला रहे हैं।

बुधवार को सपा जिलाध्यक्ष अखिलेश कुमार समेत तीन सपाइयों ने अलग-अलग थानों में तहरीर दी थी। गुरुवार को पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष मशकूर अहमद मुन्ना के बेटे ने शहजादनगर थाने में तहरीर दी थी, जिसमें कहा था कि इन अफवाहों से उनके पिता की तबीयत खराब हो गई। उन्हें मुरादाबाद के अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। शुक्रवार को सांसद के एक और समर्थक अधिवक्ता विक्की राज ने गंज कोतवाली पहुंचकर तहरीर दी, जिसमें उन्होंने फेसबुक एकाउंट से अफवाह फैलाने का आरोप लगाते हुए रिपोर्ट दर्ज कराने की मांग की है। पुलिस अधीक्षक शगुन गौतम ने बताया कि अब तक मिली सभी तहरीर पर जांच की जा रही है। दूसरी ओर आजम खां की पत्नी शहर विधायक डा. तजीन फात्मा ने कहा कि सांसद की हालत अब पहले से ठीक है। दुआओं की जरूरत है। उन्होंने कहा कि जब उनके पति और बेटा ठीक होकर वापस आ जाएंगे, कोरोना बीमारी खत्म हो जाएगी, तभी खुशी के साथ ईद मनाई जाएगी।

गांवों का हाल सुधारेंगे नोडल अधिकारी, सीनियर आइएएस अफसरों को जिम्मेदारी

लखनऊ । वैश्विक महामारी कोरोना वायरस संक्रमण का प्रसार गांवों की ओर अधिक होता देख सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी दांव बदल दिया है। अब उनका फोकस गांवों में तेजी से बढ़ रहे कोरोना वायरस के संक्रमण पर अंकुश लगाने का है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसके लिए सीनियर आइएएस अफसरों को जिलों का नोडल अधिकारी बनाया है। प्रदेश में 59 अफसरों को 75 जिलों का नोडल अधिकारी के रूप में तैनात किया गया है।

सीएम योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को टीम-9 के साथ अपने सरकारी आवास पर कोरोना वायरस संक्रमण पर समीक्षा बैठक के दौरान सभी को अब गांवों पर अधिक फोकस करने का निर्देश दिया। इसी क्रम में 75 जिलों में 59 अफसरों को नोडल अफसर बनाया गया है। अपर मुख्य सचिव के साथ ही प्रमुख सचिव और सचिव स्तर के अधिकारी गांवों में बढ़ रहे कोरोना वायरस संक्रमण पर अंकुश लगाने के प्रयास में जिला प्रशासन के कार्य पर नजर रखेंगे। नोडल अधिकारी रोज जिलाधिकारी तथा सेक्टर प्रभारी के रूप में तैनात जिला प्रशासन के अधिकारी से रोज रिपोर्ट लेंगे। योगी आदित्यनाथ सरकार ने शनिवार को 59 अफसरों को नोडल अफसर के रूप में तैनात किया है। यह सभी जिलों में एक सप्ताह तक प्रवास करेंगे। यह लोग कोरोना संक्रमण की रोकथाम के उपाय सुझाने के साथ सीएचसी व पीएचसी में ऑक्सिजन बेड की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के जिला प्रशासन के कार्यों का निरीक्षण करेंगे। एक सप्ताह के निरीक्षण के बाद आकर यह सभी शासन को अपनी रिपोर्ट देंगे। शासन ने टी वेंकटेश को अयोध्या,राजन शुक्ला को महराजगंज, डिम्पल वर्मा को हरदोई, हेमंत राव को इटावा व औरैय्या, बीएल मीना को मूजफ्फरनगर व शामली, प्रभात सरंगी को एटा व हाथरस, सुरेश चंद्रा को बरेली, सुधीर गर्ग को प्रतापगढ़, भुवनेश कुमार को जौनपुर तथा बी हेकाली झिमोमी को देवरिया का नोडल अफसर बनाया गया है।

कोविड प्रबंधन में निगरानी समितियों की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए अब हर जनपद में सचिव अथवा उससे उच्च स्तर के एक अधिकारी को नामित किया गया है। इनके साथ ही न्याय पंचायत स्तर पर जिला स्तरीय अधिकारियों को सेक्टर प्रभारी के रूप में तैनात किया जाएगा। राज्य सरकार शहर में नए केस कम संख्या में मिलने के बाद भी कोई जोखिम उठाना नहीं चाहती है।

प्रयागराज के तेज बहादुर सप्रू जिला अस्पताल में कोविड-19 वैक्सीन की एक खुराक लेने के लिए कतार में खड़े लोग।

तेजस्वी यादव पर 5100 रुपए इनाम! बिहार में राम विलास के भाई पशुपति पारस के लापता होने के लगे पोस्टर

राघोपुर (वैशाली) । बिहार के वैशाली जिले के अंतर्गत राघोपुर से विधायक और विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव पर 5100 रुपए का इनाम रखा गया है। जी हां, कोरोना महामारी के दौर में अपने क्षेत्र में नहीं दिख रहे विधायक को ढूंढने के लिए लोगों ने ऐसा पोस्टर वायरल किया है। राघोपुर प्रखंड की कई पंचायतों में ऐसा पोस्टर लगाया गया है। साथ ही इसे इंटरनेट मीडिया पर भी वायरल किया जा रहा है। ऐसे ही पोस्टर में पूर्व केंद्रीय मंत्री दिवंगत राम विलास पासवान के भाई और हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र के सांसद पशुपतिनाथ पारस को भी लापता बताया गया है।

पोस्टर में दावा- चुनाव जीतने के बाद गायब हुए दोनों नेता

कोरोना महामारी से पीड़ित लोग अपने जनप्रतिनिधि को खोज रहे हैं। इंटरनेट मीडिया पर भी दोनों जनप्रतिनिधि के लापता होने की सूचना वायरल हो रही है। पोस्टर में सांसद एवं विधायक को खोज कर लाने वाले को 51 सौ रुपये के इनाम की घोषणा की गई है। पोस्टर में लिखा गया है कि चुनाव जीतने के बाद सांसद एवं विधायक क्षेत्र से गायब हैं। कोरोना महामारी में राघोपुर प्रखंड के लोग त्रस्त हैं। कई लोगों की जान भी जा चुकी है। आरोप है कि सांसद एवं विधायक लोगों का हालचाल तक पूछने नहीं आ रहे हैं।

सत्ता पक्ष के लोग भी तेजस्वी पर उठाते रहे हैं सवाल- बिहार सरकार में शामिल दलों के नेता भी तेजस्वी यादव पर लगातार ऐसे सवाल उठाते रहे हैं। भाजपा के राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी, जदयू के प्रवक्ता संजय सिंह और अभिषेक झा लगातार कहते रहे हैं कि आपदा के वक्त तेजस्वी बिहार में दिखाई नहीं पड़ते। पिछले साल भी कोरोना की लहर के वक्त ऐसा आरोप लगा था। उससे पहले यानी कि 2019 में पटना में आई भीषण बाढ़ के वक्त भी राजद नेता पर ऐसा आरोप लग चुका है।

कोझीकोड में पुथियाप्पा मछली पकड़ने के बंदरगाह पर चक्रवात तौकते की चेतावनी के बीच मछली पकड़ने वाली नौकाएं लंगर डालते हुए।

पीपीई किट में स्वास्थ्यकर्मी जम्मू में एक मुर्दाघर के पास कचरा डंप करते हुए।

कन्याकुमारी जिले के नागरकोइल में तमिलनाडु सरकार द्वारा कोरोना राहत कोष की पहली किस्त प्राप्त करने के बाद मुस्कुराती एक बूढ़ी औरत।

एक नजर

गुजरात में कोरोना से होने वाली मौत के आंकड़े नहीं छिपा रही सरकार, गृह राज्य मंत्री प्रदीप सिंह जाडेजा ने किया ये दावा

अहमदाबाद । गुजरात सरकार का दावा है कि वह राज्य में कोरोना से होने वाली मौत के आंकड़े नहीं छिपा रही है। मृत्यु, मृत्यु प्रमाण पत्र तथा प्रमाण पत्र जारी होने के आंकड़ों को एक साथ जोड़कर नहीं देखना चाहिए कई बार परिवार मौत के लंबे समय बाद इस प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करता है। गृह राज्य मंत्री प्रदीप सिंह जाडेजा ने गुजराती अखबार में कोरोना से होने वाली मौत के आंकड़ों के संदर्भ में छपी खबर को बेबुनियाद बताते हुए कहा कि मौत, मृत्यु प्रमाण पत्र तथा प्रमाण पत्र जारी करने के आंकड़ों को जोड़कर एक तय अवधि में उन्हें मौत बताना उचित नहीं है। कोरोना महामारी के दौरान शोक में डूबे किसी भी परिवार को तकलीफ ना हो इसलिए सरकार ने ऑनलाइन प्रमाण पत्र देने की व्यवस्था की है। अलग-अलग कारण व उपयोग के लिए कई बार परिवार एक से अधिक बार भी मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर देते हैं। जाडेजा का दावा है कि मार्च अप्रैल 2020 में महानगर पालिका की ओर से 61505 से अधिक मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किए गए जबकि कोरोना से हुई मौत के संदर्भ में खबर छापने वाले अखबार में उस दौरान करीब 44943 हजार लोगों की ही मौत बताई। जडेजा का कहना है कि लोगों में भय फैलाने तथा सनसनी के लिए इस तरीके की खबर छापी गई है। राज्य सरकार को रोना से हुई मौत के किसी भी तरह के आंकड़े छिपाना नहीं चाहती है। जाडेजा ने कहां की परिवार की मुखिया की मौत हो जाने पर परिवार को बैंक इंश्योरेंस तथा अन्य कई सरकारी एवं संस्थागत औपचारिकताएं पूरी करने के लिए मृत्यु प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। शोक से पीड़ित परिवार कई बार मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए तुरंत आवेदन नहीं कर के लंबे समय बाद आवेदन करता है इसलिए उसकी मौत को मृत्यु प्रमाण पत्र की तारीख के साथ जोड़कर नहीं देखा जा सकता।

गौरतलब है कि स्थानीय गुजराती समाचार पत्र ने राज्य में करीब सवा लाख लोगों की कोरोना से मौत होने का दावा किया था, इससे पहले गुजरात कांग्रेस के अध्यक्ष अमित चावड़ा ने भी महामारी से गुजरात में करीब डेढ़ लाख लोगों के मारे जाने की बात कही थी। लेकिन है कि गुजरात में कोरोना से अब तक करीब 9000 लोगों की मौत हो चुकी है। विरोधी दल कांग्रेस राज्य में महामारी से डेढ़ लाख लोगों की मौत का आरोप लगा रहा है तो स्थानीय समाचार पत्र मौत का आंकड़ा सवा लाख बता रहा है।

राजस्थान के अस्पताल में ऑक्सीजन का प्रेशर गिरने से 3 कोरोना पीड़ितों की मौत

जयपुर । कोरोना संक्रमण के मामले में राजस्थान का देश में चौथा नंबर है। ऑक्सीजन, रेमडिसिवियर इंजेक्शन और अन्य आवश्यक दवाओं के नहीं मिलने के कारण पीड़ितों को मुश्किल हो रही है। सबसे ज्यादा मुश्किल ऑक्सीजन के कारण हो रही है। जयपुर स्थित प्रदेश के सबसे बड़े कोविड अस्पताल आरयूएचएस ऑक्सीजन की सप्लाई बाधित होने से 3 मरीजों की मौत हो गई। तीनों कोरोना संक्रमित थे। वे यहां पिछले चार से पांच दिन से भर्ती थे। अस्पताल प्रशासन का कहना है कि ऑक्सीजन का प्रेशर गिरने से सप्लाई बाधित हुई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस मामले में रिपोर्ट मांगी है। चिकित्सा मंत्री डॉ.रघु शर्मा का कहना है कि ऑक्सीजन की सप्लाई बाधित कैसे हुई और मरीजों की मौत का क्या कारण था, इसकी जांच करवाई जा रही है, जिम्मेदारी तय होगी। जानकारी के अनुसार शुक्रवार को ऑक्सीजन की सप्लाई करीब 2 मिनट के लिए बाधित होने से वार्ड में भर्ती 30 मरीजों को सांस लेने में परेशानी होने लगी, उनकी बेचैनी बढ़ गई। वार्ड में ड्यूटी पर तैनात नर्सिंगकर्मियों ने देखा तो ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो रही थी। ऐसे में वे ऑक्सीजन सप्लाई व्यवस्थित करने के लिए दौड़े, इसी बीच तीन मरीजों की मौत हो गई। कुछ देर बाद सप्लाई व्यवस्थित हुई तो शेष मरीजों को राहत मिली। हालांकि अस्पताल के कोविड प्रभारी डॉ.अजीत सिंह का कहना है कि मौतों का कारण ऑक्सीजन का प्रेशर नहीं है, जांच के बाद ही सच्चाई पता चल सकेगी।

वहीं निचले स्तर के मेडिकलकर्मियों व भर्ती मरीजों के परिजनों ने प्रेशर कम होने के कारण ऑक्सीजन की सप्लाई बाधित होने की बात कही है। अस्पताल प्रशासन व चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधिकारी इस मामले को दबाने में जुटे रहे। आक्रोशित परिजनों ने हंगामा शुरू किया तो पुलिसकर्मी मौके पर पहुंच गए। अधिकारियों ने तीनों मृतकों आत्मप्रकाश, कमल और सजना मीणा के शवों का कोविड गाइडलाइन के अनुसार अंतिम संस्कार करा दिया। परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर इसके लिए उन पर दबाव बनाने का आरोप लगाया है। पूरे प्रकरण का खुलासा हुआ तो शनिवार को सरकार में उच्च स्तर पर जांच शुरू हुई।

उल्लेखनीय है कि इससे पहले कोटा में ऑक्सीजन की कमी से कोटा में 5 मरीजों की मौत हुई थी । झालावाड़ में भी इसी तरह का मामला सामने आया था । प्रदेश के अन्य जिलों में भी ऑक्सीजन की कमी के कारण मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

बंगाल में कोविशील्ड की दो खुराकों के बीच 12-16 हफ्तों का अंतराल लागू

कोलकाता । बंगाल में कोविड टीकाकरण केंद्रों (सीवीसी) ने कोविशील्ड टीके की पहली और दूसरी खुराक लेने के बीच कम से कम 12 हफ्तों या 84 दिनों का अंतराल रखना शनिवार से शुरू कर दिया है, जिससे बड़ी संख्या में लोगों को वापस लौटना पड़ा। इससे पहले कोविशील्ड टीके की दोनों खुराक लेने के बीच छह से आठ हफ्तों का अंतराल था।वरिष्ठ नागरिक समेत बड़ी संख्या में लोग दूसरा टीका लगाने के लिए दूर-दूर से कोविड टीकाकरण केंद्र आए थे लेकिन उन्हें वापस लौटना पड़ा। अपने पति के साथ टीका लेने के लिए कोलकाता के एक केंद्र पर आई अधेड़ उम्र की एक महिला ने कहा, ''हम नैहाटी से आए हैं। हमें पता नहीं था कि टीके लगाने के बीच अंतर बढ़ा दिया है और हमें यहां आने के बाद पता चला कि दूसरा टीका 84 दिनों के बाद लगाया जाएगा।'' महानगर में 42 दिन बाद दूसरा टीका लगवाने के लिए टीकाकरण केंद्रों में कई लोग कतारों में लगे रहे लेकिन उन्हें बैरंग वापस लौटना पड़ा। बंगाल सरकार ने शुक्रवार को एक आदेश में कहा था कि कोविशील्ड टीके की दूसरी खुराक 12-16 हफ्तों के अंतराल के बाद दी जाएगी, जो कि पहले छह से आठ हफ्तों के अंतराल पर दी जा रही थी।

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के छोटे भाई असीम बनर्जी का कोरोना से निधन

कोलकाता । कोरोना का कोहराम थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस बीच बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी के छोटे भाई असीम बनर्जी का कोरोना के चलते निधन हो गया है। शनिवार सुबह कोलकाता के एक निजी अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली।वे कोरोना वायरस से संक्रमित थे और पिछले कई दिनों से इस महामारी से जंग लड़ रहे थे।

कोलकाता के मेडिका सुपरस्पेशिलिटी अस्पताल के चेयरमैन डॉ. आलोक रॉय ने इस बात की जानकारी दी।

राजस्थान के नेता प्रतिपक्ष कटारिया बोले, मुख्यमंत्री रोजाना प्रधानमंत्री को कोसना बंद करें और जनता हित पर ध्यान दें

उदयपुर । राजस्थान के नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने कहा कि महामारी के दौर में राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रोजाना सुबह उठने के बाद प्रधानमंत्री को कोसने लगते हैं। इसकी बजाय वह कोरोना महामारी से जनता को बचाने के लिए जनहित में ध्यान दें तो बेहतर होगा। कटारिया शनिवार को चुनिंदा पत्रकारों से ऑनलाइन वार्ता कर रहे थे।

कटारिया ने कहा कि भाजपा ने तय किया था कि कोरोना महामारी के दौरान हमने राज्य सरकार को आश्वासन दिया था कि हम सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग करेंगे। किन्तु दुर्भाग्य है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री रोज सवेरे उठकर केंद्र सरकार पर आरोप लगा रही है। उनसे मेरी प्रार्थना है कि वह कोविड महामारी से बचाव से जनता को बचाने में अपना ध्यान लगाएं। उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा के उस बयान की निंदा करते हुए कहा, जिसमें उन्होंने कहा कि राज्य का लॉयन ऑर्डर बिगड़ा तो इसकी जिम्मेदारी केन्द्र सरकार की होगी।

कटारिया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रत्येक राज्य के मुख्यमंत्रियों से बात की थी। जिसमें उन्होंने कहा था कि 45 वर्ष और इससे अधिक उम्र के लोगों को कोरोना से बचाव की वैक्सीन का खर्चा केंद्र सरकार उठाएगी। तब मुख्यमंत्री ने वादा किया था कि अठारह से 44 वर्ष तक के लोगों को लगाए जाने वाली वैक्सीन का खर्चा राज्य सरकार वहन करेगी। केंद्र से मिली एक करोड़ 70 लाख वैक्सीन को सबसे पहले लगाकर राज्य सरकार ने वाहवाही लूटी लेकिन अठारह से 44 वर्ष तक के लोगों को वैक्सीन लगाने में फिसड्डी साबित हो रही है। अब केंद्र से इसका खर्चा उठाने के लिए रोज केंद्र पर वादाखिलाफी का आरोप लगाते हैं, जो आपत्तिजनक है।

राज्य को 270 की जगह 453 मैट्रिक टन आक्सीजन मिल रही

कटारिया ने कहा कि राज्य में ऑक्सीजन की कमी को लेकर रोजाना केंद्र के खिलाफ कांग्रेस नेताओं की बयानवाजी जारी है। जब महाराष्ट्र में फरवरी में स्थिति बिगड़ी तो राज्य सरकार उंघ रही थी। ऑक्सीजन की कमी पर केंद्र पर निशाना साधने लगी। दस मई से केंद्र सरकार 270 की जगह 453 मैट्रिक टन ऑक्सीजन की सप्लाई कर रही है। हवाई मार्ग तथा रेल मार्ग से लगातार ऑक्सीजन आ रही है।

कालाबाजारी पर अंकुश लगाने में फैल राज्य सरकार – कटारिया ने कहा कि कोरोना से बचाव में उपयोग लिए जा रहे रेमडेसिविर इंजेक्शन तथा अन्य दवाइयों की कालाबाजारी प्रदेश में जमकर हुई और हो रही है। इस पर अंकुश लगाने में राज्य सरकार पूरी तरह विफल रही है। देश में जहां पहले तीस लाख रेमडेसिविर इंजेक्शन बनते थे और अब इनकी संख्या केंद्र के सहयोग के बाद एक करोड तीन लाख पहुंच गई। राज्य सरकार ने जो कदम अब उठाए हैं, वह पहले उठाती तो इंजेक्शन तथा दवाइयों की मारामारी नहीं होती। अब जो कदम उठाए गए हैं, उससे कालाबाजारी रूकी है। हालांकि अभी भी यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि मरीज के नाम से जो इंजेक्शन खरीदे जा रहे हैं, वह उन्हें लगाए जा रहे हैं या दूसरों से पैसे लेकर लगाए जा रहे हैं।

गांवों में वैक्सीनेशन बढ़ाए जाने की जरूरत – कटारिया ने कहा कि शहरों में वैक्सीनेशन की जितनी रफ्तार है उसका दस फीसदी गांवों में नहीं। जबकि जरूरत गांवों में वैक्सीनेशन बढ़ाए जाने की है। उन्होंने कहा कि गांवों में एक ही मकान में समूचा परिवार रहता है। उनके पास क्वारेटाइन होने के लिए जगह नहीं। उन्होंने राज्य सरकार को सुझाव देते हुए कहा कि गांवों के सामुदायिक केंद्रों को क्वारेनटाइन भवन बना दिया जाना चाहिए। वहां वैक्सीनेशन बढ़ानी होगी। उनके लिए ऑफलाइन की व्यवस्था करनी चाहिए। चिरंजीवी योजना से लोगों का उपचार कई निजी अस्पतालों में नहीं हो रहा, इसको लेकर राज्य सरकार को बताया गया है।

पीएम केयर फंड के वेंटीलेटर उपयोग में नहीं लिए तो खराब कैसे – नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि पीएम केयर फंड से जो वेंटीलेटर खरीदे गए, उन्हें अभी तक इस्तेमाल नहीं किया गया है तो वह खराब कैसे बता दिए गए। देश में पैंतालीस हजार वैंटीलेटर दिए गए हैं, लेकिन शिकायत केवल राजस्थान से की जा रही है। उदयपुर के अस्पताल को 95 वेंटीलेटर मिले, जिनमें से 71 अभी भी पैक हैं। उन्होंने कहा कि कुछ वेटींलेटर्स खराब भी हो गए तो उनकी मरम्मत करानी चाहिए। केवल चिट्ठी लिखने से वह उपयोगी नहीं बन जाते।

अहमदाबाद में महिला को पति का कोरोना संक्रमण छिपाना महंगा पड़ा, डेढ़ लाख वसूलने वाले डाक्टर की खुली पोल

अहमदाबाद । नकली दवा और नकली इंजेक्शन के बाद अब महानगर वासियों को नकली डॉक्टर का भी सामना करना पड़ रहा है। पूर्वी अहमदाबाद में रहने वाली 35 साल की एक महिला को पति का कोरोना संक्रमण छिपाना बहुत महंगा पड़ गया। फर्जी डॉक्टर ने डेढ़ लाख रुपए भी वसूल लिए और इलाज भी नहीं कर सका। महिला के रिश्तेदारों ने जब चिकित्सक से पूछताछ की तो पता चला कि वह एक कंपाउन्डर है तथा एक नर्स एक अन्य युवक के साथ मिलकर अहमदाबाद के पूर्वी इलाके में क्लीनिक खोलकर कोरोना संक्रमितों का उपचार करने लगाहै।

अहमदाबाद के अमराईवाडी पुलिस ने इस फर्जी डॉक्टर, एक नर्स व उनके एक सहयोगी को गिरफ्तार कर लिया। खोखरा इलाके में रहने वाली एक महिला ने पुलिस को बताया कि अप्रैल 27 को उसके 45 वर्षीय पति कोरोना से संक्रमित हो गए थे उन्होंने एचआर सीटी स्कैन कराया जिससे कोरोना की पुष्टि हो गयी। महिला अपने पति के संक्रमण की बात छिपाना चाहती थी इसलिए उसने पड़ोसी से उसके एक परिचित डॉक्टर का नंबर मांगा जिसने उनकी मां का घर आकर इलाज किया था। पड़ोसी ने नरेंद्र पंड्या नामक व्यक्ति का नंबर देते हुए बताया कि वह डॉक्टर है, महिला ने फोन कर उसे घर बुलाया तो वह कोरोना का उपचार करने के लिए तैयार हो गया लेकिन प्रति विजिट उसने दस हजार रुपए की मांग रखी जिसे इस महिला ने स्वीकार कर लिया है। इस पैकेज में रोज सुबह नर्स घर पर आकर देखभाल करने के साथ दवा भी देती थी। करीब दस दिन के उपचार के बाद ही जब पति की तबीयत में सुधार नहीं हुआ तो महिला ने अपने रिश्तेदारों को बताया और वह उसके घर आकर जब डॉक्टर से पूछताछ करने लगे तो उसने बताया कि वह एक कंपाउंडर है तथा एक नर्स के साथ मिलकर क्लीनिक चला रहा है। फर्जी डॉक्टर अब तक इस महिला से इलाज के नाम पर डेढ़ लाख रुपए ठग चुका है।

महिला ने पति को 108 एंबुलेंस में ले जाकर उपचार के लिए सिविल अस्पताल में भर्ती कराया तथा फर्जी डॉक्टर उसकी एक सहयोगी नर्स तथा एक अन्य व्यक्ति के खिलाफ अमराईवाड़ी पुलिस थाना में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने फर्जी डॉक्टर, नर्स व उनके एक सहयोगी को गिरफ्तार कर लिया है। मामले की जांच कर रही है पुलिस को पता चला है कि यह दोनों किसी प्राइवेट अस्पताल में काम करते हैं। इनके तीसरे साथी का किसी भी मेडिकल फील्ड से कोई ताल्लुक नहीं है। पुलिस इस मामले के साथ यह भी जांच कर रही है कि अब तक इस फर्जी डॉक्टर और कितने कोरोना संक्रमितों का उपचार किया है तथा उनमें से कितनों की मौत हो चुकी है।

कोरोना संक्रमण से रिकवर होने के बाद ब्लैक फंगस के प्रकोप ने बढ़ाई गहलोत सरकार की चिंता

जयपुर । राजस्थान में कोरोना संक्रमण से रिकवर होने के बाद मधुमेह से ग्रसित लोगों में होने वाली बीमारी ब्लैक फंगस का प्रकोप नजर आने लगा है। ब्लैक फंगस के सबसे ज्यादा मरीज जयपुर और जोधपुर में मिले हैं। ब्लैक फंगस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए राज्य सरकार ने इसके इलाज में काम आने वाली दवाओं की खरीद और इलाज को लेकर योजना बनाई है ।

चिकित्सा मंत्री डॉ.रघु शर्मा ने बताया कि ब्लैक फंगस बीमारी के काम आने वाली दवा लाइपोजोमल एम्फोटेरिसिन बी की आपूर्ति के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेजों से जुड़े अस्पतालों के चिकित्सकों से इस बीमारी पर विशेष निगरानी रखने के लिए कहा गया है। जिला अस्पतालों में भी चिकित्सकों को ब्लैक फंगस से गंभीर नुकसान नहीं हो इसके लिए कहा गया है । इस बीमारी में नाक और कान को नुकसान होता है । सही समय पर इलाज नहीं होने पर आंखों की रोशनी तक जा सकती है।

सरकार ने कोरोना से रिकवर होने वाले मरीजों को अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए जगह-जगह समझाने का अभियान चलाने का भी निर्णय लिया गया है । उधर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने ट्वीट कर कहा,राजस्थान में ब्लैक फंगस नहीं बीमारी हो रही है। इसके इलाज के लिए लाइपोजोमल एम्फोटेरिसिन इंजेक्शन और टेबलेट की जरूरत है । सरकार जल्द से जल्द ये दवा उपलब्ध कराए ताकि लोगों को इन्हे काले बाजार में अत्यधिक कीमतों पर नहीं खरीदना पड़े।

सरकार खरीदेगी वैक्सीन

18 से 44 साल तक की उम्र के लोगों के वैक्सीनेशन के लिए अशोक गहलोत सरकार ने ग्लोबल टेंडर के जरिए कंपनियों से एक करोड़ डोज की सप्लाई मांगी है । इसके लिए सरकार ने शनिवार को शॉर्ट टर्म टेंडर निकाला है । इसमें 20 मई तक कंपनियों को अपनी-अपनी बिड़ ईमेल के जरिए भेजने के लिए कहा है । नेशनल हेल्थ मिशन के निदेशक सुधीर कुमार शर्मा ने बताया कि जो कंपनी जल्द से जल्द वैक्सीन उपलब्ध कराएगी उससे खरीदने की योजना है ।

प्रवीण तोगड़िया के भाई सहित तीन लोगों पर बिल्डर को आत्महत्या के लिए मजबूर करने का आरोप

अहमदाबाद । अंतरराष्ट्रीय हिंदू परिषद के अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया के छोटे भाई सहित तीन जनों पर एक बिल्डर को आत्महत्या के लिए मजबूर करने का आरोप लगा है। आत्महत्या करने वाले अहमदाबाद मधु भाई डोबरिया ने अपने सुसाइड नोट में लिखा है कि गांधीनगर में 50 करोड़ रुपए के जमीन के सौदे में उसके हिस्से की मुनाफे की रकम नहीं दी गई। इस चिट्ठी में मधु भाई ने अंतरराष्ट्रीय हिंदू परिषद के संस्थापक अध्यक्ष एवं फायर ब्रांड हिंदू नेता प्रवीण तोगड़िया के छोटे भाई विनोद उर्फ अन्नू तोगड़िया तथा उसके दो साथी प्रवासी गुजराती प्रभूदास पटेल एवं राकेश गोहिल को भी सह आरोपी बताया है।

अहमदाबाद के निकोल निवासी बिल्डर मधुभाई डोबरिया ने पिछली 7 मई को अपने फार्म हाउस पर जहर पीकर आत्महत्या कर ली थी। उसके पुत्र चेतन डोबरिया ने बताया कि गांधीनगर की एक जमीन के सोदे में अपनी हिस्सेदारी नहीं मिलने से उनके पिता काफी चिंतित थे इसके अलावा विनोद उर्फ अन्नू तोगड़िया, राकेश गोहिल तथा प्रभु दास उसे तरह-तरह से परेशान करते थे। चेतन ने बताया कि पैसे देने के बहाने तोगड़िया उसके पिता को नरोड़ा के हंस पुरा मैं एक बिल्डर की ऑफिस में बुलाकर उसके पिता को जान से मारने की धमकी दी।

ओढव में इंडस्ट्रियल एस्टेट के अपने ऑफिस में विनोद उर्फ अन्नू तोगड़िया ने मधुभाई को बुलाया तथा चुप रहने को कहा ऐसा नहीं करने पर उसको जान से मारने की धमकी दी। मृतक मधुभाई के पुत्र चेतन की शिकायत पर पुलिस ने जांच की तथा उसके हाथ मधुभाई का एक सुसाइड नोट लगा जिसमें विनोद उर्फ अनु तोगड़िया पता उसके दो साथियों से परेशान होकर आत्महत्या करने की बात मधुभाई तोगड़िया ने लिखते हुए कहां है कि मुनाफे की रकम नहीं देने तथा बार बार मिल रही धमकियों के कारण वह आत्महत्या कर रहा है। पुलिस ने विनोद उर्फ अनु तथा उसके दो अन्य साथियों के खिलाफ आत्महत्या के लिए प्रेरित करने का मामला दर्ज कर उनकी पूछताछ के लिए तलाश शुरू कर दी है।

पुलिस बेड़े की मुस्तैदी परखने सादा कपड़ों में साइकिल पर निकले जोधपुर पुलिस कमिश्नर

जोधपुर । ईद के मौके पर जोधपुर शहर में कानून व्यवस्था के साथ ही कोरोना गाइड लाइन की पालना कराने को तैनात पुलिसकर्मी किस तरह काम कर रहे है, इसका जायजा लेने के लिए शुक्रवार को पुलिस कमिश्नर जोस मोहन सादा कपड़ों में साइकिल पर सवार होकर शहर की सड़कों पर निकल पड़े। कई थाना क्षेत्रों से होते हुए वे जालोरी गेट ईदगाह पहुंचे। ईदगाह से अपनी साइकिल यात्रा को आगे बढ़ाते हुए जोस मोहन भीतरी शहर में पहुंच गए। साइकिल भीतरी शहर में घूमते हुए घंटाघर से सोजती गेट होते हुए वापस अपने घर पहुंचे।

ईदगाह के बाहर तैनात पुलिसकर्मियों ने उन्हें रोक कर पूछताछ भी की, लेकिन वे जोधपुर कमिश्नर को नही पहचान पाए। जोस मोहन ने अपने स्तर पर शहर की व्यवस्था को परखने का फैसला किया। बिना किसी को बताए, और पूर्व सूचना के जोस मोहन साइकल पर सवार

होकर शहर के कई हिस्सों में पहुचें। ईद के अवसर पर बे बड़ी ईदगाह गए। जहाँ तैनात जवानों ने उनको जाने से रोक दिया। जिसके बाद उन्होंने पुलिस की सजक होने पर उनकी प्रशंसा भी की।

पुलिस कमिश्नर ने बताया कि ईद की व्यवस्था और कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए पूरा जायजा लिया गया। ताकि असलियत में पुलिस किस तरह से ड्यूटी कर रही हैं। उस व्यवस्था जांचने के लिए साइकिल से निकला था। कुछ जगह कमियां पाई गई उसको सुधारने की कोशिश करेंगे। वहीं कुछ स्थान पर पुलिस के जवान पूरी निष्ठा के साथ अपनी ड्यूटी निभाते नजर आए।

ईदगाह से अपनी साइकिल यात्रा को आगे बढ़ाते हुए जोस मोहन भीतरी शहर में पहुंच गए। साइकिल भीतरी शहर में घूमते हुए घंटाघर से सोजती गेट होते हुए वापस अपने घर पहुंचे। कुछ थाना क्षेत्रों में उन्होंने चुपचाप पुलिस नाकों पर तैनात पुलिसकर्मियों की कार्यशैली को परखा। उन्होंने पुलिस उपायुक्त पश्चिम आलोक श्रीवास्तव, एडीसीपी हरफूल सिंह व पुलिस निरीक्षक हनुमान सिंह से भी ईदगाह परिसर में मुलाकात की। जोधपुर में बड़ी ईदगाह पर ईद के अवसर पर सामूहिक नमाज अता होती है, लेकिन कोविड नियमो के तहत इस बार भी गत वर्ष की भांति इस पर मनाही थी, इस कारण वहां सिर्फ 9 जनों ने ही नमाज अता की।

गांवों में संक्रमण फैलने से रोकने के लिए जांच तेज, कोविड किट का घर-घर वितरण

जयपुर । राजस्थान में कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। संक्रमण अब शहरों से गांवों में पहुंच गया। ग्रामीण क्षेत्रों में सही तरह से उपचार नहीं मिलने और लोगों में जागरूकता नहीं होने के कारण रिकवरी रेट के मामले में राजस्थान देश में 31वें स्थान पर है। ग्रामीण क्षेत्रों में फैलते संक्रमण पर लगाम लगाने के लिहाज से अशोक गहलोत सरकार ने घर-घर कोविड किट पहुंचाने और जांच का काम तेज करने का निर्णय लिया है। ग्रामीण क्षेत्रों में कोविड केयर सेंटर्स बनाए जाएंगे। पीड़ितों को इन सेंटर्स में पहुंचाया जाएगा।

कोविड किट में कोरोना महामारी में काम आने वाली एजिथ्रोमाइसिन, पेरासिटामोल, लिवोसिटिरिजिन, जिंक सल्फेट और विटामिन सी की गोलियां शामिल है। इसके साथ ही घर-घर सर्वे किया जाएगा। सर्वे के लिए स्वास्थ्यकर्मी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और पंचायतकर्मी घर-घर जाएंगे। ये सभी कार्मिक कोविड किट वितरित करने, सर्वे का काम तेज करने साथ ही ग्रामीणों को महामारी के गंभीर परिणामों के बारे में बताएंगे। ग्रामीणों को समझाया जाएगा कि पीड़ित को घर से बाहर 14 दिन के लिए क्वारेंटीन किया जाए,जिससे अन्य लोगों को इस बारे में बचाया जा सके । किट वितरण एवं घर-घर सर्वे का काम शनिवार से शुरू हुआ है।

सर्वे के दौरान जिन लोगों में संक्रमण होने की जानकारी सामने आएगी उन्हे तत्काल कोविड केयर सेंटर्स में भेजा जाएगा। चिकित्सा सचिव सिद्धार्थ महाजन का मानना है कि संक्रमण की दूसरी लहर में गांव ज्यादा प्रभावित हुए हैं। इसका मुख्य कारण ग्रामीणों का बेपरवाह होना है। पिछले दो सप्ताह में अधिकांश नए संक्रमित ग्रामीण इलाकों में ही मिले हैं।

समाज को शर्मसार करने वाली घटना, महिला को पति के इलाज के लिए एंबुलेंस के किराए के तौर पर देने पड़े गहने

कोलकाता । कोरोना संक्रमित पति को अस्पताल में भर्ती कराने के लिए जगह-जगह भटक रही एक महिला को लाचार होकर 33 हजार रुपये में एंबुलेंस को किराए पर लेना पड़ा, जिसके लिए उन्हें अपने गहने देने पड़े।समाज को शर्मसार करने वाली यह घटना हुगली जिले के कोन्नगर इलाके में सामने आई है। वहां की रहने वाली तनुश्री मजुमदार ने तीन दिन पहले कोरोना से संक्रमित अपने पति को हिंदमोटर के एक नर्सिंग होम में भर्ती कराया था। पति की हालत काफी खराब होने पर नर्सिंग होम वालों ने तनुश्री को अपने पति को कोलकाता के किसी अस्पताल में भर्ती करवाने की सलाह दी थी। कोलकाता ले जाने के लिए तनुश्री ने एक एंबुलेंस किराए पर लिया था। तकरीबन छह घंटे कोलकाता के विभिन्न अस्पतालों में घूमने के बाद उनके पति को कोई अस्पताल में जगह नही मिल पाई। इसके बाद वे उसी एंबुलेंस से उत्तरपाड़ा पहुंची। छह घंटे के एंबुलेंस के किराये के तौर पर चालक 33 हजार रुपये मांगे। चालक के जबरदस्ती करने पर तनुश्री को अपनी सोने की चेन उसे किराए की रकम के तौर पर देनी पड़ी। उसके बाद चालक ने उसके पति को एंबुलेंस से उतारा। तनुश्री ने इस घटना की शिकायत थाने में की है। लोगों का कहना है जहां एक र कोरोना मरीजों के परिवारवालों को इलाज के लिए दर-दर की ठोकरें खानी पड़ रही है, वही दवाई, ऑक्सीजन तथा एंबुलेंस के नाम कुछ लोग असहाय जनों से जबरन रुपये वसूल रहे हैं।

ऐसे दोस्त बनाइए जो आपको खींचकर सफलता की ओर ले जाए : स्नेहलता वसईकर

सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन का शो पुण्यश्लोक अहिल्याबाई कई कारणों से दर्शकों का पसंदीदा बना हुआ है। इस शो में भारतीय इतिहास की सबसे कुशल महिला शासकों में से एक, रानी अहिल्याबाई होल्कर की प्रेरणादायक जीवन यात्रा दिखाई गई है, जिन्होंने अपने ससुर मल्हार राव होल्कर की मदद से समाज के रूढ़िवादी विचारों को चुनौती दी थी और इतिहास का रुख बदला था। इस समय शो में अहिल्या और रेणु की दोस्ती दिखाई जा रही है। रेणु एक विधवा है और इसलिए उसे समाज में नीची नजरों से देखा जाता है। हालांकि अहिल्या रेणु को उस तरह से नहीं देखती। वो रेणु का बचाव करती है, उसका ख्याल रखती है और उसे बहुत चाहती है। इस शो में गौतमाबाई का रोल निभा रहीं एक्ट्रेस स्नेहलता वसईकर इस शो में अहिल्या की सास बनी हैं।

स्नेहलता को गर्व है कि इस शो में दर्शकों के लिए बहुत-से मूल्यवान संदेश है और इसमें कई सामाजिक मुद्दों को उठाया गया है। इस बारे में बताते हुए स्नेहलता वसईकर कहती हैं, अपनी दोस्ती में बैलेंस बनाना और एक दूसरे से सीखना जरूरी है। सबसे अच्छे दोस्त वो नहीं होते, जो यह जानते हुए भी आपकी हां में हां मिलाते हैं कि आप अपना बेस्ट नहीं दे रहे हैं। उन्होंने कहा, सबसे अच्छे दोस्त तो वो होते हैं, जो जानते हैं कि आप और अच्छा कर सकते हैं, इसलिए आपको अपना बेहतर करने के लिए बाध्य करते हैं। अपने दोस्तों को यह बताना हिम्मत की बात है कि उनमें बहुत कुछ हासिल करने की क्षमता है। मुझे यह कहते हुए खुशी हो रही है कि हमारे शो के जरिए दर्शकों को इतने खूबसूरत रिश्ते देखने को मिल रहे हैं।

अपनी गलती मानना आपका सबसे अनमोल गुण होता है : परम सिंह

सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन का ताजातरीन शो 'इश्क पर ज़ोर नहीं' एक नए जमाने का लव ड्रामा है, जिसने दर्शकों को अपने आकर्षण में बांध लिया है। यह अहान और इश्की की कहानी है, जो प्यार और शादी को लेकर अलग-अलग सोच रखतेहैं। हालांकि उनके इस सफर में बहुत-से रोमांचक मोड़, ढेर सारे आश्चर्य, हंसी-मजाक और हल्की-फुल्की नोकझोंक शामिल है। पॉपुलर एक्टर परम सिंह इस शो में अहान मल्होत्रा का लीड रोल निभा रहे हैं। जहां परम का किरदार अहान पुराने विचारों में यकीन रखता है, वहीं अपने जीवनसाथी को लेकर भी उसकी एक विशेष राय है। वो घरेलू और पारिवारिक जीवनसाथी चाहता है, लेकिन साथ ही वो बहुत उदार और समझदार भी है। वो अपनी गलतियां स्वीकार करने और माफी मांगने में कभी नहीं झिझकता। परम सिंह मानते हैं कि अपनी गलतियों का एहसास करना बड़ा विनम्र और अनमोल गुण होता है। इस बारे में बताते हुए एक्टर परम सिंह ने कहा, अपनी गलतियां स्वीकार करने का ख्याल आपको अक्सर डरा देता है और विचलित कर देता है। लेकिन दूसरी ओर, अपनी गलतियां स्वीकार करना हमें इसका सामना करने के एक कदम करीब ले जाता है। यह हमारी सफलता का पहला कदम भी हो सकता है। उन्होंने कहा, हम दूसरों के नजरिए से चीजों को देख सकते हैं और ज्यादा समझदार और उदार रह सकते हैं। इससे हमें सीखने योग्य चीजें पता चलती हैं और हमें पूरे सम्मान और उद्देश्य के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है।

फिल्मों में आने से पहले इतना था जरीन खान का वजन, बनना चाहती थीं डॉक्टर

बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान के साथ फिल्म फिल्म 'वीर' से डेब्यू करने वाली एक्ट्रेस जरीन खान 14 मई को अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं। कैटरीना कैफ की हमशक्ल कही जाने वाली एक्ट्रेस जरीन खान अभी जितनी फिट एंड फाइन दिखती हैं, उतनी वे करियर शुरू करने से पहले नहीं थीं। अपने कॉलेज के समय में जरीन का वजन 100 किलो था, लेकिन फिल्मों में आने के बाद उन्होंने अपना वजन काफी हदतक कम किया और फिट एंड फाइन एक्ट्रेस की लिस्ट में शामिल हो गईं। उनकी यह जर्नी बेहद मुश्किल रहीं। जरीन ने कभी मॉडलिंग या फिल्मों के बारे में नहीं सोचा था। वे डॉक्टर बनना चाहती थीं, लेकिन परिवार की स्थिति को देख वे डॉक्टर न बन सकीं और कॉल सेंटर में काम करने लगीं। फिल्मों में आने के बाद एक्ट्रेस ने खूब पसीना बहाया और खुद का वजन कम किया। एक इंटरव्यू के दौरान जरीन ने कहा था, मैंने अपना वजन फिल्मों के लिए नहीं, बल्कि मीडिया के लिए घटाया है, क्योंकि आप सभी मुझे बहुत क्रिटिसाइज करते थे। खबरों के मुताबिक एक्ट्रेस ने अपनी डेब्यू फिल्म वीर के लिए 30 किलो वजन कम किया था, क्योंकि इस फिल्म में उन्होंने सलमान के अपोजिट एक राजकुमारी का किरदार निभाया था, लेकिन इतना काफी नहीं था। एक्ट्रेस ने स्लिम और ट्रिम दिखने के लिए योग, कार्डियो बूटकैंप और स्पेशल वेट लॉस ट्रेनिंग भी ली थी। सलमान और जरीन की मुलाकात फिल्म युवराज के सेट पर हुई थी, जहां सलमान को उनमें एक राजकुमारी दिखाई दी। इसके बाद ही सलमान ने उन्हें अपनी फिल्म वीर के लिए कास्ट कर लिया। यहीं से जरीन की किस्मत बदलती चली गई, जिसके बाद से एक्ट्रेस कई बेहतरीन फिल्मों में नजर आईं। जरीन खान ने रेडी, हॉउसफुल 2, हेट स्टोरी 3, वजह तुम हो, अक्सर 2 आदि फिल्मों में काम किया हैं। बता दें कि जरीन को पिछली बार साल 2020 में रिलीज हुई फिल्म 'हम भी अकेले तुम भी अकेले' में देखा गया था।

प्रियंका चोपड़ा और निक जोनास ने मिल कर भारत की मदद के लिए जुटायी 7 करोड़ से भी ज्यादा की धन राशि

कई अन्य हस्तियों की तरह प्रियंका चोपड़ा और उनके पति निक जोनास भारत की कोविड -19 के खिलाफ लड़ाई लड़ने में मदद करने के लिए आगे आए। प्रियंका और निक ने देश में कोविड -19 से प्रभावित लोगों के लिए धन जुटाने में मदद करने के लिए गेटइंडिया के साथ मिलकर एक फंडरेसर शुरू किया। अभी तक वे सफलतापूर्वक मिलियन डॉलर (7,36,28,200 रुपये) जुटाने में सफल रहे हैं। इस राशि को प्राप्त करने के बाद प्रियंका और निक ने भारत की मदद के लिए अगला लक्ष्य 3 मिलियन डॉलर (22,08,80,100 रुपये) का रखा है। 14,000 से अधिक दानदाताओं ने प्रियंका चोपड़ा और निक जोनास के फंडराइज़र में योगदान दिया है। दान दिये गये पैसे को ऑक्सीजन सांद्रता और वैक्सीन बनाने की दिया जा रहा है ताकि कोरोना वायरस से लोगों को बचाया जा सके। भारत के लिए 1 मिलियन डॉलर जुटाने की जानकारी प्रियंका चोपड़ा ने अपने सोशल मीडिया पर दी। लोगों के योगदान के लिए सभी को धन्यवाद देते हुए, प्रियंका ने लिखा, 'हमारे इतिहास के कुछ सबसे काले दिनों के बीच में, मानवता ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि हम एक साथ बेहतर हैं। निक और मैं आपके समर्थन से और दुनिया के इतने सारे हिस्सों से भारत के लिए मदद की गुहार द्वारा बहुत विनम्र हैं। 14,000 से अधिक अच्छे सामरी लोगों ने अपने दिल खोल दिए और हमें इन कोशिशों में 1 मिलियन डॉलर जुटाने में मदद की। अनगिनत लोगों ने इस प्रक्रिया को तेज करने के लिए दुनिया में इस फैलाने में हमारी मदद की। प्राप्त किए गए सभी पैसे पहले से ही ऑक्सीजन Concentrators, वैक्सीन समर्थन और इतने अधिक के रूप में देश भर में तैनात किए जा रहे हैं। हम सब यहां ये मदद जारी रखने में मदद कर सकते हैं। हम मदद के लिए न के लक्ष्य को 3 मिलियन तक बढ़ा रहे हैं और हम जानते हैं कि आपकी सहायता से हम इसे भी प्राप्त कर सकते हैं। आप सभी के समर्थन

संजय लीला भंसाली की रोमांटिक फिल्म में दिखेंगे शाहरुख खान

बॉलिवुड के किंग खान शाहरुख खान आने वाले साल में इंट्रेस्टिंग फिल्मों में नजर आने वाले हैं। ऐसे में उनका शेड्यूल काफी बिजी है। वह आखिरी बार 2018 में अनुष्का शर्मा और कटरीना कैफ के साथ 'जीरो' में दिखे थे। लेटेस्ट रिपोर्ट्स की मानें तो शाहरुख अब फिल्ममेकर संजय लीला भंसाली की अगली फिल्म का हिस्सा हो सकते हैं।

पिछले साल शाहरुख खान ने अपकमिंग फिल्म 'पठान' पर काम शुरू किया था। इस फिल्म में दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहम भी नजर आएंगे जिस पर काम चल रहा है। इस बीच खबर है कि संजय लीला भंसाली की 'इजहार' नाम की फिल्म में शाहरुख खान को लेकर बातचीत चल रही है।

भारतीय आदमी और नॉर्वे की लड़की का प्यार

मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो भंसाली 4 साल पहले शाहरुख को लेकर 'इजहार' बनाना चाहते थे। फिल्म का प्लॉट एक भारतीय आदमी के इर्द-गिर्द है जो नॉर्वे की लड़की के प्यार की खातिर नॉर्वे तक का रास्ता तय करता है। यह रियल लाइफ स्टोरी पर बेस्ड है।

शाहरुख खान देंगे हरी झंडी?

रिपोर्ट में सूत्र ने बताया कि संजय लीला भंसाली उस कहानी को स्क्रीनप्ले में अडैप्ट करना चाहते थे और अब वह फिर से शाहरुख के लिए स्क्रिप्ट पर काम कर रहे हैं। अब यह देखना होगा कि या शाहरुख इस पर हरी झंडी देते हैं।

इन ह्श्रॉजेट्स में दिखेंगे शाहरुख

प्रफेशनल फ्रंट की बात करें तो शाहरुख अब डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद की 'पठान' के अलावा साउथ के फिल्ममेकर ऐटली की एक फिल्म में नजर आ सकते हैं। इसके अलावा वह राजकुमार हिरानी की सोशल कॉमिडी में दिखेंगे। यही नहीं, वह अयान मुखर्जी की मच अवेटेड फिल्म 'ब्रह्मास्त्र' में कैमियो में नजर आएंगे।

भारतीय महिला टीम का हुआ ऐलान, शेफाली वर्मा पहली बार वनडे टीम में शामिल

नई दिल्ली । युवा भारतीय महिला बल्लेबाज शेफाली वर्मा को पहली बार भारतीय महिला वनडे टीम में जगह मिली है। आगामी इंग्लैंड दौरे के लिए उन्हें सभी प्रारूपों (टेस्ट, वनडे, टी-20) में टीम में शामिल किया गया है। वहीं अनुभवी ऑलराउंडर शिखा पांडे और विकेटकीपर बल्लेबाज तानिया भाटिया की भी टीम में वापसी हुई है। दोनों हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ घरेलू वनडे और टी-20 सीरीज से टीम से बाहर थी। राष्ट्रीय चयनकर्ताओं ने इंग्लैंड दौरे के लिए दो टीमों की घोषणा की है। इकलौते टेस्ट और तीन मैचों की वनडे सीरीज के लिए मिताली राज के नेतृत्व में 18 सदस्यीय टीम बनाई गई है और टी-20 के लिए अलग 17 सदस्यीय टीम घोषित की गई है, जिसकी कमान हरमनप्रीत कौर को दी गई है। शेफाली के अलावा अनकैप्ड विकेटकीपर इंद्राणी रॉय ने भी दोनों टीमों में जगह बनाई है, जबकि कोरोना से न उबर पाने के कारण लेग स्पिनर राजेश्वरी गायकवाड़ को ड्राप आउट (छोड़) किया गया है। उल्लेखनीय है कि भारतीय महिला टीम 16 जून को ब्रिस्टल में टेस्ट मैच के साथ अपना अभियान शुरू करेगी। इसके बाद वह तीन वनडे और तीन टी-20 खेलेगी। इस दौरे पर रमेश पोवार दो साल बाद भारतीय महिला टीम के मुख्य कोच के रूप में वापसी करेंगे।

विश्व कप क्वालीफायर्स के लिए 19 मई को कतर रवाना होगी भारतीय फुटबॉल टीम

नई दिल्ली ।

भारतीय फुटबॉल टीम 19 मई को कतर के लिए रवाना होगी क्योंकि इस देश ने भारतीय टीम को राहत देते हुए अगले महीने होने वाले 2022 विश्व कप क्वालीफायर से पहले खिलाडियों की वहां ट्रेनिंग का अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ (एआईएफएफ) का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है। इतना ही नहीं कतर ने भारतीय दल के वहां पहुंचने के लिए 10 दिन के अनिवार्य पृथकवास से छूट देने का एआईएफएफ का आग्रह भी मान लिया है। भारतीय टीम तीन जून को पहले मुकाबले पूर्व जैविक रूप से सुरक्षित माहौल में लगभग दो हफ्ते के तैयारी शिविर में हिस्सा लेगी। एआईएफएफ के महासचिव कुशाल दास ने कहा- हम 19 मई की शाम को टीम को भेजने की योजना बना रहे हैं। पृथकवास से नहीं गुजरना होगा और वे जैविक रूप से सुरक्षित माहौल में रहेंगे। दास ने कहा कि खिलाड़ी नयी दिल्ली में जुटेंगे और कतर के लिए रवाना होने से पहले उनका कोविड-19 परीक्षण होगा। भारत पहले ही 2022 फीफा विश्व कप में जगह बनाने की दौड़ से बाहर हो चुका है लेकिन इन संयुक्त क्वालीफायर में अब भी 2023 एशियाई कप में जगह बनाने की दौड़ में है। एशियाई कप क्वालीफिकेशन में भारत को अभी कतर (तीन जून), बांग्लादेश (सात जून) और अफगानिस्तान (15 जून) के खिलाफ तीन मुकाबले खेलने हैं।एशियाई फुटबॉल परिसंघ (एएफसी) ने कोरोना वायरस महामारी के कारण यात्रा और पृथकवास पाबंदियों को देखते हुए मार्च में कतर को ग्रुप ई के बाकी बचे मैचों के आयोजक के रूप में चुना था। दास ने बुधवार को कहा था कि राष्ट्रीय टीम देश में कोविड-19 संक्रमण के बढ़ते मामलों के कारण यहां ट्रेनिंग नहीं कर सकती और वे विश्व कप क्वालीफाइंग मुकाबलों से पहले विदेश में शिविर के विकल्पों पर विचार कर रहे हैं। भारतीय टीम

अभी पांच मैचों में तीन अंक के साथ ग्रुप तालिका में चौथे स्थान पर चल रही है।भारतीय टीम बाकी बचे मैचों से अधिकतम अंक जुटाना चाहेगी जिससे कि शीर्ष तीन में जगह बनाकर 2023 एशियाई कप क्वालीफाइंग तीसरे दौर के लिए स्वतः क्वालीफाई कर सके। मार्च में भारत ने दुबई में ओमान और यूएई के खिलाफ मैत्री मैच के रूप में नवंबर 2019 के बाद अपना पहला अंतरराष्ट्रीय मैच खेला था। भारत ने ओमान को 25 मार्च को 1-1 से बराबरी पर रोका था लेकिन यूएई के खिलाफ 29 मार्च को उसे 0-6 से करारी हार का सामना करना पड़ा।

ओलंपिक के आयोजन से दमदार संदेश जाएगा कि हम कोविड से आगे निकल चुके हैं : नरिंदर बत्रा

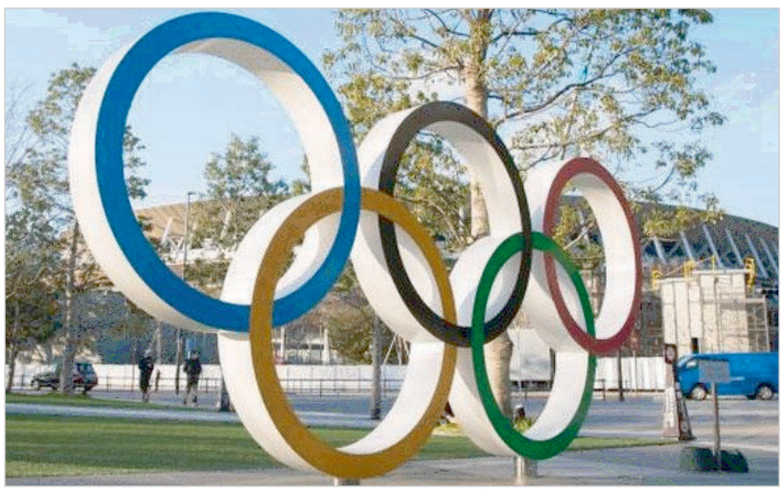

नई दिल्ली ।

भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष नरिंदर बत्रा ने शनिवार को कहा कि कोरोना महामारी के बीच ओलंपिक के आयोजन का विरोध होगा लेकिन तोक्यो में खेलों के आयोजन से मजबूत संदेश जायेगा कि हम इस भयावह हालात से आगे निकल चुके हैं। तोक्यो ओलंपिक पिछले साल कोरोना महामारी के कारण एक साल के लिये स्थगित कर दिये गए थे। आईओए अध्यक्ष और अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सदस्य बत्रा ने उम्मीद जताई कि खेल 23 जुलाई से निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आयोजित होंगे। उन्होंने कहा कि जिंदगी आगे बढ चुकी है और ओलंपिक के आयोजन से सख्त संदेश जायेगा कि हम कोरोना महामारी से आगे निकल चुके हैं। खेलों का विरोध तो होगा ही लेकिन अब जापान की आयोजन समिति और आईओसी को फैसला लेना है। जहां तक भारतीय खिलाड़ियों का सवाल है तो हम सारे जरूरी एहतियात बरत रहे हैं और अपनी ओर से सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन की हरसंभव कोशिश कर रहे हैं। इससे एक दिन पहले ही जापान में ओलंपिक के आयोजन के विरोधियों ने याचिका डालकर खेलों को रद्द करने की मांग की। जापान में कोरोना महामारी की चौथी लहर चल रही है। जापान ने तीन और इलाकों में आपातकाल लागू कर दिया है। बत्रा ने यह भी आश्वासन दिया कि भारत से यात्रा पर लगे प्रतिबंध का ओलंपिक में भारतीय खिलाड़ियों के भाग लेने पर असर नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा कि यह अस्थायी प्रतिबंध है जो कई देशों ने लागू किया है लेकिन ओलंपिक का प्रोटोकॉल अलग होता है जो सदस्य देशों को मानना ही होता है। उन्होंने कहा कि मैं आश्वासन देता हूं कि ओलंपिक के लिये क्वालीफाई कर चुके भारतीय खिलाड़ियों को कोई परेशानी नहीं आयेगी। आयोजन समिति और आईओसी ने इसकी गारंटी दी है। उनके लिये कोई प्रतिबंध नहीं होगा। भारत सारे प्रोटोकॉल का पालन कर रहा है जिसमें ओलंपिक जाने वाले खिलाड़ियों का समय पर टीकाकरण शामिल है। हम टीकाकरण को लेकर आईओसी और आयोजन समिति के सारे प्रोटोकॉल का पालन कर रहे हैं। अपने खिलाड़ियों की सुरक्षित यात्रा को लेकर सरकार से बात कर रहे हैं। हम एक तरफ की चार्टर्ड उड़ान की व्यवस्था की संभावना तलाश रहे हैं ताकि कोई किसी दूसरे के संपर्क में नहीं आए

संक्षिप्त समाचार

इंग्लैंड के हैरी गर्नी गेंदबाज ने क्रिकेट से लिया अचानक संन्यास, ले चुका है 600 से अधिक विकेट

स्पोर्ट्स डेस्क । इंग्लैंड के तेज गेंदबाज हैरी गर्नी ने क्रिकेट से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया है। गर्नी पिछले कई समय से चोट के कारण परेशान थे और टीम से अंदर बाहर होते रहते थे। हैरी गर्नी आईपीएल में कोलकाता नाईट राईडर्स की तरफ से भी खेल चुके हैं। लेकिन कंधे की चोट की वजह से वह अपना करियर आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं और उन्होंने संन्यास लेने का ऐलान कर दिया। उन्होंने अपने संन्यास का ऐलान सोशल मीडिया पर किया। हैरी गर्नी ने संन्यास लेने के बाद कहा कि मुझे क्रिकेट खेलते हुए 24 साल हो गए हैं और मैंने क्रिकेट को काफी समय दिया है। मैंने 10 साल की उम्र में गेंद पकड़ी थी। लेकिन कंधे की चोट के कारण मेरा संन्यास लेना निराशाजनक है। गर्नी का क्रिकेट करियर शानदार रहा है और उन्होंने कई बेमिसाल बॉलिंग स्पैल भी डाले हैं। उन्होंने कहा कि वह अपने क्रिकेट के इन लम्हों को सजोकर रखेंगे। गर्नी आईपीएल में ही नहीं बल्कि दुनिया की कई टी20 लीग में खेल चुके हैं। गर्नी बिग बैश, ब्लास्ट, कैरेबियन प्रीमियर लीग में खेल चुके हैं। गर्नी का करियर और भी अच्छा रहता अगर वह चोट के कारण परेशान ना रहते। गर्नी मेलबर्न रेनेगेड्स, बारबाडोस ट्राईडेंट्स, कोलकाता नाईट राईडर्स और नॉटिंघमशायर जैसी टीमों के लिए खेल चुके हैं। हैरी गर्नी का इंटरनेशनल करियर साल 2014 में शुरु हुआ था। गर्नी ने इंग्लैंड के लिए 10 वनडे और 2 टी20 मैच खेलें हैं। लेकिन चोट के कारण वह टीम में अपनी जगह बना पाने में कामयाब नहीं हो पाए। गर्नी इसके बाद एक टी20 गेंदबाज बन गए। उन्होंने दुनिया भर की टी20 लीग में विकेट चटकाकर अपने नाम 614 विकेट हासिल की।

न्यूजीलैंड के खिलाफ श्रृंखला के बाद ब्रेक लेंगे इंग्लैंड के कोच सिल्वरवुड, बताया यह कारण

लंदन। इंग्लैंड के मुख्य कोच क्रिस सिल्वरवुड न्यूजीलैंड के खिलाफ दो टेस्ट की श्रृंखला के बाद ब्रेक लेंगे और श्रीलंका तथा पाकिस्तान के खिलाफ क्रिकेट श्रृंखला में उनके सहायक जिम्मा संभालेंगे। श्रीलंका और भारत दौरे पर इंग्लैंड टीम के साथ रहे सिल्वरवुड ने कहा कि वह अगस्त में भारत के खिलाफ घरेलू टेस्ट श्रृंखला से पहले तरोताजा रहना चाहते हैं और इसीलिये ब्रेक ले रहे हैं। उनकी गैर मौजूदगी में पॉल कोलिंगवुड और ग्राहम थोर्प जून जुलाई में श्रीलंका और पाकिस्तान के खिलाफ श्रृंखला के लिये कोच का कार्यभार संभालेंगे। सिल्वरवुड ने कहा कि अगर मै शत प्रतिशत क्षमता के साथ काम नहीं कर सकता तो यह खिलाड़ियों और मेरे खुद के लिए ठीक नहीं होगा। थोर्प और कोली एक एक श्रृंखला संभाल लेंगे। मैं तरोताजा होकर अगली श्रृंखला में वापसी करूंगा। न्यूजीलैंड के खिलाफ दो टेस्ट मैचों की घरेलू श्रृंखला के बाद इंग्लैंड टीम श्रीलंका के खिलाफ 23 जून से तीन टी20 और तीन वनडे खेलेगी। इसके बाद पाकिस्तान के खिलाफ 16 जुलाई से तीन वनडे और तीन टी20 खेलने हैं।

तोक्यो ओलंपिक में इतिहास रच सकती है भारतीय महिला हॉकी टीम

नई दिल्ली।

भारत की पूर्व गोलकीपर हेलन मेरी का मानना है कि भारतीय महिला हॉकी टीम अपने खेल के कुछ पहलुओं पर काम करके तोक्यो ओलंपिक में शीर्ष तीन में स्थान हासिल कर सकती है। पिछले तीन से चार साल में भारतीय महिला हॉकी टीम ने शानदार प्रदर्शन किया है। हेलन ने 'हॉकी ते चर्चा' में कहा कि अर्जेंटीना और जर्मनी में प्रदर्शन को देखते हुए मुझे लगता है कि हमारी टीम 90 प्रतिशत तैयार है और आने वाले कुछ समय में अपने खेल को और बेहतर कर सकते है। उन्होंने कहा कि मुझे यकीन है कि वे तोक्यो में इतिहास रच सकते हैं। तोक्यो में तिरंगे का परचम लहराएगा। अर्जेंटीना में जिस तरह से भारतीय टीम खेली, हालांकि दुनिया की दूसरे नंबर की टीम को नहीं हरा सकी लेकिन आत्मविश्वास देखने लायक था । मैने भारतीय टीम को किसी टीम के खिलाफ उसके घरेलू मैदान पर ऐसे खेलते नहीं देखा। भारत के लिए 1992 से एक दशक से अधिक के अपने अंतरराष्ट्रीय कैरियर में 2002 राष्ट्रमंडल खेल और 2004 एशिया कप में स्वर्ण जीतने वाली टीम का हिस्सा रही हेलन ने कहा कि अब काफी व्यवस्थित और वैज्ञानिक तरीके से तैयारी होती है। उन्होंने कहा कि हमारे समय में और आज के समय में काफी फर्क है। अब वैज्ञानिक तरीके से सब कुछ होता है और टीम के पास बड़ा सहयोगी स्टाफ है । फिटनेस, खुराक और कार्यभार सभी पहलुओं का ध्यान रखा जाता है। हर रणनीति पहले से तय होती है।

इटालियन ओपन : राफेल नडाल ने अलेक्जेंडर ज्वेरेव को हराया

रोम ।

रफेल नडाल ने अलेक्जेंडर ज्वेरेव के खिलाफ हार का सिलसिला तोड़ते हुए उसे इटालियन ओपन टेनिस क्वार्टर फाइनल में 6-3, 6-4 से हरा दिया। ज्वेरेव ने एक सप्ताह पहले ही नडाल को मैड्रिड ओपन में सीधे सेटों में हराया था। नडाल ने जीत के बाद कहा- मैं मैड्रिड ओपन की तुलना में बेहतर खेला। हालात भी अलग थे। अब उनका सामना अमेरिका के रीली ओपेलका से होगा जिसने अर्जेंटीना के क्वालीफायर फेडरिको डेलबोनिस को 7-5, 7-6 से हराकर पहली बार मास्टर्स सेमीफाइनल में जगह बनाई। नोवाक जोकोविच और स्टेफानोस सिटसिपास के बीच क्वार्टर फाइनल बारिश के कारण स्थगित करना पड़ा उस समय सिटसिपास 6-4, 2-1 से आगे थे। एक अन्य क्वार्टर फाइनल आंद्रेइ रूबलेव और लोरेंजो सोनेगो के बीच होगा। महिला वर्ग में शीर्ष वरीयता प्राप्त एशले बार्टी को कोको गॉ के खिलाफ मैच में 6-4, 2-1 से आगे रहने के बावजूद दाहिने हाथ में चोट के कारण कोर्ट छोडना पड़ा। गॉ का सामना सेमीफाइनल

में फ्रेंच ओपन चैम्पियन इगा स्वियातेक या दो बार की रोम चैम्पियन एलिना स्वितोलिना से होगा। 2019 की चैम्पियन कैरोलिना प्लिसकोवा ने 2017 फ्रेंच ओपन चैम्पियन येलेना ओस्टापेंको को 4-6, 7-5, 7-6 से हराया। अब उनका सामना पेट्रा मार्टिच से होगा।

बिना गेंदबाजी हार्दिक पंड्या किसी भी प्रारूप में टीम इंडिया में बने रहने के हकदार नहीं : सरनदीप सिंह

नई दिल्ली।

भारत के पूर्व चयनकर्ता सरनदीप सिंह ने टेस्ट टीम से हार्दिक पंड्या को नजरअंदाज करने पर मौजूदा समिति के फैसने का समर्थन करते हुए कहा है कि यह हरफनमौला खिलाड़ी अगर गेंदबाजी में योगदान नहीं देता है, तो वह छोटे प्रारूपों की टीम में भी जगह पाने का हकदार नहीं है। हार्दिक की 2019 में पीठ की सर्जरी हुई थी। इसके बाद से वह नियमित रूप से गेंदबाजी नहीं कर रहे हैं। भारतीय क्रिकेट टीम को उनके ऑलराउंड कौशल का फायदा नहीं मिल रहा है। इसी वजह से उन्हें इंग्लैंड दौरे पर गई भारतीय टेस्ट टीम में जगह नहीं मिली है। सरनदीप का कार्यकाल इस साल ऑस्ट्रेलिया दौरे के साथ समाप्त हो गया है। उन्होंने इंग्लैंड दौरे के लिए प्रतिभाशाली पृथ्वी शॉ को टीम में जगह नहीं मिलने पर हैरानी जताई। भारतीय टीम के पूर्व स्पिनर सरनदीप ने कहा हार्दिक को टेस्ट के लिए नजरअंदाज करने का चयनकर्ताओं का फैसला समझ में आता है। वह सर्जरी के बाद नियमित रूप से गेंदबाजी नहीं कर पाए हैं। मुझे लगता है कि उन्हें छोटे फॉर्मेट में भी प्लेइंग इलेवन का हिस्सा बनने के लिए वनडे में 10 और टी20 में चार ओवर करने होंगे। वह सिर्फ बल्लेबाज के रूप में नहीं खेल सकते। सरनदीप सिंह ने कहा कि अगर हार्दिक पंड्या गेंदबाजी नहीं करते हैं तो इससे टीम इंडिया को नुकसान होगा। उन्होंने कहा, अगर हार्दिक गेंदबाजी नहीं करते हैं, तो यह टीम के संतुलन पर काफी असर डालेगा। आपको उसकी वजह से एक अतिरिक्त गेंदबाज को टीम में रखना होगा जिससे सूर्यकुमार यादव जैसे खिलाड़ी को बाहर करना होगा। हम इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज में इसका असर देख चुके है। उन्होंने कहा कि हम गेंदबाजी में सिर्फ पांच विकल्पों के साथ नहीं उतर सकते। अब टीम के पास वॉशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल, रवींद्र जडेजा के रूप में कई अन्य हरफनमौला खिलाड़ी मौजूद हैं, शारदुल ठाकुर भी एक निर्भरतायोग्य हरफनमौला बन सकते हैं।

आईपीएल से पहले कई खिलाड़ियों ने कर दिया था वैक्सीन लगवाने से इनकार

नई दिल्ली।

कोरोना से कई खिलाड़ियों के संक्रमित होने के बाद आईपीएल 2021 को स्थगित किए दो सप्ताह हो चुके है, लेकिन इसका प्रभाव अब भी खिलाड़ियों पर देखा जा सकता है। सनराइजर्स हैदराबाद के विकेटकीपर बल्लेबाज ऋद्धिमान साहा दोबारा कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जबकि केकेआर के तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा फिलहाल घर पर ही क्वारंटीन है। चेन्नई सुपर किंग्स के बल्लेबाजी कोच माइक हसी और गेंदबाजी कोच एल बैराज एक दिन पहले निगेटिव पाए गए हैं। हसी अब रविवार को ऑस्ट्रेलिया के लिए उड़ान भर सकते हैं। इस बीच कहा जा रहा है कि आईपीएल के दौरान खिलाड़ियों और सहयोगी स्टाफ के बीच कोरोना से बचाव को लेकर जागरूकता की बेहद कमी थी। आईपीएल से पहले कई खिलाड़ियों ने कोरोना वैक्सीन लगवाने से इनकार कर दिया था। आईपीएल फ्रेंचाइजी ने खिलाड़ियों को अनौपचारिक रूप से टीके लगवाने की पेशकश की थी। कुछ फ्रेंचाइजी अपने खिलाड़ियों को टीकाकरण के लिए मनाने में सफल रहीं, हालांकि उनकी संख्या बेहद कम थी। इस तथ्य से सावधान रहते हुए कि टीकाकरण के बाद उन्हें हल्का बुखार हो सकता है, कई खिलाड़ियों ने वैक्सीन लगाने के प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया। खिलाड़ियों ने महसूस किया कि वे जिस बायो बबल में थे, वह इतना सुरक्षित था कि उन्हें टीका लगाने की आवश्यकता नहीं थी। फेंचाइजी ने इसका प्रचार भी नहीं किया। फिर चीजें अचानक नियंत्रण से बाहर हो गईं। विदेशी टीके के प्रति ज्यादा सजग थे, लेकिन उन्हें टीका नहीं लगाया जा सकता था, क्योंकि यह कानूनी नहीं था। सूत्रों ने कहा, कई विदेशी, विशेष रूप से सहायक कर्मचारी, टीकाकरण को लेकर उत्साहित थे, लेकिन उन्हें टीका नहीं लगाया जा सका। टीकाकरण के प्रति अनिच्छा की वजह से खिलाड़ी बेहद खतरनाक स्थिति में पहुंच गए। ऋद्धिमान साहा और प्रसिद्ध कृष्णा अब तक कोरोना नेगेटिव नहीं हुए हैं और यह भारत के लिए चिंता का विषय है। दोनों खिलाड़ियों को 25 मई को मुंबई में

रिपोर्ट करना है।

फिर विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के लिए इंग्लैंड जाने से पहले तीन नकारात्मक परीक्षणों से गुजरना होगा। हालांकि, माइक हसी की नेगेटिव रिपोर्ट राहत देने वाली है। सीएसके प्रबंधन मालदीव में बिना क्वारंटाइन अवधि के हसी की वापसी की तैयारी कर रहा है।

आस्ट्रेलियाई कप्तान टिम पेन का आरोप, भारतीय टीम ध्यान बंटाने में माहिर

मेलबर्न । आस्ट्रेलियाई कप्तान टिम पेन ने कहा कि वह अपने बयान पर कायम हैं कि भारत के 'साइडशो के कारण उनकी टीम का ध्यान बंटा, लेकिन उन्होंने स्पष्ट किया कि वह जनवरी में भारत के हाथों मिली हार का हाना नहीं बना रहे थे। भारतीय टीम के 'साइडशो' वाले बयान पर पेन की काफी आलोचना हुई है। उन्होंने 'गिली एंड गोस पॉडकास्ट में कहा था कि मुझसे कई बातें पूछी गई थी, जिनमें भारत के खिलाफ खेलने की चुनौती संबंधी सवाल शामिल थे। उस पर मैंने कहा कि भारतीय टीम ध्यान बंटाने में माहिर है। उन्होंने कहा,उस समय लगातार बात हो रही थी कि वे ब्रिसबेन में नहीं खेलने वाले हैं, वे बार-बार दस्तानें बदल रहे थे और फिजियो को बुला रहे थे। मैंने बस इतना कहा कि उससे ध्यान बंट गया और कई बार गेंद पर से ध्यान हट गया। पेन ने कहा कि उन्होंने हमें उन्नीस साबित किया और वे जीत के हकदार थे, लेकिन उस बात को काट दिया गया। उनका कहना है कि मैं बहाना बना रहा हूं लेकिन ऐसा नही है। उन्होंने कहा, जब भी कोई आस्ट्रेलियाई कप्तान बोलता है,तब सभी की नजरें उस पर रहती है। इसमें कोई शक नहीं। यह काफी लंबा इंटरव्यू था।

बॉल टेंपरिंग विवाद को लेकर बेनक्रॉफ्ट ने दिया बड़ा बयान

केपटाउन। दक्षिण अफ्रीका के साल 2018 के दौरे पर ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी कैमरून बेनक्रॉफ्ट बॉल टेंपरिंग विवाद में आए थे। केपटाउन के दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ हुए टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलियाई कप्तान स्टीव स्मिथ, सलामी बल्लेबाज डेविड वार्नर भी इसमें शामिल थे। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट बोर्ड ने सख्त फैसला लेकर तीनों खिलाड़ियों पर बैन लगा दिया था। जहां वार्नर और स्मिथ को एक-एक साल के लिए, वहीं बेनक्रॉफ्ट पर 6 महीने के लिए। इस विवाद के बाद ऑस्ट्रेलिया की कप्तानी टिम पेन को दे दी गई। बेनक्रॉफ्ट ने हाल ही में एक बयान में कहा कि मैंने जो गेंद से छेड़छाड़ की थी उसके लिए मैं जिम्मेदार हूं और इसका जवाबदेही भी मैं ही हूं। मैंने जो किया वह गेंदबाजों के फायदे के लिए किया लेकिन टीम के गेंदबाज भी यह जानते थे। उसके बारे में अब मुझे जागरूकता और आत्म मंथन हुआ है। इससे मैंने एक चीज सीखी है कि आपको जिम्मेदार होना पड़ता है। अब मैं पहले से अधिक अच्छे फैसले ले सकता हूं। बेनक्रॉफ्ट ने कहा कि मैंने टीम में वापसी के लिए लक्ष्य और दरवाजों को बंद नहीं किया है। लेकिन साथ ही मैं मानसिक तौर पर तनाव भी महसूस नहीं कर रहा हूं।मुझे यकीन है कि मुझे एक मौका जरूर मिलेगा।